चौथी दुनिया
www.chauthiduniya.com
मूल्य 5 रुपये
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
1986 से प्रकाशित
23 फरवरी–01 मार्च 2015
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

फोटो : प्रभात पाण्डेय

राहुल तक नहीं पहुंच रही है कांग्रेसियों के रोने की आवाज़

सितंबर में सोनिया गांधी पूर्ण रूप से रिटायर होने जा रही हैं. यानी, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने जा रही हैं. ज़ाहिर है, इस पद पर सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी आएंगे. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार सिर्फ हार का सामना करना पड़ रहा है. कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक आलाकमान के रवैये से न सिर्फ हैरान है, बल्कि परेशान भी है. उनकी समस्या ये हैं कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है. अब जब राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वेसर्वा बनने वाले हैं, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी की कार्यशैली कैसी है? वह क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? किसकी सुनते हैं? क्या सुनते हैं और क्या नहीं सुनते हैं? इन सवालों का जवाब जानना न सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के लिए जरूरी है, बल्कि इस देश की जनता के लिए भी उतना ही जरूरी है.

संतोष भारतीय

वर्ष 1984 में भाजपा दो सीटों पर सिमट गई थी और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है. विश्लेषण करें, तो पाते हैं कि तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में निराशा नहीं आई थी. वे लगातार काम करते रहे. अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए चुनावी लड़ाइयां लड़ते रहे. यह अलग बात है कि आज अटल जी बीमार हैं और भाजपा के दूसरे महानायक श्री लालकृष्ण आडवाणी राजनीतिक एकांतवास झेल रहे हैं. कोई भी उन्हें या मुरली मनोहर जोशी को फ्रंटलाइन में नहीं देख पा रहा. आज के दौर के महानायक का चेहरा बदल चुका है. आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के न केवल सर्वमान्य नेता हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिशा निर्देशक भी हैं.

कांग्रेस की हालत इससे बिल्कुल उलट है. कांग्रेस ने आज से दस साल पहले अपने खाते में हार का सिलसिला दर्ज करना शुरू किया. कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार का पहला चुनाव हारी. फिर वह बिहार का दूसरा चुनाव भी हारी. बिहार के चुनाव में हारने के बाद यह आशा थी कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में सीख लेगी और उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू करेगी. पर कांग्रेस ने कोई सीख नहीं ली और उत्तर प्रदेश भी दोनों बार उसके हाथ से जाता रहा. फिर, उसके हाथ से राजस्थान गया. एक तरीके से संपूर्ण उत्तर भारत कांग्रेस के हाथ से निकल गया और अंत में केंद्र भी उसके हाथ से निकल गया. राहुल गांधी साबित ही नहीं कर पाए कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के मुक़ाबले सत्ता में आने का दावा पेश कर रही है. नतीजा यह निकला कि केंद्र के बाद हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र कांग्रेस के हाथ से निकल गया और दिल्ली में कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कांग्रेस को महान शून्य की बढ़त हासिल हुई और उसके खाते में सीटें भी शून्य आईं.

तब यह सवाल पैदा हुआ कि आख़िर कांग्रेस में ऐसी कौन–सी चीज है, जो उसे लोगों की नज़रों से उतार रही है. आज कांग्रेस का मतलब कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, उनके पुत्र एवं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी हैं. अगर इन तीन नामों को हम किनारे कर दें, तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व कहीं नज़र नहीं आता. इसलिए इन तीनों के बारे में देश के लोगों को जानना चाहिए कि इनका मनोविज्ञान क्या है, कार्य करने की इनकी शैली क्या है, विषयों को समझने का इनका तरीका क्या है, ताकि हम यह समझ सकें कि कांग्रेस अगले पांच, दस, पंद्रह सालों में क्या करने की योजना बना रही है.

राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो उलझा हुआ दिखाई देता है. राहुल गांधी को लगता है कि ऐसे लोग, जो सामान्य या गंदे कपड़े पहनते हैं या ऐसे लोग, जो संभ्रांत चीजें नहीं जानते हैं, वही जनता के नज़दीक हैं. और, इस प्रक्रिया में राहुल गांधी के सर्वाधिक नज़दीक पहुंचने वाले लोगों में मधुसूदन मिस्त्री हैं, मीनाक्षी नटराजन हैं, मोहन गोपाल हैं.

अब एक किस्सा आपको बताते हैं. मीनाक्षी नटराजन थ्री व्हीलर से राहुल गांधी से मिलने आती हैं और राहुल गांधी को लगता है कि अरे, मीनाक्षी नटराजन कितनी सीधी हैं, जो थ्री व्हीलर से उनसे मिलने आती हैं. इसलिए वही नेतृत्व कर सकती हैं. एक मीटिंग में कोका कोला का कैन बंटा. मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी से पूछती हैं कि सर, यह कैन कैसे खुलेगा? राहुल जवाब देते हैं, तुम कैन नहीं खोल पाती हो? मीनाक्षी हल्के से मुस्कुरा देती हैं. राहुल कैन खोलकर देते हैं. और, यही मीनाक्षी नटराजन का प्लस प्वाइंट है. जेब में अगर प्लास्टिक का पेन है, तो वह राहुल को पसंद है. और, अब जो लोग राहुल से मिलने आते हैं, वे फटे, मुड़े–तुड़े कपड़े पहन कर, मोंट ब्लैंक पेन छिपाकर, जेब में प्लास्टिक का पेन डालकर, खराब घड़ी पहन कर आते हैं. दरअसल, सबको पता चल गया है कि राहुल को नाटक पसंद है. दूसरे शब्दों में, वे राहुल को बहुत भोला मानते हैं और इसलिए राहुल के आसपास ज़्यादातर वैसे ही लोग हैं, जो इस तरह के नाटक में भरोसा करते हैं.

दूसरी तरफ़ राहुल गांधी अपने लिए दूसरे प्रतिमान रखते हैं. वह स्वयं फाल्कन हवाई जहाज में चलते हैं, जबकि नेहरू जी देश में सद्भावना यात्रा पर ट्रेन से निकलते थे. फाल्कन हवाई जहाज और जेट वह ऐसे लेते हैं, जो छोटे हवाई अड्डों पर उतर नहीं सकते. तो, बड़े हवाई अड्डे पर राहुल गांधी फाल्कन या सहारा के बड़े जेट से उतर कर, हेलिकॉप्टर में बैठकर जहां मीटिंग होती है, वहां जाते हैं. चुनाव के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया, उसमें से राहुल गांधी ने फाल्कन हवाई जहाज के किराये पर ही 400 करोड़ रुपये खर्च कर दिए. राहुल गांधी को छोटे जहाज में चलना

> **राहुल का दिमाग बनाने वाले मोहन गोपाल से पहले यह काम जयराम रमेश करते थे, लेकिन अब वह उस दायरे से बाहर हैं. मोहन गोपाल भी मुड़े-तुड़े कपड़े पहनते हैं. वह पहले एनएसयूआई में थे. वह पहले अमेरिका गए और वहां से देश की राजनीति सीखकर आए हैं. ओबीसी समर्थक हैं और वह राहुल गांधी को विभिन्न विषयों पर नोट्स बनाकर देते रहते हैं. राजू आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और एससी-एसटी हैं. राहुल गांधी के भाषणों में जो एससी-एसटी समर्थक तत्व आता है, उसके पीछे राजू का योगदान है. मधुसूदन मिस्त्री, सीपी जोशी, कुछ रोल मोहन प्रकाश भी कभी निभाते हैं. ये हैं, राहुल गांधी के प्रत्यक्ष तौर पर दिमाग बनाने वाले मित्र.**

पसंद नहीं है. राहुल गांधी पर यह कहावत बहुत सटीक बैठती है और शायद किसी ने लिखा भी है कि सोशलिस्ट बाई डे एंड एलिटिस्ट बाई नाइट. राहुल गांधी शाम के बाद लोगों की पहुंच से बाहर चले जाते हैं. और, यही राहुल गांधी के व्यक्तित्व का पहला कॉन्ट्राडिक्शन है कि वह अपने लिए सादगी नहीं पसंद करते, लेकिन जो सादगी का नाटक करता है, उसे वह सही मानते हैं. राहुल गांधी ने चुनाव में कांग्रेस को जिताने वाली फोर्स, यूथ कांग्रेस और

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कांग्रेस का भविष्य राहुल या प्रियंका पेज-03

अति आत्मविश्वास ने भाजपा को हरा दिया पेज-04

सोनभद्र : अपराधियों को पुलिस का खुला संरक्षण पेज-06

साई की महिमा पेज-12

राहुल तक नहीं पहुंच रही है

कांग्रेसियों के रोने की आवाज़

पृष्ठ एक का शेष

एनएसयूआई के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर दिए और नतीजे के तौर पर कांग्रेस को हर जगह गिनती गिनने लायक ही सीटें मिलीं.

राहुल गांधी के व्यक्तित्व का एक और उदाहरण अमीना शेख वाला विज्ञापन है, जिसके ऊपर राहुल गांधी ने 300 करोड़ रुपये खर्च किए. इसमें अमीना शेख कहती हैं कि वह यूथ कांग्रेस की सदस्य हैं और वह राहुल गांधी को वोट देंगी. इस विज्ञापन का कोई असर नहीं हुआ. लोगों का कहना था कि अमीना शेख अगर यूथ कांग्रेस की सदस्य हैं, तो वह राहुल गांधी को नहीं, तो क्या नरेंद्र मोदी को वोट देंगी? इसकी जगह यह होता कि मैं गोवा विश्वविद्यालय की छात्रा हूं और मैं राहुल गांधी को वोट दूंगी. पर राहुल गांधी की टीम में किसी ने इस विज्ञापन के ज़रिये होने वाले नुक़सान को देखा ही नहीं. नतीजे के तौर पर वह 300 करोड़ का विज्ञापन बर्बाद हो गया. कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इसी तरह बिना दिमाग के विज्ञापनों ने पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी हार दिलाई. राहुल का मनोविज्ञान भी मजेदार है. राहुल हार्डवर्कर माने जाते हैं और उन्होंने पिछले दस सालों में बहुत पढ़ा-लिखा भी है. वह हर विषय पर बात कर सकते हैं. वह अपने सलाहकारों की टीम के साथ अपनी एक राय बनाते हैं और तब उन्हें जो प्रभावित करने की कोशिश करता है, उसे वह पसंद नहीं करते. उदाहरण के तौर पर आनंद शर्मा जैसे लोग, जो हाथ हिलाते हुए हाई फाई भाषा में राहुल से बात करते हैं, तो राहुल को यह पसंद नहीं आता. यह भी सही है कि वह जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं. उनके अपने तर्क हैं और इसकी शुरुआत उनके पढ़ाई के दिनों से हुई. उन्हें बचपन से ही दिल्ली से बाहर रखा गया. वह अमेरिका में रहे. कमल डांडोना के साथ उन्हें रहना पड़ा. कमाल डांडोना राजीव गांधी के दोस्त और बड़े बिजनेसमैन थे, जहां से राहुल में एक अलग तरह का आत्मविश्वास आया और जिसे आप नकचढ़ा आत्मविश्वास कह सकते हैं. एक तत्व विकसित हुआ, जिसमें उन्हें अपने अलावा सब ग़लत लगते हैं.

पिता की हत्या के बाद राहुल गांधी देश में वापस आए और मां की इच्छानुसार धीर-धीरे देश की राजनीति में खपे भी, लेकिन यह देश उन्हें बहुत पसंद नहीं आया. उन्हें जब भी वक्त मिलता, वह अपने दोस्तों से मिलने बाहर चले जाते. अभी भी लगभग ऐसा ही है. राहुल के बहुत से कार्यक्रम उनकी विदेश यात्रा को देखकर बनते हैं और इस विदेश यात्रा या कहें कि अपने दोस्तों से मिलने के मोह ने उनमें एक और आदत विकसित कर दी कि वह किसी भी चीज पर कॉन्सन्ट्रेट नहीं करते. दस दिनों तक एक और दस दिनों के बाद दूसरा विषय. और इसी सारी प्रक्रिया के दौरान, चूंकि आप देश में नहीं रहते हैं, तो आपको वे लोग पसंद नहीं आते, जिनमें अंदरूनी ताकत है और जो पार्टी के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर एक और दुर्गुण पैदा कर दिया है. वह कहते हैं, आई नो एवरीथिंग, व्हॉट आई एम सेइंग इज राइट, व्हॉट यू आर सजेस्टिंग, यू आर रॉन्ग. और इसने राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एरोगेंस पैदा कर दिया है. और जहां एरोगेंस होती है और जब वह जनता के सामने आ जाती है या पार्टी के सामने आ जाती है, तो उसके परिणाम बहुत खराब होते हैं.

राहुल का दिमाग बनाने वाले मोहन गोपाल से पहले यह काम जयराम रमेश करते थे, लेकिन अब वह उस दायरे से बाहर हैं. मोहन गोपाल भी मुड़े-तुड़े कपड़े पहनते हैं. वह पहले एनएसयूआई में थे. वह पहले अमेरिका गए और वहां से देश की राजनीति सीखकर आए हैं. ओबीसी समर्थक हैं और वह राहुल गांधी को विभिन्न विषयों पर नोट्स बनाकर देते रहते हैं. राजू आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और एससी-एसटी हैं. राहुल गांधी के भाषणों में जो एससी-एसटी समर्थक तत्व आता है, उसके पीछे राजू का योगदान है. मधुसूदन मिस्त्री, सीपी जोशी, कुछ रोल मोहन प्रकाश भी कभी निभाते हैं. ये हैं, राहुल गांधी के प्रत्यक्ष तौर पर दिमाग बनाने वाले मित्र. केरल से आने वाले मोहन गोपाल मोटा कुर्ता पहनते हैं. अभी राहुल गांधी से दिल्ली चुनाव से ठीक पहले ग़लती हुई. ग़लती यह कि उन्होंने यूथ कांग्रेस की एक बैठक बुलाई, जिसमें एक नतीजा निकला कि चूंकि कांग्रेस प्रो-मुस्लिम ज़्यादा हो गई है, इसलिए उसे हार का सामना करना पड़ा. अब सवाल यह है कि अगर ऐसी बैठक करनी ही थी, तो दिल्ली चुनाव के बाद करते. यह तथ्य उजागर होते ही आपको मिलने वाला एक-दो प्रतिशत वोट भी शून्य हो गया.

सीपी जोशी साहब मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए थे. एक वोट से नहीं हारते, तो वह राजस्थान में गहलोत की जगह मुख्यमंत्री होते. उन्हें गुजरात सौंपा गया. उन्होंने वहां थ्योरी निकाली कि जो दो बार हार गया है, उसे टिकट नहीं देना चाहिए. और इस सिद्धांत ने गुजरात में सबके टिकट कटवा दिए, जिसमें नरहरि अमीन जैसा बड़ा नाम भी शामिल है. जो हार्ड कोर कांग्रेसी रहे, वे कांग्रेस से दूर जाने लगे. स्वयं सीपी जोशी हमेशा गुस्से में रहने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं. पार्टी एक तरह के भ्रम में जी रही है. उत्तर भारत की राजनीति के अंतर्विरोध मधुसूदन मिस्त्री नहीं समझते. उत्तर प्रदेश में, जहां जाति की राजनीति बुरी तरह चलती है, उनके सुझाव पर निर्मल खत्री पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं. खत्री लगातार कह रहे हैं कि वह बीमार हैं, वह पार्टी को आगे नहीं ले जा सकते. पर चूंकि मधुसूदन मिस्त्री ने सुझाया है,

> लोग सोनिया जी से कहते हैं कि कांग्रेस सिमट रही है. वह सब सुन रही हैं, पर चुप रहती हैं. शायद यह इस तथ्य को पुख्ता करता है कि वह राहुल को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो गई हैं. यद्यपि मां देख रही है कि नुक़सान हो रहा है, पर कुछ कर नहीं पा रही है. वह बेटे और पार्टी की स्थिति के बीच शायद कोई रास्ता तलाश रही हैं. दूसरी तरफ़ राहुल गांधी बात करने में बहुत तेज हैं. मुझे जिस नेता ने घटना बताई, उसने कहा कि वह बहुत उस्ताद हैं. वह हर बार अपनी मां को कनविंस कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मां, ऐसे पार्टी को ठीक करूंगा, वैसे ठीक करूंगा. एक इलेक्शन बाहर रहने से कुछ नहीं होता. मैं पार्टी को ऐसे बनाऊंगा, यूथ कांग्रेस को इस तरह मजबूत करूंगा और राजनीति में अच्छे लोगों को लाकर दस साल बाद पचास साल के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ले आऊंगा.

तो राहुल गांधी उन्हें ही अध्यक्ष बनाकर चुनाव की लड़ाई लड़ना चाहते हैं. राहुल गांधी इस राय पर भी गए कि समझौते नहीं करने हैं, गठबंधन में नहीं जाना है, तो उन्होंने महाराष्ट्र में बनता हुआ गठबंधन तोड़ दिया. जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिश्ता तोड़ दिया. जबकि जम्मू में आठ सीटें कांग्रेस एक हज़ार से कम वोटों से हारी है. राहुल गांधी के बारे में, जो उनके साथ मीटिंगों में बैठते हैं, उनका कहना है कि वह उत्तेजित होकर (अंग्रेजी में हाइपर कहते हैं) फ़ैसले लेते हैं. उनका यह वाक्य-यू डोंट नो व्हॉट आई एम सेइंग इज राइट, लोग अक्सर सुनते हैं.

कांग्रेस कम हो रही है, सिकुड़ रही है या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शब्दों में, कांग्रेस डूब रही है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने सोनिया गांधी का नाम गांधारी रख दिया है, जिसे अपने बेटे का कोई भी निगेटिव प्वाइंट, व्यक्तित्व में कोई भी कमी दिखाई ही नहीं देती. लोकसभा चुनाव हारने के बाद, जिसमें पहली बार राहुल को एक बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था, मां यानी सोनिया गांधी राहुल को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो गई हैं. कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने एक कहानी सुनाई कि यह एक्जटिली किसी एक घटना का दोहराव है. जब कांग्रेस चुनाव हार गई, तो संजय गांधी को लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी भी ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थीं. उन्होंने बताया कि 1977 की हार के बाद रामलीला मैदान में एक सम्मेलन हो रहा था. संजय गांधी नीचे श्रोताओं के साथ बैठे थे. कुछ लोगों ने शोर मचाया कि संजय गांधी को ऊपर लाओ. तो कुछ बड़े कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया. इसमें वसंत साठे का नाम प्रमुख था. जब सम्मेलन ख़त्म हो गया, तो इंदिरा जी ने इस नेता को बुलाया और कहा कि आपके पास जो कार है, उसे जाने दीजिए. आप मेरी कार में चलिए. रास्ते में उन्होंने इस नेता से कहा कि वसंत साठे से कहिए कि अगर आगे उन्होंने ऐसा किया, तो मैं उन्हें पार्टी से निकाल कर फेंक दूंगी. साथ ही उन्होंने कहा कि संजय गांधी के सारे नज़दीक के लोगों को बुलाइए और उन्हें इनकरेज करिए और उन्हें पार्टी से जो मदद मिल सकती है, वह दीजिए.

लोग सोनिया जी से कहते हैं कि कांग्रेस सिमट रही है. वह सब सुन रही हैं, पर चुप रहती हैं. शायद यह इस तथ्य को पुख्ता करता है कि वह राहुल को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो गई हैं. यद्यपि मां देख रही है कि नुक़सान हो रहा है, पर कुछ कर नहीं पा रही है. वह बेटे और पार्टी की स्थिति के बीच शायद कोई रास्ता तलाश रही हैं. दूसरी तरफ़ राहुल गांधी बात करने में बहुत तेज हैं. मुझे जिस नेता ने घटना बताई, उसने कहा कि वह बहुत उस्ताद हैं. वह हर बार अपनी मां को कनविंस कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मां, ऐसे पार्टी को ठीक करूंगा, वैसे ठीक करूंगा. एक इलेक्शन बाहर रहने से कुछ नहीं होता. मैं पार्टी को ऐसे बनाऊंगा, यूथ कांग्रेस को इस तरह मजबूत करूंगा और राजनीति में अच्छे लोगों को लाकर दस साल बाद पचास साल के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ले आऊंगा. यानी 2025 में सरकार हमारी होगी, मतलब कांग्रेस की होगी. शायद राहुल गांधी की इन्हीं बातों से प्रभावित होकर सोनिया गांधी सितंबर में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने जा रही हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 51
दिल्ली, 23 फरवरी-01 मार्च 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

आम आदमी पार्टी का असर

दिलीप चेरियन

क्या 27 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव डीएम सपोलिया को नई सरकार उनका कार्यकाल समाप्त होने तक बनाए रखेगी? यह दिल्ली में नौकरशाहों द्वारा पूछे जा रहे सवालों में से एक है. हालांकि, उन्हें अरविंद केजरीवाल के बतौर मुख्यमंत्री वापस आने पर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की आशंका है. नौकरशाहों को वह बात याद है कि पिछली बार जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने सपोलिया को मुख्य सचिव के पद से हटा दिया था, जिनकी कुछ महीने बाद पद पर वापसी हो गई थी. अब आप और केजरीवाल की दिल्ली की गद्दी पर वापसी हो गई है. नौकरशाही पर नज़र रखने वालों को अंदेशा है कि नई सरकार सरकारी कामकाज पूरा करने में अपनी मदद के लिए चुनिंदा अफसरों का चुनाव करेगी. पिछली बार केजरीवाल ने सपोलिया की जगह दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष एसके श्रीवास्तव को मुख्य सचिव नियुक्त किया था. केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद सबसे पहले उन्हें ही पद से हटाया गया था. इस वजह से उनकी वापसी की संभावना सबसे प्रबल है. इसी तरह जिन अधिकारियों पर केजरीवाल को विश्वास है, उनकी वापसी की संभावनाएं प्रबल हैं. ■

धीमी चाल

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त बाबुओं के बीच काफी हड़कंप मचा हुआ है. कथित तौर पर इन दो हाई प्रोफाइल पदों के लिए एक सौ से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारियों ने आवेदन किया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गहनता से निगरानी किए जाने की वजह से चयन प्रक्रिया और दुष्कर हो गई है. इसलिए मोदी सरकार अवांछित विवादों से बचने के लिए सावधानी से काम कर रही है. इस तरह के विवादों का सामना यूपीए सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान करना पड़ा था. सूत्रों के अनुसार, इस पद की दौड़ में देवेंद्र सिकरी, पूर्व पर्यटन सचिव परवेज दीवान, पंकज जैन, एएस लांबा, पूर्व जहाजरानी सचिव विश्वपति त्रिवेदी और पूर्व पेट्रोलियम सचिव जीसी चतुर्वेदी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. सीवीसी के पद की दौड़ तब और रोचक हो गई, जब सतर्कता आयुक्त राजीव ने इसके लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी. इनमें से कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त बनता है, यह देखने की बात है. सुप्रीम कोर्ट 23 फरवरी को सुनवाई के बाद कह सकता है कि जिन लोगों के पास पूर्व में इस तरह का कार्य करने का अनुभव हो, उन्हें वरीयता दी जाए. इससे कई हाई प्रोफाइल आवेदकों की दावेदारी ख़तरे में पड़ जाएगी. सरकार इस मामले में बहुत संभल कर क़दम उठा रही है और देरी के बावजूद पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है. ■

बजट पर जोर

वित्त मंत्री अरुण जेटली और बजट तैयार करने में जुटे अधिकारी माह के अंत तक बजट को अंतिम रूप देने के लिए बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं. यह बजट मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट होने के साथ-साथ हाल के समय का सबसे प्रत्याशित बजट है. इसलिए टीम जेटली के कुछ चुनिंदा अधिकारियों, जैसे वित्त सचिव महिर्षी, वाणिज्य सचिव शक्तिकांत दास, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी रतन वटाल के पास देने के लिए बहुत कुछ है. उनके सामने प्रमुख आर्थिक लक्ष्यों से समझौता किए बगैर सार्वजनिक निवेश के लिए पैसा जुटाकर अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने जैसा बड़ा दायित्व है. जाहिर है, इस कार्य की गंभीरता की वजह से ही प्रधानमंत्री कार्यालय सही बजट सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है. जिस तरह वित्त मंत्री और उनकी टीम काम में लगी हुई है, उसी तरह नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा समानांतर तरीके से बजट निर्माण में लगे हुए हैं. वह स्वतंत्र रूप से आर्थिक विशेषज्ञों से बजट निर्माण के संबंध में राय ले रहे हैं. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

कृष्णा चौधरी महानिदेशक बने

1979 बैच एवं बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी कृष्णा चौधरी को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है. चौधरी इससे पहले रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे.

भुवनेश निजी सचिव नियुक्त

1994 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) अधिकारी भुवनेश कुलश्रेष्ठ को पंचायतीराज राज्य मंत्री निहाल चंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है.

प्रसांथ न्याय विभाग से जुड़े

1991 बैच के आईटीएस अधिकारी प्रसांथ कुमार जल्द ही 1992 बैच के आईटीएस अधिकारी शंभु प्रसाद सिंह के स्थान पर निदेशक के रूप में न्याय विभाग से जुड़ सकते हैं.

राजीव प्रधान आवासीय आयुक्त

1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव बंसल नई दिल्ली स्थित नगालैंड हाउस में आवासीय आयुक्त नियुक्त हुए हैं. वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत अप्रैल 2013 के बाद से केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में सचिव के रूप में कार्यरत थे.

अभिषेक जहाजरानी मंत्रालय गए

2003 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक चंद्रा को जहाजरानी मंत्रालय भेजा गया है. वह 1998 बैच के आईआरएस आईटी अधिकारी संबित त्रिपाठी का स्थान लेंगे.

सोनिया यह मानती हैं कि नरेंद्र मोदी को न नीतीश रोक पाएंगे और न मुलायम सिंह. सिर्फ़ राहुल गांधी रोक पाएंगे. बाकी कांग्रेस नेताओं का मानना है कि उन्हें केवल प्रियंका रोक सकती हैं. राहुल तो पहले दौर में उन्हें 2025 तक प्रधानमंत्री बने रहने का रास्ता दे रहे हैं. कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि अब अकेले प्रियंका भी नहीं रोक सकतीं, क्योंकि आज की राजनीतिक सच्चाइयां बदल गई हैं. उन्हें क्षेत्रीय ताकतों से गठजोड़ या समझौता करना पड़ेगा, तभी नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने का उपाय किया जा सकता है. इसके लिए वे राहुल से ज़्यादा प्रियंका गांधी को उपयुक्त मानते हैं. एक बड़े नेता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, लालू यादव, ओम प्रकाश चौटाला आदि से गठबंधन करना अब आवश्यक हो गया है.

फ़ोटो : प्रभात पाण्डेय

कांग्रेस का भविष्य किसके हाथ

राहुल या प्रियंका

संतोष भारतीय

राहुल की बहन प्रियंका गांधी, जो अब तक लगातार कहती रही हैं कि वह राजनीति में कभी नहीं आएंगी. दरअसल, राहुल गांधी के साथ प्रियंका का रिश्ता भी अजीब है. सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका आएं, पर प्रियंका का मानना है कि अगर वह बिना राहुल को सफलता मिले राजनीति में आती हैं, तो लोग मानेंगे कि उन्होंने राजनीति से राहुल गांधी को बाहर कर दिया और यह स्वयं प्रियंका का भी मानना है. उन्होंने अपने एक अंतरंग मित्र से कहा, मैं अगर अभी आती हूं, अगर राहुल को सफलता न मिले, तो इसे राहुल को डिस्लाज करना माना जाएगा. प्रियंका यह जानती और मानती हैं कि जिस दिन वह कांग्रेस में आ गईं, एक भी आदमी राहुल के पास नहीं जाएगा. उस दिन राहुल प्रियंका की जगह होंगे और आइसोलेट हो जाएंगे. प्रियंका ने अपने नज़दीकी लोगों से कहा कि यह ग़लत है कि राहुल उनके राजनीति में आने के ख़िलाफ़ हैं. दरअसल, राहुल ने उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव रखा था और यह भी कहा कि वह केंद्र में महामंत्री बन जाएं और उनके साथ घूमें. सोनिया गांधी को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं है. पर मजे की बात यह है कि सोनिया गांधी हां भी नहीं कह रही हैं. शायद वह भी इस स्थिति को समझ रही हैं कि अगर प्रियंका राजनीति में आएंगी, तो राहुल गांधी को कोई नहीं पूछेगा. सोनिया गांधी भी अंतत: रिटायरमेंट लेना चाहती हैं. इसलिए वह सितंबर में अध्यक्ष पद छोड़ रही हैं. इसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी है. पिछले छह महीने से उन्होंने सारे अधिकार राहुल गांधी को दे दिए हैं. राहुल अपने साथियों से कहते हैं कि उनके पास अधिकार ही नहीं हैं. शायद वह मां के पूर्ण रिटायरमेंट के बाद ही खुद को अधिकार संपन्न मान पाएंगे, ऐसा उनके दोस्तों का कहना है. राहुल अक्सर कहते हैं कि मम्मी के लोग उन्हें कुछ करने ही नहीं देते. मम्मी के लोगों से सीधा मतलब अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी और मोती लाल बोरा से है.

प्रियंका गांधी से उनकी दोस्त ने कहा कि राहुल को आदमियों की पहचान नहीं है. इस पर प्रियंका ने कहा कि यह ग़लत है. राहुल को आदमियों की पहचान है, पर उनकी कमजोरी यह है कि वह जिसे पसंद नहीं करते, उसके मुंह पर कह देते हैं, जबकि मैं कहती नहीं हूं. प्रियंका का मानना है कि राहुल टैक्टफुल नहीं हैं. प्रियंका के इस मित्र का यह भी कहना है कि प्रियंका मां एवं भाई की समस्या और अंतर्विरोध समझती हैं. कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कह रहा है कि राहुल फेल हो गए हैं. प्रियंका से तो लोगों ने यहां तक कहा कि बीमार को तो आप बचा सकती हैं, पर मुर्दों को कैसे बचाएंगी? प्रियंका लोगों की चिंताएं सुनती हैं. उनकी अपनी स्थिति भी पिछले कुछ दिनों में बदली है. पहले वह कहती थीं कि राजनीति में नहीं आएंगी, पर अब वह आएंगी. कब आएंगी, यही फ़ैसला प्रियंका गांधी को करना है और कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका इंतज़ार कर रहे हैं. राहुल गांधी कहते हैं कि प्रियंका को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद केंद्र में आना चाहिए. पर प्रियंका को लगता है कि जिसने भी राहुल को यह सुझाव दिया है, वह उन्हें (प्रियंका) राजनीति में असफल करना चाहता है. प्रियंका को लोग सलाह दे रहे हैं कि उन्हें महामंत्री–संगठन प्रभारी बनकर राजनीति में आना चाहिए. अंदाज़ा यह है कि मधुसूदन मिस्त्री जैसों ने राहुल के दिमाग में प्रियंका को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का आइडिया डाला है.

सोनिया यह मानती हैं कि नरेंद्र मोदी को न नीतीश रोक पाएंगे और न मुलायम सिंह. सिर्फ़ राहुल गांधी रोक पाएंगे. बाकी कांग्रेस नेताओं का मानना है कि उन्हें केवल प्रियंका रोक सकती हैं. राहुल तो पहले दौर में उन्हें 2025 तक प्रधानमंत्री बने रहने का रास्ता दे रहे हैं. कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि अब अकेले प्रियंका भी नहीं रोक सकतीं, क्योंकि आज की राजनीतिक सच्चाइयां बदल गई हैं. उन्हें क्षेत्रीय ताकतों से गठजोड़ या समझौता करना पड़ेगा, तभी नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने का उपाय किया जा सकता है. इसके लिए वे राहुल से ज़्यादा प्रियंका गांधी को उपयुक्त मानते हैं. एक बड़े नेता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, लालू यादव, ओम प्रकाश चौटाला आदि से गठबंधन करना अब आवश्यक हो गया है. साथ ही जगन मोहन रेड्डी और ममता बनर्जी से भी संबंध दोबारा बनाने पड़ेंगे. इस नेता का कहना है कि 1991 की भाजपा को कांग्रेस नहीं हटा पाई या नहीं रिप्लेस कर पाई, 1993 की सपा एवं बसपा को रिप्लेस नहीं कर पाई, बल्कि कांग्रेस सिकुड़ती और हारती चली गई. तब यह कैसे माना जाए कि कांग्रेस अकेले नरेंद्र मोदी का मुक़ाबला कर लेगी. उन्हें लगता है कि इन सब लोगों को साथ लेकर ही नरेंद्र मोदी का मुक़ाबला किया जा सकता है.

बिहार में एक अजीब स्थिति है. नीतीश कुमार कांग्रेस के समर्थक हैं, वहीं लालू यादव कांग्रेस के विरोधी हो गए हैं. सवाल यह है कि अगले पांच सालों में राहुल क्या करेंगे? अगर प्रियंका साथ आईं, तो कांग्रेस के नेताओं को कुछ आशा है. इसमें अंतर्विरोध किस तरह के विकसित होंगे, इस पर भी कांग्रेस नेताओं को डर है. वैसे कांग्रेस नेताओं का मानना है कि बहन यानी प्रियंका गांधी इस राजनीति, जिसमें नरेंद्र मोदी का तूफान चल रहा है, को रोकने में ज़्यादा असरदार साबित होंगी. कांग्रेस में आशा है कि प्रियंका गांधी के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह आ जाएगा. दूसरा, उन्हें अच्छी राजनीतिक सलाह दी जा सकती है, जो राहुल गांधी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि राहुल सुनते ही नहीं हैं. जैसे बिहार में किसके साथ जाना चाहिए, जगन को वापस लाना चाहिए. अब एक नई जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी पिछले चुनाव में चाहती थीं कि राहुल गांधी अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ जाएं और साथ में चाय पीकर आ जाएं. वह खुद मायावती से मिलने खामोशी से ऑटो रिक्शा में बैठकर जाना चाहती थीं, पर राहुल गांधी की नाराज़गी की वजह से नहीं गईं. उनके बारे में मानना है कि वह पॉलिटिकल एलायंस के लिए खुली हैं. शरद पवार की बेटी से उनकी दोस्ती हो सकती है. कांग्रेस के लोगों का मानना है कि प्रियंका राजनीति में नाक आगे करके नहीं चलेंगी, जबकि राहुल आज ऐसा ही कर रहे हैं. कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आने के लिए एक बड़ा कोलेशन बनाने की ज़रूरत है, जिसे कांग्रेस नेताओं की राय में सिर्फ़ प्रियंका बना सकती हैं.

कांग्रेस के कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि कुछ प्रदेश वहां के नेताओं के लिए छोड़ देने चाहिए, जैसे ममता बनर्जी के लिए बंगाल छोड़ दें, जगन रेड्डी के लिए आंध्र छोड़ दें, शरद पवार के लिए महाराष्ट्र छोड़ दें और इनकी पार्टियों को कांग्रेस में मर्ज कर लें. पर इन नेताओं का मानना है कि इस स्थिति को सिर्फ़ प्रियंका संभव कर सकती हैं, राहुल गांधी संभव नहीं कर सकते. बहुत सारी चीजों को दोबारा परिभाषित करने की ज़रूरत है, जिससे कांग्रेस की रणनीति सामने आएगी. कांग्रेस की नाक के नीचे से ब्राह्मण एवं दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी और अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग नेताओं के पास चला गया. इन वर्गों को वापस लाने में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रियंका गांधी सफल हो सकती हैं. पर यह कांग्रेस के नेताओं का जंगल विलाप है. वे रो रहे हैं, वे चीख रहे हैं, वे हाथ जोड़ रहे हैं, दोबारा राजनीति में खड़े होना चाहते हैं. पर किसी भी तरह उनकी बात न सोनिया गांधी सुन रही हैं, न राहुल गांधी सुन रहे हैं और प्रियंका गांधी अनमने मन से सुन रही हैं. इस कांग्रेस का बिखरना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, ऐसा खुद कांग्रेस के नेताओं का कहना है. पर जंगल में रोना हो रहा है. अरण्य रुदन हो रहा है. न कोई सुन रहा है, न कोई आंसुओं को देख रहा है. ■

editor@chauthiduniya.com

> प्रियंका गांधी से उनकी दोस्त ने कहा कि राहुल को आदमियों की पहचान नहीं है. इस पर प्रियंका ने कहा कि यह ग़लत है. राहुल को आदमियों की पहचान है, पर उनकी कमजोरी यह है कि वह जिसे पसंद नहीं करते, उसके मुंह पर कह देते हैं, जबकि मैं कहती नहीं हूं. प्रियंका का मानना है कि राहुल टैक्टफुल नहीं हैं. प्रियंका के इस मित्र का यह भी कहना है कि प्रियंका मां एवं भाई की समस्या और अंतर्विरोध समझती हैं. कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कह रहा है कि राहुल फेल हो गए हैं. प्रियंका से तो लोगों ने यहां तक कहा कि बीमार को तो आप बचा सकती हैं, पर मुर्दों को कैसे बचाएंगी? प्रियंका लोगों की चिंताएं सुनती हैं. उनकी अपनी स्थिति भी पिछले कुछ दिनों में बदली है. पहले वह कहती थीं कि राजनीति में नहीं आएंगी, पर अब वह आएंगी.

भाजपा ने सबसे पहली ग़लती किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर की. चूंकि किरण बेदी इससे पहले भाजपा की आलोचना करती रही थीं और हाल में पार्टी में शामिल हुई थीं. उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते ही पार्टी में विद्रोह के सुर सुनाई देने लगे. विपक्ष को भी यह कहने का मौक़ा मिल गया कि भाजपा के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वह पैराशूट उम्मीदवार उतार रही है. रही–सही कसर ख़ुद किरण बेदी ने पूरी कर दी. मीडिया के सवालों के कुछ ऐसे जवाब उन्होंने दिए, जो चुनाव में पार्टी का नुक़सान करने वाले थे. जब तक भाजपा नेतृत्व को अपनी ग़लतियों का एहसास होता, तब तक काफी देर हो चुकी थी.

अति आत्मविश्वास ने भाजपा को हरा दिया

शशि शेखर

यदि भाजपा की अप्रत्याशित पराजय के कारणों का आकलन किया जाए, तो उसमें दो मुख्य पहलू उभर कर सामने आते हैं. पहला यह कि आम आदमी पार्टी की रणनीति अधिक कारगर और असरदार थी. आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी और चुनाव की घोषणा होने से पहले ही भाजपा एवं कांग्रेस से बढ़त बना ली थी. पार्टी ने सबसे पहले अपने खिसके हुए जनाधार को सुरक्षित किया और भाजपा विरोधी मतदाताओं को यह यकीन दिलाया कि इस चुनाव में कांग्रेस कोई चुनौती नहीं पेश कर रही है. लिहाज़ा आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जो भाजपा को हराने की स्थिति में है. नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के जनाधार का एक बड़ा हिस्सा भी आम आदमी पार्टी को हस्तांतरित हो गया. और, आम आदमी पार्टी को एक ऐसी जीत मिली, जिसकी उम्मीद उसके नेताओं को भी नहीं थी. दूसरा पहलू यह है कि भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही कई ऐसी ग़लतियां कीं, जो उसके लिए न केवल घातक साबित हुईं, बल्कि एक ऐतिहासिक हार का कारण बनीं.

हालांकि, भाजपा यह कहकर खुद को सांत्वना दे रही है कि उसका मत प्रतिशत 2013 के विधानसभा चुनाव से बहुत अधिक कम नहीं हुआ है, इसलिए मतों की संख्या और जनाधार की बुनियाद पर पार्टी को अधिक नुक़सान नहीं हुआ है. लेकिन, सिक्के का एक और पहलू भी है. यदि 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिले मतों से इस चुनाव की तुलना की जाए, तो भाजपा के मत प्रतिशत में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की गई है. बहरहाल, भाजपा ने दिल्ली जैसे छोटे राज्य (जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है) के चुनाव को अत्यधिक महत्व देते हुए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ की, लेकिन उस रैली में पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई. इसी घबराहट में पार्टी ने आनन–फानन में अपनी रणनीति में बदलाव करना शुरू किया. और, फिर वह एक बाद एक ग़लतियां करती चली गई, जो अंत में उसकी इतनी बड़ी हार का कारण बनीं.

भाजपा ने सबसे पहली ग़लती किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर की. चूंकि किरण बेदी इससे पहले भाजपा की आलोचना करती रही थीं और हाल में पार्टी में शामिल हुई थीं. उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते ही पार्टी में विद्रोह के सुर सुनाई देने लगे. विपक्ष को भी यह कहने का मौक़ा मिल गया कि भाजपा के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वह पैराशूट उम्मीदवार उतार रही है. रही–सही कसर खुद किरण बेदी ने पूरी कर दी. मीडिया के सवालों के कुछ ऐसे जवाब उन्होंने दिए, जो चुनाव में पार्टी का नुक़सान करने वाले थे. जब तक भाजपा नेतृत्व को अपनी ग़लतियों का एहसास होता, तब तक काफी देर हो चुकी थी. डैमेज कंट्रोल के लिए समय नहीं था, इसलिए किरण बेदी के मीडिया से बात करने पर ही पाबंदी लगा दी गई. दरअसल, यह जोखिम पार्टी के जान–बूझकर उठाया था. भाजपा समझ गई थी कि इस बार उसका मुकबला सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से होने वाला है और कांग्रेस पार्टी यहां हाशिये पर चली गई है. चूंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अन्ना आंदोलन की उपज हैं और किरण बेदी भी उस आंदोलन का एक चेहरा थीं और एक पुलिस अधिकारी के तौर पर भी उनकी पहचान है, लिहाज़ा भाजपा को लगा कि बेदी आम आदमी पार्टी को हरा सकती हैं. लेकिन, भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. इसी वजह से भाजपा की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली सीट से भी वह चुनाव हार गईं.

लोकसभा चुनाव की कामयाबी के बाद भाजपा ने किसी भी प्रदेश के चुनाव में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी. उक्त सभी प्रदेशों में पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और हर जगह कामयाब हुई थी. आम आदमी पार्टी यह समझ रही थी कि अगर यह चुनाव अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी हुआ, तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अपने प्रचार में आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ़ से भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार से अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की तुलना शुरू कर दी. ज़ाहिर है, आम आदमी पार्टी ने यह एक पासा फेंका था, जिसमें भाजपा फंस गई.

आम आदमी पार्टी ने मुफ्त पानी, बिजली के बिल में कटौती और मुफ्त वाईफाई जैसे लोक–लुभावन वादे किए. जनता को भी लगा कि आप इन वादों को पूरा कर सकती है. चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा की तरफ़ से दिल्ली के विभिन्न अख़बारों में आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ कार्टून प्रकाशित हुए, जिनमें निजी तौर पर हमले किए गए, जिसका भाजपा के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ा. भाजपा की हार का एक महत्वपूर्ण कारण पार्टी नेतृत्व का अति आत्मविश्वास था. वे यह समझ रहे थे कि अपने स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन–चार रैलियों से दिल्ली का चुनाव जीत लेंगे, लेकिन उनका यही अति आत्मविश्वास पार्टी पर भारी पड़ गया.■

shashishekhar@chauthiduniya.com

दिग्गज कांग्रेसी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों हारे

यह प्रश्न निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ समझे जाने वाले पांच मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कभी न हारने वाले दिग्गज कांग्रेसी मुस्लिम उम्मीदवार आख़िर क्यों हार गए? आख़िर ऐसा क्या हुआ कि जो चेहरे इन क्षेत्रों में चुनाव के वक्त कांग्रेस की नैया पार लगाते थे, उन्हें इस बार धूल चाटनी पड़ी? आइए, जानते हैं कि इन सबके पीछे क्या वजह रही और खुद उक्त उम्मीदवार इस बारे में क्या सोचते हैं...

ए. यू. आसिफ

feedback@chauthiduniya.com

यह सच किसी से ढंका–छिपा हुआ नहीं है कि ओखला, बल्लीमारान, मटिया महल, सीलमपुर एवं मुस्तफाबाद दिल्ली के ऐसे मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कांग्रेस के गढ़ रहे हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में मटिया महल को छोड़कर शेष चार विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के टिकट पर मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए थे. मटिया महल में इस चुनाव से पहले राजद और बाद में जदयू के सहारे निर्वाचित होते आए विधायक शोएब इकबाल हाल में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और फिर उन्हें इस पार्टी से टिकट मिला. इस तरह वह भी दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज मुस्लिम उम्मीदवारों की सूची में शामिल हो गए. लेकिन, इस बार उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आसिम अहमद खां के हाथों जबरदस्त शिकस्त मिली. आसिम को 47,584 और शोएब को 21,488 वोट मिले.

कभी न हारने वाले शोएब इकबाल की 26,096 वोटों से हुई हार एक बहुत बड़ी हार मानी जा रही है. आश्चर्य की बात यह है कि कुछ मुस्लिम संगठनों एवं शख्सियतों ने उनके समर्थन में अपील भी जारी की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ. ग़ौरतलब है कि चौथी दुनिया अपने 02–08 फरवरी, 2015 के अंक में दिल्ली का चुनावी दंगल शीर्षक तले पहले ही बता चुका था कि 65 प्रतिशत मुस्लिम वोटों वाले मटिया महल क्षेत्र में शोएब इकबाल का खासा प्रभाव है, लेकिन बार–बार पार्टी बदलने के चलते वह बदनाम हो गए हैं. हालांकि, इस बारे में शोएब की राय अलग है. उनका कहना है कि वह आम आदमी पार्टी की सुनामी का शिकार हो गए. बताते चलें कि मतदान से दो दिन पहले शोएब इकबाल की रैली में हज़ारों लोगों ने शिरकत की थी.

दूसरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बल्लीमारान है, जहां से पांच बार विधायक रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री हारून यूसुफ इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इमरान हुसैन से 43,913 वोटों से हार गए. हारून को सिर्फ़ 13,205 वोट मिले. उन्हें स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि वह इतने ज़्यादा वोटों से कैसे हार गए. ग़ौरतलब है कि चौथी दुनिया ने अपने उक्त अंक (देखें, दिल्ली का चुनावी दंगल) में बताया था कि स्थानीय लोगों की शिकायत है कि हारून ने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया और न कभी दिखाई पड़े. हारून को शिकस्त देने वाले इमरान हुसैन क्षेत्र के काउंसलर हैं और युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं.

तीसरा क्षेत्र ओखला है, जिसे मटिया महल और बल्लीमारान की तरह पुरानी दिल्ली कहा जाता है. यहां से पिछली बार कांग्रेस के आसिफ मुहम्मद खां निर्वाचित हुए थे. आसिफ अपने विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं. इसके अलावा वह क्षेत्र में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के समय उनका एवं उनके परिवार का सहारा बनते रहे और उनकी आवाज़ उठाते रहे. अभी हाल में बरेलवी विचारधारा के इस्लामी विद्वान मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही की गिरफ्तारी होने पर आसिफ खासे सक्रिय रहे, उनकी रिहाई कराने में भी कामयाब रहे. वैसे, इस मामले में आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अमानतुल्लाह खां भी खासे सक्रिय रहे. आसिफ 2013 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वह तीसरे नंबर पर रहे. यहां आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खां ने भाजपा उम्मीदवार ब्रह्म सिंह को 60,321 वोटों से जबरदस्त शिकस्त दी. अमानतुल्लाह खां को 1,04,271 वोट मिले, जबकि ब्रह्म सिंह को 39,739 और आसिफ को 20,135 वोट मिले. आसिफ मुहम्मद खां भी शोएब इकबाल की तरह बार–बार पार्टी बदलते रहे. हालांकि, चौथी दुनिया से बातचीत में आसिफ ने कहा कि जब कोई सुनामी होती है, तो लोग विकास एवं अन्य कार्यों की अनदेखी कर देते हैं. लेकिन, काउंसलर या विधायक रहे बगैर भी वह क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे.

चौथा क्षेत्र सीलमपुर है. कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद 1993 से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे. वह भी इस सुनामी में बह गए और तीसरे नंबर पर पहुंच गए. मतीन अहमद को सिर्फ़ 23,791 वोट मिले, जबकि आप उम्मीदवार हाजी मुहम्मद इशराक उर्फ भूरे को 57,302 और दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के संजय जैन को 29,415 वोट मिले. बकौल चौधरी मतीन अहमद, ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि मुसलमानों में यह सोच उभरने लगी कि कांग्रेस तो भाजपा को रोक नहीं पाएगी और न कुछ सीटें जीतने से उसकी सरकार बनेगी. दूसरी तरफ़ आम आदमी पार्टी ने बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दे उठाए, जबकि कांग्रेस की ओर से ऐसा कुछ नहीं हुआ. इसके अलावा आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रबंधन दीगर सियासी दलों की तुलना में मजबूत था. मतीन अहमद कहते हैं, यही वजह थी कि मेरे द्वारा कराए गए विकास कार्य और मेरी छवि भी मेरे काम नहीं आ सके.

पांचवां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मुस्तफाबाद है, जहां भाजपा के जगदीश प्रधान, जो पिछली बार कुछ वोटों से हार गए थे, ने इस बार कांग्रेस के हसन अहमद को 6,031 वोटों से परास्त किया. जगदीश प्रधान को 58,388 और हसन अहमद को 52,357 वोट मिले. यहां आम आदमी पार्टी के हाजी युनूस बुरी तरह हारे. हसन अहमद अपनी हार का कारण मुस्लिम वोटों का विभाजन बताते हैं. इस तरह पांच मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में से चार में दिग्गज मुस्लिम उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की सुनामी और अच्छे चुनाव प्रबंधन के साथ–साथ अपनी खराब होती छवि के कारण हार गए, जबकि मुस्तफाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार को अपनी अक्षमता के साथ–साथ मुस्लिम वोटों के चलते हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस के लिए यह सब कुछ चिंता और आत्ममंथन का विषय है.■

> नेता जी गाड़ी से बाहर अवतरित हुए. नारों और स्वागत के बीच उनका चेहरा भावों का विभोर ज्ञापित कर रहा है. नेता जी मंच पर लगी कुर्सी पर बैठ जाते हैं. उनके पीछे कुछ और कुर्सियां तुरंत लगाई जाती हैं. उन कुर्सियों पर यथाक्रम कैबिनेट मंत्री नारद राय, अंबिका चौधरी, मनोज पांडेय वगैरह बैठ जाते हैं. मंत्रियों की कुर्सी के पीछे भी कुर्सियों का एक और क्रम बिछता है, जिस पर प्रदेश सचिव एवं कार्यालय प्रभारी एसआरएस यादव विराजमान हो जाते हैं. भीड़ लॉन में बिछ जाती है.

थोड़ा समाजवाद और ज़्यादा मुलायमवाद

> मुलायम सिंह का बोलना जारी है. फिल्म के इस ट्रैजेडी वाले पार्ट में कार्यकर्ताओं की रुहानी संलग्नता स्पष्ट दिख रही है. पीछे की कतार में बैठे मंत्रियों के चेहरे पर झेंप और गुस्से की रेखाएं झलक दिखला जा रही हैं. नेता जी कहते हैं, लोकसभा चुनाव में हार के बाद सभी लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड में राजी थे कि मंत्रियों को हटाया जाए और सजा दी जाए, मगर मैं ही पिघल गया. सोचा कि चलो, एक मौक़ा और देते हैं. मगर अभी भी स्थितियां नहीं सुधरी हैं और मुझे बहुत निराशा है आप लोगों के कामों से. ऐसा कहकर मुलायम सिंह मंत्रियों की तरफ़ इशारा करते हैं. मुलायम सिंह आगे बोले, भाजपा हमसे बहुत आगे तेजी से काम कर रही है. अमित शाह ने अपने प्रत्याशी भी चयनित कर लिए हैं, उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में गुप्त रूप से काम करने को भी कह दिया गया है, पर हमारी कोई तैयारी ही नहीं है. मैं भी जल्दी ही पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दूंगा. जिन-जिन लोगों को पार्टी के किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद से शिकायत, समस्या या कोई सुझाव है, वे कागज पर लिखकर एसआरएस यादव और मेरे सचिव अरविंद यादव को दे दें. नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन कार्रवाई होगी.

प्रभात रंजन दीन

स्थान-लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय. समय-पूर्वान्ह 11 बजे. पार्टी दफ्तर में गुनगुनी धूप है, ठंडी-ठंडी बयार भी है, थोड़ी कंपकंपाहट भी है, लेकिन नेताजी के शीघ्र दफ्तर पहुंचने की सुगबुगाहट वहां मौजूद लोगों को थोड़ी-थोड़ी गर्मी भी दे रही है. अलर्ट होता है...नेता जी मुलायम सिंह यादव बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं. पार्टी दफ्तर में झंडारोहण वाले स्थल पर कुर्सियां लग जाती हैं. सामने लॉन में भी कुर्सियां लग जाती हैं. तक़रीबन दो-ढाई सौ लोग लॉन और इधर-उधर चहलकदमी कर रहे होते हैं. इनमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता सब शरीक हैं. कुछ फरियादीनुमा चेहरे भी हैं. कुछ हमारे जैसे भी हैं, जग का मुजरा लेने वाले. सब लोग नेता जी के पार्टी दफ्तर में आने का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने-अपने मतलब की, अपनी-अपनी सियासत की और अपनी-अपनी समझ की चर्चा में मशगूल हैं. उन चर्चाओं का निकस यह समझ में आता है कि पार्टी की दुर्दशा पर चिंता या चटखारा ही गुफ्तगू के केंद्र में है.

लोगों की बातचीत कभी चलती है, कभी चलते-चलते पार्टी दफ्तर के गेट की ओर उचक कर झांकने के क्रम में थमती है और फिर नेता जी के आने में हो रही अनावश्यक देरी की बात का प्रसंग बनाते हुए फिर से शुरू हो जाती है. समय बीतता जाता है. इसी बीच मुलायम सिंह के निवास स्थान पर उनसे मिलने आए लोगों को भी पार्टी दफ्तर के लिए ही डायवर्ट कर दिया जाता है. उन लोगों के पार्टी दफ्तर पहुंचने से वहां पहले से मौजूद लोगों में थोड़ी असहजता झलकती है, लेकिन अब नेता जी आएंगे, इसका सुकून वाला भाव भी उनके चेहरे से झांकता है. पार्टी दफ्तर में लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है. नेता, कार्यकर्ता, दोनों स्तर के मंत्री और आम चेहरे वाले लोगों का हुजूम इकट्ठा होता जा रहा है. अब लोगों की निगाहें नेता जी के इंतज़ार में पार्टी दफ्तर के दरवाजे पर ही जाकर टंग गई हैं.

दोपहर का क़रीब दो-सवा दो बज रहा है. कुछ लोग तो निराश होकर वापस लौट भी जाते हैं. उन्हें नेताओं की सवारी के आने-जाने में समय के घिसटने का शायद अनुभव नहीं रहा होगा. अब तो ढाई भी बज चुके हैं. धैर्यवान लोगों की जमात जुटी हुई है. बतकहियां भी जारी हैं. उसी में अलग-अलग गुच्छे बने हुए हैं और गुटबाजी पर बतिया रहे हैं. क़रीब ढाई-पौने तीन का समय हो गया है. अचानक सरसराहट और सनसनाहट का माहौल बनता है. माहौल ही बता देता है कि नेता जी आ रहे हैं. नेता जी आ चुके हैं. दफ्तर का दरवाजा खुलता है और नेता जी का काफिला अंदर दाखिल हो जाता है. पार्टी दफ्तर का पर्यावरण, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, नेता जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, मुलायम सिंह ज़िंदाबाद के नारों से भर गया और नेता जी का चेहरा भावों से भर गया.

नेता जी गाड़ी से बाहर अवतरित हुए. नारों और स्वागत के बीच उनका चेहरा भावों का विभोर ज़ापित कर रहा है. नेता जी मंच पर लगी कुर्सी पर बैठ जाते हैं. उनके पीछे कुछ और कुर्सियां तुरंत लगाई जाती हैं. उन कुर्सियों पर यथाक्रम कैबिनेट मंत्री नारद राय, अंबिका चौधरी, मनोज पांडेय वगैरह बैठ जाते हैं. मंत्रियों की कुर्सी के पीछे भी कुर्सियों का एक और क्रम बिछता है, जिस पर प्रदेश सचिव एवं कार्यालय प्रभारी एसआरएस यादव विराजमान हो जाते हैं. भीड़ लॉन में बिछ जाती है. सब नेता जी का मुखारबिंद निहार रहे हैं, कुछ सुनने को तत्पर दिख रहे हैं कि अचानक नेता जी माइक न होने पर गुस्सा होने लगते हैं. व्यवस्था खड़खड़ाती है और आनन-फानन में एक माइक की व्यवस्था हो जाती है.

लगता है, नेता जी आजकल कुछ नाराज़ चल रहे हैं. अपने संबोधन की शुरुआत ही वह कार्यकर्ताओं पर नाराज़गी जताते हुए करते हैं. कहते हैं कि हम लोकसभा चुनाव की तरह ही 2017 का विधानसभा चुनाव भी बुरी तरह से हारने वाले हैं. अचानक सबके होश फाख्ता हो जाते हैं. यह नेता जी ने क्या कह दिया! मुलायम सिंह अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, क्योंकि आप सब अपने-अपने क्षेत्रों में काम करने के बजाय यहां गणेश परिक्रमा करने में ही लगे हुए हैं. मैं अपना एक ज़रूरी काम छोड़कर यहां आप सबके होने की जानकारी पाकर आप सबसे मिलने चला आया. मेरा आप सबसे कहना है कि आप सब अपने-अपने क्षेत्रों में काम करिए और कोई शिकायत हो, तो हमें चिट्ठी के माध्यम से बताइए. हम सबकी चिट्ठी पढ़ते हैं और चिट्ठियों का जवाब भी देते हैं और कार्रवाई भी करते हैं.

जैसे ही नेता जी ने यह कहा, तभी मेरठ के सिवालखास क्षेत्र से आई एक महिला कार्यकर्ता खड़ी हो गई और कहने लगी, नेता जी कोई काम नहीं हो रहा है. शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. महिला की बोली से तो नेता जी सन्न. महिला से पूछा, तुम्हारे पोलिंग बूथ पर कितने वोट मिले थे? महिला बोली, 27. नेता जी ने महिला को डपटा, इतने कम वोट पार्टी को दिलाती हो और बोलती हो कि काम नहीं होता, सुनवाई नहीं होती! अब तो महिला ने नेता जी को ज़मीनी दृश्य दिखाना शुरू कर दिया. उसने सपा प्रमुख से लेकर तमाम बड़े नेताओं को लोकसभा में मिले वोटों का हिसाब-किताब सामने रखना शुरू कर दिया. वह अखिलेश सरकार के कामकाज से लेकर मंत्रियों के अराजक रवैये और शिकायत करने पर कोई कार्रवाई न होने की पुलिंदा भर-भर कर जो शिकायतें थीं, पेश करने लगी. पूरी पार्टी ही कुछ समय के लिए कठघरे में खड़ी हतप्रभ दिखने लगी. मुलायम सिंह इतने खफा हो गए कि इस बोली को अनुशासनहीनता करार देते हुए उस महिला को पार्टी दफ्तर से बाहर जाने की हिदायत देने लगे, लेकिन महिला भी दमदारी से वहीं खड़ी रही और अपनी बात पर अड़ी रही. मुलायम सिंह बिफर उठते हैं और सुरक्षाकर्मियों से उस महिला को जबरन पार्टी दफ्तर से बाहर निकालने के लिए कहते हैं. महिला को समाजवाद के परिसर से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता है.

दृश्य बदलता है. नेता जी का संबोधन फिर शुरू होता है. इस बार उनके निशाने पर मंत्री, सरकार और मुख्यमंत्री होते हैं. अभी-अभी एक महिला कार्यकर्ता को बाहर निकाले जाने के वाकये पर क्षुब्ध हुए कार्यकर्ताओं को सहलाने का प्रयास करते हुए मुलायम सिंह कहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने में नौजवानों और कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है और अब उसी सरकार में उनकी उपेक्षा हो रही है. पार्टी के नेता और मंत्रीगण अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए हैं. उनके अपने स्वार्थों और झगड़ों के बीच पार्टी और कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है. इससे पार्टी को नुक़सान पहुंच रहा है. मुझे भी आजमगढ़ में हराने की कोशिश हमारे ही नेताओं ने की थी, मगर मैंने खुद जब वहां कमान संभाली, तब हार से बच पाया. मुझे संसद में सुनना पड़ता है कि केवल परिवार ही जिता पाए. इस बात से मुझे बड़ी तकलीफ होती है. कन्नौज में भी नेताओं की आपसी लड़ाई से डिंपल हारते-हारते बचीं. मुख्यमंत्री अखिलेश सोचते हैं कि दौड़-भाग करने से वोट मिल जाएगा. ऐसा नहीं है. वोट संघर्ष करने और जनता एवं कार्यकर्ताओं के हितों का ख्याल रखने से मिलता है.

मुलायम सिंह का बोलना जारी है. फिल्म के इस ट्रैजेडी वाले पार्ट में कार्यकर्ताओं की रुहानी संलग्नता स्पष्ट दिख रही है. पीछे की कतार में बैठे मंत्रियों के चेहरे पर झेंप और गुस्से की रेखाएं झलक दिखला जा रही हैं. नेता जी कहते हैं, लोकसभा चुनाव में हार के बाद सभी लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड में राजी थे कि मंत्रियों को हटाया जाए और सजा दी जाए, मगर मैं ही पिघल गया. सोचा कि चलो, एक मौक़ा और देते हैं. मगर अभी भी स्थितियां नहीं सुधरी हैं और मुझे बहुत निराशा है आप लोगों के कामों से. ऐसा कहकर मुलायम सिंह मंत्रियों की तरफ़ इशारा करते हैं. मुलायम सिंह आगे बोले, भाजपा हमसे बहुत आगे तेजी से काम कर रही है. अमित शाह ने अपने प्रत्याशी भी चयनित कर लिए हैं, उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में गुप्त रूप से काम करने को भी कह दिया गया है, पर हमारी कोई तैयारी ही नहीं है. मैं भी जल्दी ही पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दूंगा. जिन-जिन लोगों को पार्टी के किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद से शिकायत, समस्या या कोई सुझाव है, वे कागज पर लिखकर एसआरएस यादव और मेरे सचिव अरविंद यादव को दे दें. नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन कार्रवाई होगी.

इतने पर तो कार्यकर्ता भावुक हो गए और उनके सब्र का बांध टूटने लगा. कार्यकर्ताओं के बीच से एक ने मंत्रियों के प्रति अपनी खुली नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, सारे मंत्री धूर्त और चोर हैं, वे किसी भी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं करते. माल लेकर आने वालों को ही पूछते हैं. कार्यकर्ता की इस खुली शिकायत पर मंत्री अंबिका चौधरी और मनोज पांडेय बिगड़ने लगे. उनका मंत्री पद उन पर इतना हावी दिखने लगा कि उन्हें नेता जी की मौजूदगी भी दिखनी बंद हो गई. वे उस कार्यकर्ता से उलझ पड़े. इस पर मुलायम सिंह ने उन मंत्रियों को डपटा. बोले, यहां कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने का पूरा हक़ है. ये यहां नहीं कहेंगे, तो और कहां कहेंगे. उनकी इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन आप लोग बिफर रहे हैं. आप लोगों में धैर्य नहीं है. आलोचना सहने की क्षमता होनी चाहिए. मेरी भी बहुत आलोचना हुई, मगर मैं नहीं घबराया. अगर आप लोग सही ढंग से काम कर रहे होते, तो यह नौबत न आती. तभी कार्यकर्ताओं के बीच से कानपुर की एक महिला कार्यकर्ता नीलम रोमिला सिंह ने 2012 में अपना टिकट काटे जाने का हवाला देते हुए कहा, नेता जी, आपने मुझे लालबत्ती देने को कहा था, पर आपका वादा झूठा निकला. इस पर नेता जी फिर से नाराज़ हो गए और उन्हें शांत रहने को कहा. लेकिन, नीलम रोमिला सिंह कहां मानने वाली थीं. उनसे भी वहां से हटने को कहा गया. नेता जी ने इस अनुशासनहीनता पर भी नाराज़गी प्रगट की.

फिर नेता जी कार्यकर्ताओं से बोले, 2017 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मैं जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी करूंगा. आप लोगों से निवेदन है कि आपको प्रत्याशी ग़लत लगे या सही, आप उसे जिता ज़रूर देना. उस प्रत्याशी में केवल मुझे देखना. शिकवा-शिकायत सब बाद में बैठकर दूर कर लेंगे. प्रधानमंत्री न बन पाने का मुलायम सिंह का दर्द भी उभरा. बोले, अगर हमारी 40 सीटें भी आ जातीं, तो केंद्र में समाजवादी सरकार ही बनती. सभी दलों ने हमें अपना नेता मान लिया था और समर्थन देने को राजी थे, मगर नेताओं-मंत्रियों की गद्दारी से ऐसा नहीं हो सका. कार्यकर्ता कभी गद्दारी नहीं करता, उसकी कभी उपेक्षा नहीं होने दी जाएगी.

याद आया कि डॉ. राम मनोहर लोहिया कार्यकर्ताओं से कहते थे कि अगर हमारा प्रत्याशी ग़लत हो, तो उसे हर हाल में हराकर भेजना. लेकिन, अब मुलायम सिंह कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी ग़लत भी हो, तो उसे जिताकर भेजना. यह लोहिया के समाजवाद का मुलायमियत वाला संस्करण है. मुलायम सिंह बहुत कुछ समझने की बातें हवा में उछाल कर चल पड़े. हम-आप गुत्थियां सुलझाते रहें. कैसी पार्टी, कैसी सरकार, कैसा मुख्यमंत्री, कैसे मंत्री, कैसा सामंजस्य, किस हाल में कार्यकर्ता, किस हाल में समाज और किस हाल में समाजवाद...■

feedback@chauthiduniya.com

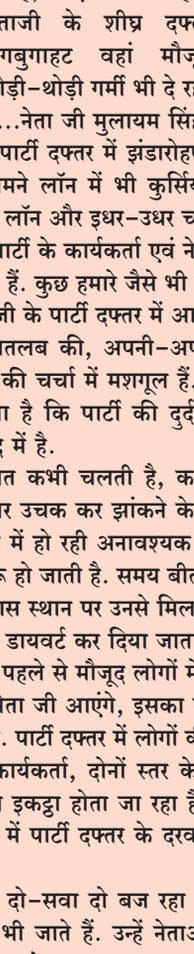

...और सपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं

समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जनता की आशा समाजवादी पार्टी से है. किसान और ग़रीब मानते हैं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं की है. प्रदेश में समाजवादी सरकार की उपलब्धियां भी कम नहीं हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव की चुनौती का एकजुटता से सामना करना है. बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव, विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय, वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव, अहमद हसन, अवधेश प्रसाद, राजेंद्र चौधरी समेत कई नेता मौजूद थे. सपा प्रमुख ने पार्टी पदाधिकारियों को भाजपा की फरेबी राजनीति से सावधान करते हुए कहा कि जनता के बीच झूठे वादों की कलई खुलने लगी है. पार्टी महासचिव अरविंद सिंह गोप ने बैठक में राजनीतिक-आर्थिक प्रस्ताव पेश किए.

> एसपी परेश सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट में औरंगाबाद निवासी और पुलिस द्वारा गिरफ्तार नक्सली कालिका यादव के बयान का हवाला देते हुए लिखा कि राजेश कुमार की हत्या कोई नक्सली घटना नहीं, बल्कि यह पूर्ण रूप से राजनीतिक हत्या है. यह हत्या गया लोकसभा क्षेत्र में राजेश कुमार के बढ़ते प्रभाव के कारण कुछ नक्सली नेताओं को पैसा देकर कराई गई. परेश सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट में अपरोक्ष रूप से इस हत्याकांड में साजिशकर्ता के रूप में राज्य के सत्ता शीर्ष पर बैठे एक राजनेता के नाम का उल्लेख किया था.

सोनभद्र : अपराधियों को पुलिस का खुला संरक्षण

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

ज़िले के चोपन थाना अंतर्गत ग्राम बाड़ी में दबंगों के इशारे पर सैकड़ों की भीड़ ने हमला करके दलित महिला शोभा का घर क्षतिग्रस्त कर दिया. हमले में क़रीब 20 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. आरोप है कि यह घटना स्थानीय दबंग कलवंत अग्रवाल, डॉक्टर मिश्रा, बीडीसी जसौदा, वन विभाग और डाला पुलिस चौकी प्रभारी विजय यादव के इशारे पर अंजाम दी गई. पुलिस ने आपस में मारपीट का मामला दिखाकर घायल महिलाओं को ही जेल भेज दिया. बकौल शोभा, छह फरवरी की सुबह उपद्रवियों की भीड़ ने उसके घर पहुंच कर बिना वजह हमला कर दिया. भीड़ का नेतृत्व बीडीसी जसौदा कर रही थीं. शोभा का कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म करने वाले कलवंत अग्रवाल को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया.

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में दलित–आदिवासियों पर असामाजिक तत्वों का कहर जारी है. उस पर कोढ़ में खाज वाली स्थिति यह कि इलाकाई पुलिस के साथ–साथ आला अफसर तक पीड़ितों की मदद करने के बजाय खनन माफिया को खुला संरक्षण दे रहे हैं. इसके चलते इलाके में पुलिस–प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है. यदि समय रहते उत्पीड़न पर रोक न लगाई गई और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न की गई, तो स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है. जानकारी के अनुसार, ज़िले के चोपन थाना अंतर्गत ग्राम बाड़ी में दबंगों के इशारे पर सैकड़ों की भीड़ ने हमला करके दलित महिला शोभा का घर क्षतिग्रस्त कर दिया. हमले में क़रीब 20 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. आरोप है कि यह घटना स्थानीय दबंग कलवंत अग्रवाल, डॉक्टर मिश्रा, बीडीसी जसौदा, वन विभाग और डाला पुलिस चौकी प्रभारी विजय यादव के इशारे पर अंजाम दी गई. पुलिस ने आपस में मारपीट का मामला दिखाकर घायल महिलाओं को ही जेल भेज दिया. बकौल शोभा, छह फरवरी की सुबह उपद्रवियों की भीड़ ने उसके घर पहुंच कर बिना वजह हमला कर दिया. भीड़ का नेतृत्व बीडीसी जसौदा कर रही थीं. शोभा का कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म करने वाले कलवंत अग्रवाल को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया. आरोप है कि इस हमले के पीछे चोपन थानाध्यक्ष एवं डाला पुलिस चौकी प्रभारी का भी हाथ है. शोभा की शिकायत पर आलाधिकारियों ने जांच तो बैठाई, लेकिन जांचकर्ता अपर पुलिस अधीक्षक ने विरोधियों के पक्ष में रिपोर्ट दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि शोभा के साथ 18 अन्य महिलाओं को भी जेल भेज दिया गया.

हमला यह कहकर किया गया कि शोभा वन भूमि पर काबिज़ है और उसे वहां रहने का कोई हक़ नहीं है. उधर अपर पुलिस अधीक्षक ने यह बयान दिया कि शोभा ने बीडीसी जसौदा से मारपीट की, इसलिए उसके घर पर हमला हुआ. इन दोनों बातों से साफ़ है कि हमला पुलिस और दबंगों की मिलीभगत का नतीजा है, ताकि शोभा को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया जाए. शोभा पिछले दस वर्षों से अपने भू–अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है. शोभा चोपन के क्रशर बेल्ट में मज़दूरी करती है और पास ही अपनी झोपड़ी डालकर रहती थी. उसे वहां से हटाने के लिए खनन माफिया कलवंत अग्रवाल ने 2008 में उसके पति को चोरी के आरोप में जेल भिजवाया और फिर घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वह पुलिस की मिलीभगत से धारा 376 व एससी–एसटी एक्ट में कोर्ट से स्टे ले आया और बेखौफ घूमता रहा. वह शोभा की लड़कियों को भी धमकी देता रहा. दुष्कर्मी कलवंत को गिरफ्तार करने के लिए जून 2014 में चोपन थाने का घेराव किया गया और उसके स्टे को कोर्ट में चुनौती देकर गिरफ्तार कराया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह छूट गया.

ग़ौरतलब है कि इस मामले में सोनभद्र पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बावजूद कलवंत की छह साल तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई. जिस भूमि पर शोभा का घर है, उस पर वनाधिकार क़ानून 2006 के तहत शोभा ने दावा कर रखा है, जो अभी तक लंबित है. वनाधिकार क़ानून लागू कराने के लिए जनपद के दलित–आदिवासी अर्से से संघर्ष कर रहे हैं. इस सिलसिले में शोभा ने एक मोर्चा बनाया और महिलाओं को बड़े पैमाने पर संगठित करके सामंतों, पूंजीपतियों एवं अपराधियों को चुनौती दी. शोभा को पहले से आशंका थी कि किसी भी दिन उस पर जानलेवा हमला हो सकता है. महिलाओं की इस संगठित ताकत को तितर–बितर करने के लिए डाला पुलिस चौकी इंचार्ज की मदद से शोभा को उसके घर से बेदखल करने की साजिश रची गई, जबकि वनाधिकार क़ानून 2006 की धारा 4 की उपधारा 5 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जब भी कोई शख्स इस क़ानून के तहत अपना दावा पेश करता है, तो उसे उसकी भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसका दावा निस्तारित न हो जाए. इस क़ानून की अवमानना के ख़िलाफ़ अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं, क्योंकि यह क़ानून वनाश्रित समुदाय के प्रति हुए अन्याय को समाप्त करने के लिए लाया गया है. लेकिन, प्रशासन और भू–माफिया के सहयोग से आएदिन इस क़ानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. दलित–आदिवासी समुदाय ने डाला पुलिस चौकी प्रभारी विजय यादव, चोपन थानाध्यक्ष एवं अपर पुलिस अधीक्षक शंभू शरण यादव को तत्काल निलंबित करने की मांग की है. इसके अलावा शोभा के घर पर हुए हमले की उच्चस्तरीय जांच, गिरफ्तार 18 महिलाओं की बिना शर्त रिहाई, दुष्कर्मी कलवंत अग्रवाल की गिरफ्तारी, शोभा को घर के नुक़सान के बदले 25 लाख रुपये हर्जाना देने और क्षेत्र में दलित–आदिवासियों के भू एवं वनाधिकार सुनिश्चित करने की मांग भी प्रदेश शासन के समक्ष रखी गई है.■

पूर्व सांसद राजेश कुमार हत्याकांड की सीबीआई जांच की अनुशंसा

कई राजनेताओं की सांस ऊपर–नीचे

सुनील सौरभ

बिहार की राजनीति को अपने बयानों से उथल–पुथल कर देने वाले जीतन राम मांझी की एक अनुशंसा ने सत्ता शीर्ष पर बैठे राजनीतिज्ञों की सांस फुला दी है. वजह यह कि राजनीतिक साजिश के तहत अपने प्रतिद्वंद्वी को रास्ते से हटाने के लिए अपराध का सहारा लेने वाले उक्त राजनेताओं की गर्दन जीतन राम मांझी की इस अनुशंसा से फंसती नज़र आ रही है. सत्ता के बल पर अपने विरोधियों को सबक सिखाने वाले ऐसे राजनीतिज्ञों को जीतन राम मांझी ने भी सबक सिखाने के लिए मुख्यमंत्री पद से हटते–हटते एक ऐसी अनुशंसा कर डाली, जिससे तय है कि बिहार की राजनीति के अपराधीकरण का एक और घिनौना चेहरा सामने आएगा. ग़ौरतलब है कि आज से दस साल पूर्व राज्य के तेजतर्रार पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्या कर दी गई थी. उक्त हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा करके जीतन राम मांझी ने नेता–अपराधी गठजोड़ में शामिल राजनेताओं को बेनकाब करने का रास्ता साफ़ कर दिया. पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्या में बिहार के सत्ता शीर्ष पर बैठे एक बड़े राजनेता का नाम बतौर साजिशकर्ता सामने आया था. राजेश कुमार के परिवारीजन और लोजपा के वरिष्ठ नेता इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग बराबर करते आ रहे थे.

मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी ने राजेश कुमार हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा करके बिहार की राजनीति को आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रभावित करने का प्रयास किया है. यही नहीं, ऐसा करके उन्होंने दलितों की भी सहानुभूति हासिल हासिल कर ली. राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान 22 जनवरी, 2005 को गया के डुमरिया थाना क्षेत्र के मैगरा बाज़ार में चुनाव प्रचार से लौटते समय पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्या कर दी गई थी. उनके साथ तीन सहयोगी भी मारे गए थे. राजेश कुमार इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे. इसे सत्ता और बड़े पुलिस अधिकारियों का दबाव ही कहा जाएगा कि दस वर्षों बाद भी इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच पुलिस नहीं कर पाई. अब तक क़रीब आधा दर्जन जांच अधिकारी बदले जा चुके हैं. घटना के समय मगध के तत्कालीन डीआईजी सुनील कुमार और गया के तत्कालीन एसपी संजय सिंह ने नक्सली वारदात बताकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था. लेकिन, राजेश कुमार के पुत्र एवं पूर्व विधायक कुमार सर्वजीत हर मंच से इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते रहे. जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, तब राजेश कुमार के परिवारीजनों को उम्मीद की एक किरण नज़र आई कि गया निवासी मांझी इस मामले में उन्हें इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे. इससे पहले कुमार सर्वजीत ने 2006 में पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके आलोक में हाईकोर्ट ने एक स्पेशल कोर्ट बहाल कर इस मामले के त्वरित निष्पादन का आदेश दिया था, लेकिन बिहार सरकार और संबंधित विभाग हाईकोर्ट के आदेश को भी ठेंगा दिखाते रहे.

जब दो अप्रैल, 2008 को कड़क आईपीएस के रूप में शुमार परेश सक्सेना बतौर एसपी गया पदस्थापित हुए, तो उन्होंने राजेश कुमार हत्याकांड की जांच अपने स्तर पर और नए सिरे से शुरू कर दी. परेश सक्सेना की रिपोर्ट पर मगध के तत्कालीन डीआईजी अरविंद पांडेय ने भी सहमति दे दी. इससे पहले 2006 में तत्कालीन डीआईजी अरविंद पांडेय ने जांच रिपोर्ट बिहार सरकार को भेजी थी, जिसमें साजिशकर्ता के तौर पर एक राजनेता के नाम का जिक्र था. उस रिपोर्ट को सार्वजनिक तो नहीं किया गया, लेकिन जब सरकार के पास वह रिपोर्ट पहुंची, तो हड़कंप मच गया. एसपी परेश सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट में औरंगाबाद निवासी और पुलिस द्वारा गिरफ्तार नक्सली कालिका यादव के बयान का हवाला देते हुए लिखा कि राजेश कुमार की हत्या कोई नक्सली घटना नहीं, बल्कि यह पूर्ण रूप से राजनीतिक हत्या है. यह हत्या गया लोकसभा क्षेत्र में राजेश कुमार के बढ़ते प्रभाव के कारण कुछ नक्सली नेताओं को पैसा देकर कराई गई. परेश सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट में अपरोक्ष रूप से इस हत्याकांड में साजिशकर्ता के रूप में राज्य के सत्ता शीर्ष पर बैठे एक राजनेता के नाम का उल्लेख किया था. अचानक 23 सितंबर, 2008 को परेश सक्सेना को गया से हटा दिया गया. कुछ समय बाद डीआईजी अरविंद पांडेय का भी तबादला कर दिया गया.

अब दस वर्षों के बाद इस मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा ने बिहार के सत्ता संघर्ष में जदयू की आपसी लड़ाई के बीच एक भूचाल ला खड़ा किया है. राजेश कुमार के पुत्र एवं पूर्व विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि सूबे के दलित मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा करके राजनीतिक हत्या के शिकार बने परिवार के साथ इंसाफ किया. बीते दिनों बोधगया में राजेश कुमार की पुण्य तिथि पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा प्रमुख राम विलास पासवान, केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री राम कृपाल यादव, सांसद सुशील कुमार सिंह, विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह, विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, पूर्व विधायक अवधेश कुमार सिंह और विधायक अनिल कुमार आदि ने हिस्सा लिया. उधर उदय नारायण चौधरी का कहना है कि वह पूर्व सांसद राजेश कुमार की हत्या के मामले में अपना नाम घसीटे जाने से दु:खी हैं. उन्होंने कहा कि उनका चरित्र हनन हो रहा है, सारे आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं. इस साजिश में लगे लोगों के ख़िलाफ़ वह क़ानूनी कार्रवाई करेंगे. चौधरी ने कहा कि सच शीघ्र ही सामने आ जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

शेखावाटी महोत्सव-2015

20 वां शेखावाटी महोत्सव नवलगढ़ में संपन्न हुआ. इस उत्सव में राजस्थान की कला, संस्कृति, खान-पान, रहन-सहन की झलक देखने को मिली. दो दशक पहले इस उत्सव की शुरूआत शेखावटी की कला-संस्कृति को, ग्रामीण खेलों को बचाये रखने के उद्देश्य से की गई थी. यह प्रयास आज भी बदस्तूर जारी है. फोटो जर्नलिस्ट **प्रभात पाण्डेय** की नजर से शेखावटी महोत्सव की एक झलक...

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

अब बिहार, जहां भाजपा की कोई भूमिका नहीं है, वह एक पार्टी के तौर पर तस्वीर में कहीं भी नहीं है. वह वही काम कर रही है, जो कांग्रेस करती थी. यानी पैसे बांटती थी, विधायकों की खरीद-फरोख्त करती थी और शराब बांटकर सत्ता तक पहुंचती थी. अच्छी बात है, उसे ऐसा करने देते हैं. ऐसा करके वह निश्चित रूप से यह चुनाव नीतीश कुमार के हवाले कर देगी. वह विधानसभा चुनाव में जीत नहीं हासिल कर पाएगी. क्योंकि, जो लोग किसी खेमे में नहीं हैं, उन्हें यह कहने में आसानी हो जाएगी कि कांग्रेस और भाजपा में कोई फ़र्क़ नहीं है.

राज्यपाल को अंपायर होना चाहिए, खिलाड़ी नहीं

पिछले साल के आम चुनाव में जीत के बाद भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे पहला झटका लगा है. उसे यहां 70 में से केवल तीन सीटें ही मिल पाईं. भाजपा ने अपने सबसे खराब आकलन में भी इतनी कम सीटों की अपेक्षा नहीं की होगी. उसे आशा थी कि वह बहुमत हासिल कर लेगी. किरण बेदी को मैदान में उतार कर उन्हें ब्रह्मास्त्र के तौर पर पेश किया गया, जैसे वह इतनी लोकप्रिय हैं कि उनके आते ही पार्टी चुनाव स्वीप कर लेगी. बहरहाल, भाजपा को लग रहा था कि वह 36 का आंकड़ा पार कर लेगी, जिसे बाद में संशोधित करके 34 कर दिया गया. भाजपा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एकदम से उसका सफाया हो जाएगा. दिल्ली चुनाव का विस्तृत आकलन बाद में आएगा, जिसमें हार के कई कारण हो सकते हैं. उसके लिए फिलहाल सबसे उपयुक्त कारण यह लग रहा है कि उसका वोट प्रतिशत 30 के आसपास बना हुआ है. ये कांग्रेस के वोट थे, जो आम आदमी पार्टी के खाते में चले गए. यह बहुत ही साधारण तर्क है. चुनावी अंकगणित इतना साधारण नहीं होता, लेकिन हारने वाले को कुछ न कुछ बहाना तो बनाना पड़ता है और जीतने वाले भी अपना कारण बताते हैं. यह सब चलता रहता है, इसलिए इसे यहीं छोड़ते हैं.

अब बिहार पर एक नज़र डालते हैं. बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) को बहुमत हासिल था, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे. इसलिए पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने यह फ़ैसला किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. यह एक ग़लती थी. नीतीश कुमार ने पद त्याग दिया और महादलित वर्ग से संबंध रखने वाले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया. भारतीय संविधान और प्रचलित व्यवस्था के चलते यहां कोई भी पद इतना ताक़तवर होता है कि जो एक बार उस पर स्थापित हो जाता है, वह उसे छोड़ना नहीं चाहता. कहने को तो मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक करते हैं और कैबिनेट फ़ैसले लेती है, लेकिन प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री के पद बहुत शक्तिशाली होते हैं. इसलिए स्वाभाविक रूप से जीतन राम मांझी को सत्ता का चस्का लग गया और वह अब अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं. पार्टी की मंशा यह है कि वह नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, ताकि राज्य की शासन व्यवस्था सही ढंग से चल सके और वह अगला चुनाव सही तरीके से लड़ सकें. अगर मौजूदा सरकार को जारी रखा जाता है, तो यह मुमकिन नहीं हो सकेगा.

और अब क्या हो रहा है? जीतन राम मांझी जिस स्थिति में हैं, उसमें उनका व्यवहार किसी दूसरे नेता की तरह है, जो अपनी पार्टी तोड़ना चाहता है. वह नीतीश समर्थक मंत्रियों को हटाकर, उनके खेमे के विधायकों को मंत्री पद का लालच देकर अपने पक्ष में करना चाहते हैं. यह सामान्य राजनीति है, लेकिन समस्या अंपायर के काम से उत्पन्न होती है. बॉलिंग और बैटिंग करने वाली टीमें अपना-अपना काम करती हैं. अंपायर, जो यहां गवर्नर हैं, को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए. जो एक बार फिर बहुत ही कठिन काम है. हमने पहले भी देखा है कि कैसे एक के बाद एक राज्यपालों ने केंद्र के इशारे पर फ़ैसले लिए हैं. भाजपा वही तरीका अपना रही है, जो कांग्रेस अपनाती थी. उसे मालूम नहीं है कि ऐसा करके वह केवल पांच साल बाद कांग्रेस की जल्द वापसी के लिए रास्ता साफ़ कर रही है. इससे यह ज़ाहिर होगा कि दोनों पार्टियां एक जैसी हैं. भाजपा ने यह कहकर शुरुआत की थी कि वह अलग तरह की पार्टी है और अब ऐसा लग रहा है कि उसका व्यवहार कांग्रेस से भी बदतर है.

जहां तक संविधान के प्रावधानों का सवाल है, तो बिहार के कार्यकारी राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी का चौंकाने वाला बयान आया है. वह कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावले हो रहे हैं. क्या कोई अंपायर ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकता है? अगर हां, तो फिर वह अंपायर बनने के योग्य नहीं है. अगर भाजपा वही पार्टी है, जैसा कि वह खुद को दिखाती है, तो केशरी नाथ त्रिपाठी को फौरन न केवल बिहार, बल्कि बंगाल के राज्यपाल पद (जहां उनकी वास्तविक नियुक्ति है) से भी हटा देना चाहिए. यह बहुत ही दुःखद है. अगर वह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी के लिए तबाही बन जाएंगे. यह सही तरीका नहीं है. राज्यपाल को ऐसे मामलों में खामोश रहना चाहिए. उन्हें अपने पास आने वाले मामलों का ही निपटारा करना चाहिए.

बहरहाल, उन्होंने जीतन राम मांझी से कहा है कि वह 20 फरवरी तक अपना बहुमत सिद्ध करें. उन्हें 13 फरवरी तक का समय दिया जाना चाहिए था. 20 फरवरी तक का समय ज़रूरत से अधिक था. ऐसा करके उन्होंने विधायकों की खरीद-फरोख्त का मौक़ा दिया. हालांकि, यह उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है. अब वह कांग्रेस द्वारा बनाए गए कठपुतली राज्यपालों से कैसे अलग साबित होंगे, जो हमेशा मज़ाक बनते रहे, वह चाहे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रामलाल हों या कोई और. मुझे हैरानी है कि प्रधानमंत्री यह नहीं समझ पा रहे हैं कि नक़ल एक तरह की चापलूसी होती है. अगर भाजपा भारत में अपना शासन बनाए रखना चाहती है, तो उसे अपनी कार्यशैली बदलनी होगी. आप केवल एक साल पहले सत्ता में आए हैं, अभी तक आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया है, जिसका दोष मैं नहीं दूंगा, क्योंकि भारत एक विशाल देश है. जो लोग यह समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी रातोंरात देश को बदल देंगे, उन्हें मायूसी होगी. बड़े देशों में परिवर्तन धीरे- धीरे आता है, लेकिन उसके लिए अच्छे मानक स्थापित करने चाहिए. अब तक उन्होंने दो खराब मानक स्थापित किए. एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर उन्हें किरण बेदी को चुनने का अधिकार है, लेकिन उनको पार्टी का नेता बनाना बहुत ही ग़लत था. कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती थी. कांग्रेस भले ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित न करे, लेकिन वह किसी उधार के रिटायर्ड अधिकारी (जिसके पास कोई राजनीतिक अनुभव न हो) के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी. यह भाजपा के दिवालिएपन की निशानी है, सोच के दिवालिएपन की निशानी है.

अब बिहार, जहां भाजपा की कोई भूमिका नहीं है, वह एक पार्टी के तौर पर तस्वीर में कहीं भी नहीं है. वह वही काम कर रही है, जो कांग्रेस करती थी यानी पैसे बांटती थी, विधायकों की खरीद-फरोख्त करती थी और शराब बांटकर सत्ता तक पहुंचती थी. अच्छी बात है, उसे ऐसा करने देते हैं. ऐसा करके वह निश्चित रूप से यह चुनाव नीतीश कुमार के हवाले कर देगी. वह विधानसभा चुनाव में जीत नहीं हासिल कर पाएगी. क्योंकि, जो लोग किसी खेमे में नहीं हैं, उन्हें यह कहने में आसानी हो जाएगी कि कांग्रेस और भाजपा में कोई फ़र्क़ नहीं है. ऐसा करके आप अरविंद केजरीवाल की बातों को ही सत्यापित करेंगे, जो कहते हैं कि भाजपा एवं कांग्रेस दोनों एक ही हैं, दोनों कॉरपोरेट से पैसे लेती हैं और आम आदमी को लूटती हैं. इन दोनों पार्टियों में सिर्फ़ नाम का फ़र्क़ है. इसलिए अगर आप केजरीवाल को सच साबित करना चाहते है, तो केशरी नाथ त्रिपाठी जो करना चाहते हैं, उन्हें करने दीजिए. वह वही कर रहे हैं, जो गृह मंत्रालय और अमित शाह कराना चाह रहे हैं. लेकिन, भाजपा अगर संवैधानिक तरीके से काम करना चाहती है, कम से कम नरेंद्र मोदी से लोगों की यही अपेक्षा है, तो राज्यपाल को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए. विधानसभा को अपना काम करने दीजिए. जिसे बहुमत होगा, वह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेगा और राज्यपाल को बदल देना चाहिए.

राज्यपाल को क्रिकेट मैच के किसी अंपायर की तरह बीच मैदान में नहीं बोलना चाहिए, जब तक कि उससे अपील न की जाए. यहां एक ऐसा अंपायर है, जो इस खेल को खुद ही खेलना चाहता है. केशरी नाथ त्रिपाठी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और उत्तर प्रदेश में कहीं से चुनाव लड़ना चाहिए. आप एक साथ दो काम नहीं कर सकते. जाहिर है, भाजपा सत्ता में पहली बार अकेले दम पर आई है, उसे सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा. पांच साल का वक्त देखते ही देखते निकल जाएगा. भाजपा जितनी जल्दी चीजों को ठीक से समझ ले, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

जेपी ने कहा था, फिर आना

जेपी की पिछली वर्षगांठ पर अधिकांश लोग यही सोच रहे थे कि वह उनका आख़िरी जन्मदिन है, लेकिन जेपी ने उसके बाद एक साल और गुज़ार दिया. इस गुज़रे वर्ष ने जेपी को अकेलेपन और राजनीतिज्ञों के गुस्से भरे अपमान के कई तोहफे दिए. पिछले दो वर्षों की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जेपी के बारे में यह भ्रम फैला दिया गया कि जेपी अब केवल सत्ताधीशों में दिलचस्पी लेते हैं, आम जनता में नहीं. सच्चाई यह है कि जेपी अपने अंतिम दिनों में गुस्से का केंद्र बने हुए थे, लेकिन उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि उनके प्रति किसका गुस्सा किन कारणों से है.

27 सितंबर, 1979. सुबह सवा आठ के आसपास मैं जेपी के यहां पहुंचता हूं. सुनसान पड़ा था सारा अहाता. नीचे चारमीनार की सिगरेट पीता सुरक्षा कर्मचारी बैठा था, जिसने एक बार तो चौंक कर देखा, पर दूसरे ही क्षण फिर सिगरेट पीने लगा. याद आ गए अचानक चौहत्तर-पचहत्तर के हंगामा भरे दिन. जोश से उफनते युवकों से सारा मुहल्ला चौबीसों घंटे भरा रहता था. जेपी के घर तो मानो मेला ही लगा रहता था. देश के हर कोने से आंदोलनकारी आकर जेपी से मिलने की जिद लेकर बैठ जाते थे. कौन जानता था कि जल्दी ही ऐसा दिन भी आएगा, जब क़दमकुआं का वह प्रभा-स्मृति आंदोलनकारियों की एक आहट के लिए भी तरस जाएगा.

> मैं प्रतिवाद कर उठता हूं कि सवाल किसी पार्टी के पक्ष में बोलने का नहीं है, जेपी को अपना विश्लेषण जनता के सामने रखना चाहिए, जिससे यह साफ़ हो कि जेपी आम जनता के हैं, सत्ताधीशों के नहीं. जेपी लगातार मेरा चेहरा देखते रहे. मैं यह कहकर कि शाम को फिर आऊंगा, बाहर निकल आता हूं. नीचे उतरते हुए मन भरा-भरा सा है.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती हैं कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता हूं, तो देखता हूं कि मार्क्सिस्ट को-ऑर्डिनेशन के तकी रहीम जेपी को उर्दू की कुछ ग़ज़लें सुना रहे हैं. जेपी मेरी ओर देखते हैं, कुछ देर चुप रहकर बोलते हैं, अच्छा संतोष हैं, बैठो-बैठो. तकी रहीम एक और ग़ज़ल सुनाकर चले जाते हैं, तो जेपी अपने सामने की कुर्सी पर आने का इशारा करते हैं. लखनऊ के बारे में जानने की उनकी इच्छा पूरी करता हूं, तभी उनके सचिव सच्चिदानंद इशारा करते हैं कि जेपी थक गए हैं. मैं चुप होकर उठने की कोशिश करता हूं, तो जेपी कहते हैं, चलो अंदर, बातें करेंगे. कमजोरी बहुत है, सहारा लेकर जेपी उठते हैं तथा अंदर बेडरूम में जाकर लेटते हैं.

बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, जब जेपी के पास इस तरह बैठने की बात सोचना भी असंभव लगता था. जेपी की एक से बात ख़त्म नहीं होती थी कि दूसरा हाजिर रहता था. आज मैं अकेला इतनी देर से उनके पास बैठा था. जेपी बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि देश में कहां क्या हो रहा है, इसकी उन्हें जानकारी मिले. अख़बार वह रोज सुनते हैं, लेकिन जो बातें वह जानना चाहते हैं, उन्हें उनके पास कोई नहीं पहुंचाता. मैं घटनाओं के साथ जब उन्हें बताता हूं कि लोग आपसे नाराज़ हैं, तो वह चौंक पड़ते हैं, क्यों, मुझसे क्यों नाराज़ हैं? यह जानने के बाद कि जनता पार्टी ने जिस तरह जनता को एक किनारे छोड़ दिया तथा जिस तरह से निचले स्तर पर जाकर कुर्सी की लड़ाई लड़ी गई, उससे लोग आपातकाल को अब पॉजिटिव रूप में याद करने लगे हैं, जेपी चुपचाप छत की ओर देखने लगते हैं. बोलने में संभवत: मैं और निर्मम हो जाता हूं तथा उनसे कहता हूं कि आंदोलन के दौरान पहली बार पैदा हुए आम आदमी के आत्मविश्वास को जनता सरकार ने बिल्कुल तोड़ दिया है, तो जेपी अपना चेहरा मेरी ओर घुमाते हैं. उनकी आंखों में वही पुरानी चमक दिखाई देती है. कुछ तेज आवाज़ में बोलते हैं, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? बीच में उनके सचिव सच्चिदानंद बोल उठते हैं, आपने कल अटल जी से कहा कि मैं अभी सोचूंगा तथा विचार करूंगा.

मैं प्रतिवाद कर उठता हूं कि सवाल किसी पार्टी के पक्ष में बोलने का नहीं है, जेपी को अपना विश्लेषण जनता के सामने रखना चाहिए, जिससे यह साफ़ हो कि जेपी आम जनता के हैं, सत्ताधीशों के नहीं. जेपी लगातार मेरा चेहरा देखते रहे. मैं यह कहकर कि शाम को फिर आऊंगा, बाहर निकल आता हूं. नीचे उतरते हुए मन भरा-भरा सा है. जेपी का अपने को घायल सिपाही कहना लगातार याद आ रहा है. अभी कुछ देर पहले मैंने उनसे कहा था कि आप ही केवल सफल रहे हैं, बाकी सब असफल, तो जेपी तत्काल बोल उठे, नहीं, नेता भी असफल रहे हैं. क्या कभी इतिहास जयप्रकाश की इस मनोवृत्ति का सही आकलन कर सकेगा कि, मैं उन लोगों में नहीं हूं, जो कमरे में बैठकर नेतृत्व देते हैं. नीचे उतरने पर फिर पाता हूं कि पूरा अहाता सुनसान है तथा वही सुरक्षा कर्मचारी तन्मय होकर विविध भारती सुन रहा है.

> सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता हूं, तो देखता हूं कि मार्क्सिस्ट को-ऑर्डिनेशन के तकी रहीम जेपी को उर्दू की कुछ ग़ज़लें सुना रहे हैं. जेपी मेरी ओर देखते हैं, कुछ देर चुप रहकर बोलते हैं, अच्छा संतोष हैं, बैठो-बैठो. तकी रहीम एक और ग़ज़ल सुनाकर चले जाते हैं, तो जेपी अपने सामने की कुर्सी पर आने का इशारा करते हैं. लखनऊ के बारे में जानने की उनकी इच्छा पूरी करता हूं, तभी उनके सचिव सच्चिदानंद इशारा करते हैं कि जेपी थक गए हैं. मैं चुप होकर उठने की कोशिश करता हूं, तो जेपी कहते हैं, चलो अंदर, बातें करेंगे. कमजोरी बहुत है, सहारा लेकर जेपी उठते हैं तथा अंदर बेडरूम में जाकर लेटते हैं.

शाम को पुन: जेपी के यहां जाता हूं, तो पाता हूं कि अहाता फिर सुनसान है. ऊपर सेवानिवृत्त अफसर रणछोड़ बाबू हैं. कुछ देर बाहर बैठता हूं. जेपी की नर्स आकर पास बैठ जाती है. बताती है कि जेपी को रात में नींद नहीं आती. लगातार दो घंटे भी नहीं सो पाते. कमजोरी कम है, लेकिन ठीक पूरी तरह से नहीं हैं. सुबह मुझसे बात करते हुए अपनी दाईं हथेली लगातार दबाते रहे थे. मेरे साथ गए प्रियदर्शी ने जब उनका हाथ दबाया, तो उन्हें काफी अच्छा लगा था. बेतिया की वह लड़की जेपी के बारे में बोलते-बोलते काफी भावुक हो गई. सचमुच यदि उसके वश में होता, तो वह कुछ भी करके जेपी को ज़रूर अच्छा कर देती. सप्ताह में सोम, बुध और शुक्र को जेपी की डायलिसिस होती है, जो लगभग छह घंटे चलती है. एक-एक बूंद रक्त का शरीर से बाहर आना, साफ़ होना, फिर शरीर में जाना. एक दिन दर्द से बेहाल जेपी बच्चों की तरह फूट-फूटकर रो पड़े, मैं आदमी नहीं हूं क्या, मुझे भी दर्द होता है. ■

क्रमश:

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

जनता की आशाएं धूमिल होने से बचाइए

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक जबरदस्त सच्चाई उजागर की है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान जब यह कहा कि हरेक भारतीय के बैंक खाते में 15 से 20 लाख रुपये आ जाएंगे, यदि देश में काला धन वापस आ जाता है और इसे बार-बार इस तरह प्रस्तुत किया गया कि अगर भाजपा की सरकार आती है, तो हर ग़रीब के बैंक खाते में 15 से 20 लाख रुपये आ जाएंगे. इस स्थिति ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को उत्साहित कर दिया और उन्हें लगा कि अब तक जितनी सरकारें रही हैं, उन्होंने आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन यह पहली सरकार बन रही है, जो हर भारतीय के बैंक खाते में 15 से 20 लाख रुपये देगी. इस बयान से ग़रीब बहुत उत्साहित हुआ और भाजपा को भरपूर समर्थन देने के पीछे उसकी यह आशा भी थी.

अब श्री अमित शाह जी ने कहा है कि यह बयान राजनीतिक बयान था या चुनावी जुमला था. इसका मतलब क्या हम यह मानें कि जितने भी वादे सरकार बनने से पहले भाजपा या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से किए थे, वे सब चुनावी वादे थे या चुनावी जुमले थे, जिनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं और ऐसी बातें वोट लेने के लिए चुनावों में की जाती हैं? अगर सच्चाई यह है तो मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति की एक ऐसी परिभाषा गढ़ रही है, जिसमें सच्चाई सर्वोपरि नहीं है, बल्कि सच्चाई को भटकाने वाली बातें ज़्यादा सच हैं.

इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे कि हर घर को 24 घंटे बिजली, हरेक को घर, हरेक को खाना, जिन्होंने लोकसभा में ब्रह्मास्त्र का काम किया, वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में काम नहीं आए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी किस्मत से पेट्रोल के दाम कम हुए हैं और देश में महंगाई कम हुई है, तो आप किसी बदनसीब को वोट क्यों दें, आप नसीब वाले को वोट दें यानी उनकी पार्टी को वोट दें. उन्होंने अपना चेहरा सामने रखा और कहा कि जो देश का मूड है, वही दिल्ली का मूड है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिसे धरना-प्रदर्शन आता है, उसे धरना-प्रदर्शन का काम दो, जिसे झाड़ू लगाना है, उसे झाड़ू लगाने का काम दो और जिसे सरकार चलानी आती है, उसे सरकार चलाने का काम दो. अब अगर दिल्ली के चुनाव का विश्लेषण करें, तो क्या कहेंगे? क्या हम यह मानें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी बातों को दिल्ली के लोगों ने नकार दिया? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीब वाले से बदनसीब बना दिया? उन्होंने प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को अच्छा शासन चलाने वाला नहीं माना? निष्कर्ष लोग अपनी-अपनी तरह से निकालेंगे, पर इसका एक निहितार्थ तो निकलता है.

निहितार्थ यह निकलता है कि राजनीति में अगर आप विनम्रता नहीं अपनाएंगे, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे. अगर आप राजनीति में कुछ करते हुए नहीं दिखेंगे, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे. और, यह बात मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ़ इशारा करके कह रहा हूं. मुझे नहीं पता कि उन्हें लोग यह बात बता रहे हैं कि नहीं कि उन्होंने जनता के बीच जितनी आशाएं पैदा की थीं, उनसे यह भावना फैल गई थी कि सरकार आते ही काम करना शुरू कर देगी. लेकिन, अब जबकि नौ महीने बीत चुके हैं और सरकार काम करते हुए नहीं दिखाई देती है, बल्कि उसकी जगह यह वाक्य सुनाई देता है कि जब साठ साल में लोगों ने काम नहीं किया, तो हमसे कैसे साठ दिन में काम करने की अपेक्षा की जा रही है, तो इससे लोगों की आशाएं टूटती हैं. अब लोग खुलेआम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ़ बातें ही करते हैं, काम करने की दिशा में एक क़दम भी नहीं बढ़ रहे.

हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने काम की बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हों. हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बदलने का कोई नक्शा दिमाग में रखा हो, पर वह नक्शा पिछले बजट में नज़र नहीं आया और न ही वित्त मंत्री के बजट भाषण में नज़र आया था. वह भाषण, अगर चेहरा हटा दें और नाम बदल दें, तो पुराने वित्त मंत्री पी चिदंबरम का ही भाषण लग रहा था. अब फिर 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है. यह बजट सत्र बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने द्वारा देश में जगाए गए सपने पूरा करने के लिए या देश के उन करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए क्या योजनाएं सामने ला रहे हैं, जिन्होंने उन्हें वोट दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके दल को बड़े पैसे वालों ने वोट ज़रूर दिया होगा, पर उन्होंने वोट से ज़्यादा चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया. पर वह प्रधानमंत्री बनने के लिए काफी नहीं था. प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन लोगों ने वोट दिया, उनमें देश के सत्तर प्रतिशत ग़रीब, किसान, मज़दूर, सड़कों पर रोजाना जीने के लिए जद्दोजहद करने वाले लोग और नौज़वान शामिल थे. ऐसे लोग, जिन्हें यह आशा थी कि भाजपा की सरकार आने के बाद सचमुच उनकी ज़िंदगी में कुछ रोशनी आएगी.

भारतीय जनता पार्टी जोर-शोर से ज़रूर यह प्रचार कर रही है कि लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो गई और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुलेआम कह रहे हैं कि लोग 15 सौ से लेकर 45 सौ रुपये तक, सारा खर्च करने के बावजूद, प्रति माह बचा रहे हैं यानी बैंक में रख रहे हैं. ये सारे बयान इस देश के लोगों के लिए खासे हैरत भरे हैं, क्योंकि लोगों के बैंक खाते में 15 रुपये भी हर महीने जमा नहीं हो रहे हैं, 15 सौ और 45 सौ रुपये तो बहुत दूर की बात है. यह मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो वोट देते हैं और सरकारें बनाते हैं. प्रचार करने से जनता के पेट में रोटी नहीं पहुंचाई जा सकती है. टीवी पर शोर करने से लोगों के घर का अंधेरा नहीं दूर हो पाता. इसके लिए आवश्यक है कि उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव हो, जिन्होंने बडी आशाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा को वोट दिया.

> भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गृह मंत्री की राय के बिना राज्यपाल यह फ़ैसला नहीं करते कि वह पहले अभिभाषण देंगे और फिर विधानसभा में विश्वास मत का परीक्षण होगा. यह तर्क समझ में नहीं आता कि बजट सत्र का महत्व स्वयं राज्यपाल समझते हैं या फिर नहीं समझते. दरअसल, बजट सत्र चाहे लोकसभा का हो या राज्यों के विधान मंडल का हो, उनमें वहां की सरकार का नज़रिया परिलक्षित होता है और सरकार की आर्थिक नीति संबंधी मसौदे को ही राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने अभिभाषण में सामने रखते हैं. बिहार में 20 फरवरी को होने वाले विधान मंडल सत्र में राज्यपाल अभिभाषण देंगे और वह अभिभाषण मौजूदा सरकार यानी जीतन राम मांझी की सरकार द्वारा बनाया गया बजट भाषण होगा. राज्यपाल उसे पढ़ देंगे और उसके बाद विश्वास मत रखा जाएगा.

ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि भाजपा जो ग़लती दिल्ली में कर चुकी है कि उसने जैसे वादे किए, जिस तरह चुनाव प्रचार किया और जो शैली अपनाई, उसका बड़ा नतीजा सिर्फ़ तीन सीटों पर जीत के रूप में आया, बाकी 67 सीटों पर वह चुनाव हार गई. अब वही काम वह बिहार में कर रही है.

भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गृह मंत्री की राय के बिना राज्यपाल यह फ़ैसला नहीं करते कि वह पहले अभिभाषण देंगे और फिर विधानसभा में विश्वास मत का परीक्षण होगा. यह तर्क समझ में नहीं आता कि बजट सत्र का महत्व स्वयं राज्यपाल समझते हैं या फिर नहीं समझते. दरअसल, बजट सत्र चाहे लोकसभा का हो या राज्यों के विधान मंडल का हो, उनमें वहां की सरकार का नज़रिया परिलक्षित होता है और सरकार की आर्थिक नीति संबंधी मसौदे को ही राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने अभिभाषण में सामने रखते हैं. बिहार में 20 फरवरी को होने वाले विधान मंडल सत्र में राज्यपाल अभिभाषण देंगे और वह अभिभाषण मौजूदा सरकार यानी जीतन राम मांझी की सरकार द्वारा बनाया गया बजट भाषण होगा. राज्यपाल उसे पढ़ देंगे और उसके बाद विश्वास मत रखा जाएगा. जीतन राम मांझी अगर विश्वास मत नहीं जीतते हैं, यहां एक बहुत बड़ा अगर है. अगर विश्वास मत नहीं जीतते हैं, तो फिर क्या दूसरा बजट सत्र होगा? आर्थिक नीति का मसौदा, जो नया मुख्यमंत्री बनेगा, उसका होगा? यह सवाल इसलिए है कि क्या इससे एक नया संवैधानिक संकट नहीं खड़ा होने जा रहा है?

क्या राज्यपाल मानते हैं कि जीतन राम मांझी की सरकार निश्चित रूप से विश्वास मत जीतेगी और अगर विश्वास मत जीतेगी, तो उसमें जिस पार्टी के जीतन राम मांझी थे, उसके कितने लोगों को तोड़कर बहुमत बनेगा? क्या यह एक बड़े राजनीतिक संकट को उत्पन्न करने का आधार तो नहीं बन जाएगा?

भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम कहना चाहिए कि वह जीतन राम मांझी का समर्थन करती है और जीतन राम मांझी महादलित समुदाय से आते हैं, जिसका सबसे बड़ा पक्षधर अगर कोई दल इस समय है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है. भारतीय जनता पार्टी को जीतन राम मांझी को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए. और, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं दिखती कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है, तो उसे बिहार में नीतीश कुमार को चुनाव में हराने के लिए बहुत बड़ा अवसर हासिल हो जाएगा. इस राजनीतिक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने महादलितों का जिस तरह समर्थन किया, उसका यह स्वाभाविक परिणाम हो सकता है कि जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी अपना नेता स्वीकार कर बिहार में चुनाव की लड़ाई लड़े.

पर इस सारी चीज में, जिसे राज्यपाल संविधान सम्मत कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी संविधान सम्मत कहती है या जनता दल यूनाइटेड संविधान सम्मत कहता है, कोई भी संविधान की धाराओं और भाषा का उल्लेख नहीं करता. जिस तरह वेद, पुराण और कुरान का नाम लेकर असत्य चलाया जाता है, उसी तरह ही संविधान का नाम लेकर भी असंवैधानिक काम होते हैं. बिहार में एक नया राजनीतिक संकट पैदा होने जा रहा है और यह संकट दोतरफ़ा है. पहला संकट यह कि अगर राज्यपाल जीतन राम मांझी सरकार का दिया हुआ अभिभाषण पढ़ते हैं, तो क्या फिर सत्र स्थगित कर नया बजट सत्र बुलाया जाएगा और फिर वह उद्घाटन भाषण देंगे? और दूसरा यह कि अगर जीतन राम मांझी विश्वास मत जीतते हैं, तो क्या यह दलीय व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास राज्यपाल द्वारा नहीं माना जाएगा? वैसे राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उनके द्वारा लिए गए बहुत सारे फ़ैसले विवादास्पद रहे हैं. बिहार में भी राज्यपाल महोदय ने एक संगीन संवैधानिक विवाद उत्पन्न कर दिया है. मजे की बात यह है कि इस संवैधानिक विवाद का निपटारा भी उन्हें अपने अभिभाषण के बाद विधानसभा में विश्वास मत के शक्ति परीक्षण के बाद करना पड़ेगा. शायद राज्यपाल महोदय ऐसी स्थिति को अपने लिए उपयुक्त मानते हों. लेकिन, अब तक ऐसी स्थिति सिर्फ़ एक बार आंध्र प्रदेश में आई, जिसका हल तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने निकाला था और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक सही फ़ैसला लिया था. अब बिहार विधानसभा के अंदर होने वाले शक्ति परीक्षण में जो संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा, उसका हल राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति शासन लगाकर करते हैं या जीतन राम मांझी को दोबारा शक्ति परीक्षण में विजयी घोषित करते हैं या फिर किसी नए को मुख्यमंत्री बनाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा. लेकिन, राज्यपाल महोदय ने गुत्थी तो उलझा ही दी है और भारतीय जनता पार्टी को एक महादलित नेता चुनने का अवसर मिल गया है, जिसके नेतृत्व में वह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है.

मैं यह फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यह मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि वह जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी का नेता घोषित करे और उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़े. इससे भारतीय जनता पार्टी का अपने वोट और महादलितों के वोट मिलकर नीतीश कुमार को हराने का काम बखूबी करेंगे. ■

editor@chauthiduniya.com

अत्यधिक प्रोटीनयुक्त भोजन नुकसानदेह

मोनिशा भटनागर

आजकल के फिटनेस पसंद लोग, खासकर युवा अपनी डायट में प्रोटीन पर खासा जोर देते हैं. जिम करने और तेजी से वजन कम करने के इच्छुक लोग मेटाबॉलिज्म को काबू में रखने के लिए उच्च प्रोटीन डायट लेना पसंद करते हैं, लेकिन शोधों की मानें तो लंबे समय तक उच्च प्रोटीनयुक्त डायट खाने से दिल, किडनी व हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है

प्रोटीन को मांसपेशियों का भोजन भी कहा जाता है, लेकिन जब मांसपेशियों को आवश्यकता से अधिक प्रोटीन मिलता है, तो उसका प्रभाव बाहरी रूप भले ही न दिखाई दे, लेकिन शरीर के आंतरिक अंगों की कार्यप्रणाली गड़बड़ा जाती है. फिटनेस पसंद लोगों की डायट में प्रोटीन का क्रेज इसी रूप में देखने को मिल रहा है. आसानी से और जल्दी बॉडी बनाने के लिए युवा प्रोटीन सप्लीमेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो अधिक हानिकारक साबित होते हैं.

क्यों हानिकारक है अधिक प्रोटीन

चिकित्सा क्षेत्र में हुए अध्ययन की माने, तो अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन (कुल कैलोरी में 30 फीसदी से अधिक प्रोटीन डायट का भाग) शरीर को नुकसान पहुंचाता है. इससे शरीर में कीटोंस की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि विषैला पदार्थ है. कीटोंस को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है. इस पूरी प्रक्रिया में शरीर से ज्यादा मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है, जिससे डीहाइड्रेशन भी हो सकता है. अधिक व्यायाम करने वालों में ऐसा अधिक होता है. ऐसी डायट को कीटोजेनिक डायट भी कहते हैं, जिससे कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांसों से बदबू आना या दूसरी समस्याएं हो सकती हैं.

किडनी की समस्या और हड्डियों की समस्या, जैसे रूमेटाइड ऑर्थराइटिस से जूझ रहे लोगों को भी उच्च प्रोटीन डाइट से परहेज रखने की सलाह दी जाती है. हमारी किडनी रक्त में प्रोटीन को भी शुद्ध करने का काम करती है. अधिक प्रोटीन डायट लेने से किडनी पर दबाव अधिक पड़ जाता है. शोध यह भी बताते हैं कि एक आयु के बाद उच्च प्रोटीन डायट लेने वालों में यूरिया एसिड बढ़ जाता है. पेशाब में कैल्शियम की मात्रा कम निकलती है. कैल्शियम की यह अतिरिक्त मात्रा किडनी में लंबे समय तक जमने से पथरी का रूप ले सकती है और हृदय पर भी अधिक ज़ोर पड़ता है. प्रोटीन के अवशोषण के लिए अधिक कैल्शियम की आवश्यकता से मांसपेशियों व हड्डियों का कैल्शियम घटने लगता है. जो लोग लंबे समय तक उच्च प्रोटीन डायट के लिए मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हृदय रोगों और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है. इसके अलावा भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से कार्बोहाइड्रेड का सेवन कम हो जाता है, जिससे शरीर को फाइबर कम मिलता है और अन्य पोषक तत्व कम हो जाते हैं. इससे कब्ज की समस्या भी बढ़ जाती है. उच्च प्रोटीन डायट से सूजन भी आ सकती है. इन दिनों जिम इंस्ट्रक्टर छह से आठ अंडे खाने व प्रोटीन सप्लीमेंट्स की सलाह देते हैं, जो बैलेंस्ड डायट नहीं है.

विशेषज्ञों के अनुसार, प्रोटीन के सेवन और हड्डियों के स्वास्थ्य में सीधा संबंध है. अगर कम मात्रा में प्रोटीन का सेवन करेंगे तो शरीर में कैल्शियम का अवशोषण प्रभावित होगा व हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी, जबकि लंबे समय तक हाई प्रोटीन डायट लेने से हड्डियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. पेड़-पौधों से मिलने वाला प्रोटीन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है. इनके सेवन से पशु प्रोटीन की तुलना में कैल्शियम का अवशोषण बेहतर तरीके से होता है. फिटनेस कोच एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बतातें हैं कि प्रोटीनयुक्त सप्लीमेंट्स सेहत के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन स्टेरॉयड युक्त प्रोटीन सप्लीमेंट्स जरूर सेहत को

नुकसान पहुंचाते हैं. शाकाहारी लोग और जो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं या खेलों में सक्रिय रहते हैं, उनके लिये ये सही मात्रा में लेने पर उपयोगी भी हो सकता है, लेकिन अधिक और अनियंत्रित सेवन किडनी और लीवर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है. साथ ही त्वचा पर झुर्रियां आ जाती हैं और रेशेज भी पड़ जाते हैं. शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए सामान्य भोजन खाना बेहतर विकल्प है. दाल, साग, सब्जी, दूध, दही में काफी ताकत होती है. एक्सपर्ट्स युवाओं को भीगे हुए काले चने, भीगी हुई मूंगफली, गुड़, भुने चने, सोयाबीन व सोयाबीन की दाल खाने की सलाह देते हैं. यह सभी पौष्टिक और प्रोटीन सप्लीमेंट्स से कहीं अधिक सुरक्षित हैं.

एथलिट्स, बॉडी बिल्डर्स या वो सभी, जो एक अच्छी बॉडी चाहते हैं, उन्हें अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने या हाई प्रोटीन डायट खाने से पहले इसके दुष्परिणामों से अवगत होने की आवश्यकता है. बिना जाने क्रियेटिन या प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने के बहुत से साइड इफेक्ट हो सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

हिटलर के ख़िलाफ़ जासूसी करते थे क्लॉस

अरुण तिवारी

जासूसों की कहानियों की शृंखला में हम इस बार आपको एक ऐसे जासूस के बारे में बता रहे हैं, जिसने हिटलर की नाक में दम कर दिया था. जर्मनी के ही रहने वाले क्लॉस फुश का जन्म 1911 में हुआ था. उनके पिता जर्मनी में लूथेरियन मिनिस्टर थे और शांति प्रचारक मंडली के सदस्य भी थे. पहले विश्व युद्ध से पहले वे शांति मिशन के अपने दोस्तों से मिलने के लिए इंग्लैंड भी गए थे. क्लॉस जब अपने किशोरावस्था में पहुंचे तो उन्हें बचपन की सभी यादें लगभग ताजा थीं. अपने पिता से बेहद लगाव होने के कारण पिता की सारी स्मृतियां उनके दिमाग में बसी हुई थीं, लेकिन मां को वे लगभग भूल चुके थे. जब वे मात्र दस साल के ही थे, तभी उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी. क्लॉस को अपनी मां के बारे में इतना भी नहीं याद था कि उनकी मौत होने पर उन्होंने स्कूल से छुट्टी भी ली थी या नहीं.

क्लॉस की बड़ी बहन एलिजाबेथ भी शांति प्रचारक थी. उसने अपने जैसे विचार रखने वाले एक दोस्त से शादी कर ली थी, जिससे उनका एक बेटा भी था. नाजियों ने उसकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उसे कई बार जेल की हवा खिलाई थी. 1939 में गेस्टापो द्वारा उसका पीछा किया गया. बचते हुए वह एक पुल पर से कूद गई और सामने से आती एक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई थी. क्लॉस का बड़ा भाई जर्मनी में लॉ स्कूल में पढ़ता था. उसे सियासी हरकतों में शामिल होने का आरोप लगा कर निकाल दिया गया था. इसके बाद उसका ज्यादातर जीवन जेल में ही बीता. क्लॉस के परिवार का जीवन काफी दुखद पस्थितियों में गुजरा था. परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ अलग-अलग समय पर कुछ न कुछ दुर्घटना हुई थी. क्लॉस की छोटी बहन क्रिस्टल को शीजोफ्रेनिया

क्लॉस की बड़ी बहन एलिजाबेथ भी शांति प्रचारक थी. उसने अपने जैसे विचार रखने वाले एक दोस्त से शादी कर ली थी, जिससे उनका एक बेटा भी था. नाजियों ने उसकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उसे कई बार जेल की हवा खिलाई थी. 1939 में गेस्टापो द्वारा उसका पीछा किया गया. बचते हुए वह एक पुल पर से कूद गई और सामने से आती एक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई थी. क्लॉस का बड़ा भाई जर्मनी में लॉ स्कूल में पढ़ता था. उसे सियासी हरकतों में शामिल होने का आरोप लगा कर निकाल दिया गया था. इसके बाद उसका ज्यादातर जीवन जेल में ही बीता.

की बीमारी थी. उसका समय कॉलेज में कम पागलखाने आने-जाने में ज्यादा बीतता था. 1933 में जब क्लॉस जर्मनी से स्विट्जरलैंड जा रहा था, तब नाजियों ने उस पर भी नजर रखी थी. वहां पढ़ाई के दौरान हिटलर के विरोध के लिए क्लॉस ने जर्मन सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली थी. उनके दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि हिटलर की बढ़ती हुई ताकत को सिर्फ यही पार्टी जवाब दे सकती है, लेकिन उन्हें अपनी इस सोच के लिए निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि जब जर्मनी में 1932 में चुनाव हुए तो सोशलिस्ट पार्टी ने हिटलर का ज्यादा विरोध नहीं किया और उसे सत्ता पर आसानी से काबिज हो जाने दिया. पार्टी की ऐसी हरकतों की वजह से क्लॉस खिन्न हो गए और उन्होंने पार्टी का साथ छोड़कर जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली.1933 में रेशटंग जल गया था. हिटलर ने इस अग्निकांड के लिए कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया और पूरे देश में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई. उस समय क्लॉस बर्लिन में थे. उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई और देश से बाहर निकलने में कामयाब हो गए. जर्मनी से भागकर वे फ्रांस पहुंचे. जब से पेरिस पहुंचे तो उस समय उनके पास सिर्फ एक छोटा सा सूटकेस था. उनके पास उनके पिता के दिए हुए कुछ पते भी थे, जो उनके दोस्तों के थे. क्लॉस ने अपने पिता के दोस्तों से संपर्क साधना शुरू किया. इन्हीं लोगों की वजह से वे कुछ दिनों तक आसानी के साथ पेरिस में रह सके, लेकिन वे वहां पर बहुत दिनों तक टिक न सके. उन्होंने इसके बाद इंग्लैंड की तरफ रुख किया और वहीं पर आगे का आशियाना भी जमाने का प्रयास करने की कोशिश की. दरअसल, इंग्लैंड में उनके पिता के शांति मिशन से संबंधित कई दोस्त रहते थे, जिनकी वजह से क्लॉस को वहां किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

क्लॉस फुश ने इंग्लैंड से भौतिकशास्त्र में पीएचडी की और कुछ समय इंग्लैंड के परमाणु बम प्रोजेक्ट में भी काम किया. इस दौरान उसने इंग्लैंड की हथियारों की खोज से संबंधित खुफिया जानकारियां सोवियत रूस को दी, जिसकी बदौलत रूस ने दूसरे देशों से पहले हाइड्रोजन का आविष्कार कर लिया. इंग्लैंड में काम करते समय क्लॉस फुश ही हथियारों से संबंधित अमेरिका और इंग्लैंड की खोजों की जानकारियां रूस पहुंचा दिया करते थे. उन्हें 1943 में अमेरिका भेजा गया, जहां उन्होंने मैनहटन प्रोजेक्ट पर काम किया. इस दौरान उन्होंने अमेरिका के हाइड्रोजन बम बनाने के प्लान की पूरी जानकारी केजीबी को दी. उन्होंने यूरेनियम 235 के उत्पादन का पूरा डाटा भी केजीबी को सौंपा, जिसके दम पर सोवियत रूस ने परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका पर बढ़त बना ली. अमेरिका से वापस 1946 में इंग्लैंड लौटने पर क्लॉस फुश पकड़े गये, जहां उनसे कुछ रूसी जासूसों के नाम उगलवाए गए. इस दौरान उन्हें 14 साल की सजा हुई, लेकिन 9 सालों बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया. क्लॉस फुश ने बाकी की अपनी जिंदगी जर्मनी में बिताई. ■

feedback@chauthiduniya.com

आईएसआईएस ने खोदी अपनी क़ब्र

एक साधारण घटना से निकली चिनगारी कब ज्वाला बनकर बड़ी क्रांति का रूप अख्तियार कर ले, इसका एहसास आईएसआईएस के हाल की हिंसक प्रवृत्तियों से हो जाता है. 2011 में पुलिस के अत्याचार ने एक ऐसी क्रांति फैलाई थी कि पूरी सरकार का तख़्ता पलट हो गया और फिर यह तूफ़ान अरब क्रांति के रूप में कई खाड़ी देशों को अपनी चपेट में ले लिया. अब ऐसा ही कुछ इराक में होने वाला है और आईएसआईएस द्वारा जॉर्डन के एक पायलट को पिंजरे में बंद करके,जिंदा जला कर दर्दनाक तरीके से मारने की घटना आईएसआईएस की तबाही का कारण बनती नज़र आ रही है.

वसीम अहमद

2014 में अलबगदादी इराक के कुछ हिस्से पर क़ब्ज़ा करने के बाद इराक की ज़मीन पर जिस प्रकार से अपना दायरा बढ़ाता जा रहा था, उसको देखते हुए ऐसा लगता था कि अलबगदादी की ताक़त के सामने दुनिया के दिग्गज भी बेबस हैं. जब उसने मूसल के बाद शहर कोबानी पर क़ब्ज़ा कर लिया, उसके बाद तो ऐसा लगने लगा था कि अब यह मिलिटेंट संगठन इराक और सीरिया से बाहर दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में ले लेगा. अलबगदादी बार-बार दावा करता था कि वह यूरोप तक अपनी सरकार क़ायम करेगा. उसकी रफ्तार को रोकने के लिए कोबानी में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अपनी पूरी ताक़त झोंक दी. ताबड़तोड़ हमले हुए, कुछ हद तक आईएसआईएस की रफ्तार को रोका भी गया, लेकिन अमेरिका जिस तरह से दावा कर रहा था, वैसा नहीं हो सका. आईएसआईएस को रोका नहीं जा सका, लेकिन अचानक यह ख़बर आई कि आईएसआईएस के लड़ाके कोबानी खाली कर वापस जा रहे हैं. फिर एक और ख़बर आई कि बशमर्गा की सेना ने मूसल में आईएसआइएस को तीन ओर से घेर लिया है. इस घेराव की वजह से आईएसआईएस का दायरा तंग हो रहा है. उत्तर की ओर से बशमर्गा नैनवी के पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी ताक़त मज़बूत करके मूसल की ओर से बढ़ रहे हैं. पूर्व की ओर से ख़ाज़र, मख़मूर और कोबर और पश्चिम में कसक, आसकी, वाना, तिलअफर और संजर की ओर से बशमर्गी सेना ने घेराबंदी कर दी है. दक्षिण में सलाहुद्दीन अय्यूबी में इराक की सेना मौजूद है. इस सेना ने मूसल को आईएसआईएस से आज़ाद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस आईएसआईएस के बारे में अमेरिका के विदेश मंत्री कहते थे कि आईएसआईएस को ख़त्म करने में सालों लग जाएंगे. ब्रिटेन कहता था कि आईएसआईएस को ख़त्म करना मुश्किल भरा काम है. ऐसे में अचानक ऐसा क्या हुआ कि आईएसआईएस का दायरा सिमटने लगा. इसी को समझने के लिए हमें यूरोप और इस्लामी देशों के युवाओं में आईएसआईएस के प्रति जो भावनाओं हैं, उस पर एक नज़र डालनी होगी.

इस्लामी देशों और यूरोप में एक ऐसा वर्ग मौजूद था, जो आईएसआईएस के लिए नरम रुख़ रखता था. रूस की एक पब्लिक ओपिनियन सर्वे करने वाली कंपनी आइसीएम ने यूरोप के कई देशों के सर्वे के बाद खुलासा किया है कि फ्रांस के 18-24 वर्षों के 16 प्रतिशत युवा आईएसआईएस को लेकर नरम रुख़ रखते थे, जबकि ब्रिटेन के 7 प्रतिशत युवा आईएसआईएस से हमदर्दी रखते थे. अगर इस सर्वे की पृष्ठभूमि देखी जाये तो हैरानी बढ़ जाती है कि आईएसआईएस किस प्रकार से युवाओं को अपनी टीम में शामिल करता था. आईएसआईएस में शामिल होने वाले अधिकतर ऐसे युवा है, जिनका परिवार किसी और देश से पलायन करके वहां बसा हुआ है. आईएसआईएस के लिए एजेंट के रूप में काम करने वाले लोग उन युवाओं से संपर्क करते थे. विशेष रूप से जेलों में बंद युवाओं से वे संपर्क करते थे और ज़मानत पर या सज़ा पूरी कर लेने के बाद जब वह जेल से बाहर आते थे तो इस्लाम के नाम पर उन्हें आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रभावित किया जाता था. ये युवा आसानी से उनका चारा बन जाते थे. अलबग़दादी जानते थे कि ऐसे युवाओं को भटकाकर आसानी से अपनी सेना में शामिल किया जा सकता है. लिहाज़ा उसने फ्रांसीसी युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए कई बार बयान जारी किया. चार्ली एब्दो पर हमले के बाद भी फ्रांसीसी युवाओं के लिए इसका एक प्रभावित करने वाला बयान आया था. आईएसआईएस ने यूरोपीय देशों में सबसे अधिक ध्यान फ्रांस पर इसीलिए दिया था, क्योंकि वहां मुस्लिम युवाओं का एक बड़ा वर्ग जेलों में बंद है. इनमें अधिकतर बेरोज़गार नौजवान हैं. एक राजनीतिक पार्टी यूएमपी के उपाध्यक्ष लैरिब की रिपोर्ट के अनुसार इस समय फ्रांस की जेलों में जितने क़ैदी बंद हैं, उनमें से 60 प्रतिशत क़ैदी मुसलमान हैं, जबकि देश में मुसलमानों की संख्या केवल 7.5 प्रतिशत है, लेकिन जेलों में बंद मुसलमानों की कुल संख्या 40 हज़ार यानी कुल कैदियों का 60 प्रतिशत. ऐसे युवाओं को गुमराह करना आईएसआईएस के लिए बहुत आसान होता है. यही कारण है कि वहां से युवाओं का एक बड़ा वर्ग आईएसआईएस में शामिल हुआ. इन शामिल होने वालों में लड़के और लड़कियां दोनों ही थे. इसी प्रकार जर्मनी के ऐसे युवाओं में भी आईएसआईएस के प्रति नरम रुख़ देखने को मिलता था. जर्मन शासकों का अनुमान है कि लगभग 400 जर्मन युवा आईएसआईएस लड़ाकों में शामिल हैं. इराक के पड़ोसी देश जॉर्डन में भी ऐसे लोगों की अच्छी-ख़ासी संख्या थी, जो आइएसआइएस पर हवाई हमला करने से अपनी सरकार पर ऐतराज़ कर रही थी. यही कारण था कि सहयोगी सेना में शामिल होने के बावजूद जॉर्डन आईएसआईएस पर कम से कम हवाई हमले करता था. यहां तक कि इराक के दो आर-ोपी साजिदा रशावी और ज़दबा करबलावी को गिरफ्तार करने के बावजूद इसे फांसी देने में जॉर्डन संशय में था. सऊदी युवाओं में भी आइएसआइएस के लिए किसी हद तक नरम रुख़ था. अभी दो महीने पहले ही सऊदी अरब के 8 युवा आईएसआईएस की ओर से लड़ते हुए कुर्द सेना के हाथों मारे गये थे. सऊदी गजट के अनुसार, वहां आईएसआईएस इस्लाम के नाम पर अनपढ़ सऊदी नौजवानों को बरग़लाता है. अफगानिस्तान में पूर्व तालिबानी कमांडर अब्दुर्रऊफ आईएसआईएस के लिए नौजवानों की भर्ती करता था. यह भी 2001 से 2006 तक ग्वांतनामो बे जेल में रह चुका था. स्वीडन की कई लड़कियां भाग कर आईएसआईएस में शामिल हो गई थीं. इसके बाद से ही स्वीडन की आंतरिक सुरक्षा की ख़ुफिया संस्था सीबू ने केन्द्र से सिफारिश की थी कि विदेश जाने वाली लड़कियों पर नज़र रखी जाये. स्वीडन इमीग्रेशन ने पिछले वर्ष 20 ऐसे लोगों को पकड़ा था, जिन पर आईएसआईएस में शामिल होने का संदेह था. इस्लाम के नाम पर यूरोप से लेकर खाड़ी देशों तक एक ऐसा वर्ग पाया जाता था, जो आइएसआइएस के लिए नरम रवैया रखता था. वह यह समझता था कि आईएसआईएस इस्लाम का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है,लेकिन जब उसने जॉर्डन के एक पायलट को दर्दनाक मौत दी, जिसको इस्लाम किसी भी तरह से पसंद नहीं करता है, विशेष रूप से जलाकर मारने पर कड़ी पाबंदी है तो आईएसआईएस का जो भ्रम था, वह खुल गया और वही युवा, जो अब तक आईएसआईएस का समर्थन करते थे, अब उसका विरोध करने लगे हैं. इस नफरत का एक असर तो यह हुआ कि नये युवाओं की भर्ती कम हो गई और दूसरा यह कि जो युवा उसके लिए लड़ रहे हैं, वह भी अब असमंजस में हैं कि आख़िर वह किसके लिए लड़ रहे हैं. एक दमनकारी तानाशाह के लिए या इस्लाम के लिए.

जॉर्डन में जो वर्ग आईएसआईएस पर हवाई हमले के ख़िलाफ़ था, उस घटना के बाद वह भी अपनी सरकार पर दबाव बना रहा है कि माज़ कसासबा का बदला लिया जाए. जनता के दबाव के कारण जॉर्डन ने आईएसआईएस के कई ठिकानों पर ताबड़तोड हमले करके इसके 55 से अधिक महत्वपूर्ण लीडरों को मार दिया है. बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि जॉर्डन के शाह का कहना है कि वह कसासबा के ख़ून को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आईएसआईएस को जड़ से उखाड़कर दम लेंगे. आईएसआईएस के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करने के लिए अमेरिका और जर्मनी ने हथियारों की और अधिक खेप इराक भेज दी है, ताकि मोसुल में आईएसआईएस का दायरा अधिक तंग कर दिया जाये. अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने अपने एक बयान में साफ़ कर दिया है कि आईएसआईएस का अत्याचार सिर से ऊंचा हो चुका है, अब इसे ख़त्म करके ही दम लेंगे. ब्रिटेन, जो अब तक आईएसआईएस पर हवाई हमले के मसले में टालमटोल कर रहा था, अब उसने भी कड़ा रुख़ अपना लिया है. चारों ओर से कार्रवाई के कारण आईएसआईएस का दायरा तेज़ी से सिमटता जा रहा है. अब हालत यह है कि जहां एक ओर आईएसआईएस के लड़ाकों की संख्या में कमी हो रही है, वहीं इसकी आमदनी भी कम होती जा रही है. वह अब तक 3 से 5 लाख डॉलर का तेल प्रतिदिन बेचा करता था. तेल का बड़ा भंडार मोसुल के आसपास है, लेकिन अब इसकी ज़मीन तंग होती जा रही है, जिससे आईएसआईएस की आमदनी पर भी गहरा असर पड़ेगा.लिहाज़ा इराक में रक्षा आयोग के सदस्य मौफिक़ अलरबीई कहते हैं कि चारों ओर से घेराबंदी करके सीरिया की ओर से तेल एक्सपोर्ट करने का रास्ता बंद कर दिया गया है. अब ऐसा लगता है कि आईएसआईएस ने जॉर्डन के पायलेट(माज़ कसासबा) को मारकर अपनी क़ब्र खुद खोद ली है. कल तक जिन लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा था, वह भी अब आईएसआईएस को विलेन समझने लगे हैं. इसकी आय कम हो गई है और अमेरिकी सहयोगियों ने अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी हैं. ऐसे में यह कहना उचित होगा कि इराक के बेगुनाहों की बर्बर हत्या करने, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिकी नागरिकों को मौत के घाट उतारते हुए वीडियो जारी करने के कारण आईएसआईएस का हौसला बढ़ा था और वह एक के बाद एक अन्य अत्याचारों की अति कर रहा था. इस पर माज़ कसासबा के ख़ून ने विराम लगा दिया है. माज़ कसासबा को दिसंबर में अलरक़ा के क्षेत्र से उस समय पकड़ा गया था, जब उसका जहाज़ दौलत-इस्लामिया के नियंत्रित क्षेत्र में गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया. इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आईएसआईएस ने वैश्विक मानचित्र पर रक्त पात का नंगा नाच शुरू किया था, उसपर पर्दा जल्द ही गिरने वाला है. आईएसआईएस की कब्र तैयार हो चुकी है, अमन-चैन पसंद देशों को इंतजार है तो बस उसके दफन होने का. ■

feedback@chauthiduniya.com

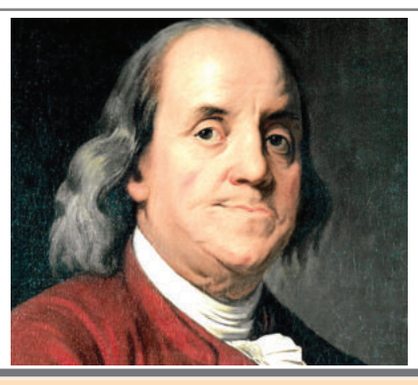

एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई. तभी मैंने आपसे बीस डॉलर लिए थे. उस व्यक्ति ने अपने बीते दिनों के बारे में सोचा तो उसे याद हो आया कि काफी पहले एक लड़का प्रेस में काम किया करता था और एक दिन उसने उसकी मदद भी की थी. इस पर वह बोला, हां मुझे याद आ गया. लेकिन दोस्त, यह तो मनुष्य का सहज धर्म है कि वह मुसीबत में सहायता करे. इन गिन्नियों को अब अपने पास ही रखें. कभी कोई जरूरतमंद आए तो उसे दे दें.

साई भक्तों की चिंताओं को हरते हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

अगर मनुष्य स्वच्छ मन से अपने गुरु में आस्था प्रकट करे, तो उसकी सब चिंताएं दूर हो जाती हैं. साई बाबा ने किस तरह अपने भक्तों की चिंताओं को दूर किया. आइए जानते हैं इस लेख से.

यह सर्वविदित है कि बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के दो ग्रंथ श्रीमद्भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी. काकासाहेब इन ग्रंथों का नियमपूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधि लेने के उपरांत भी वह उसी प्रकार अध्ययन करते रहे. एक समय चौपाटी (मुंबई) में काकासाहेब प्रातःकाल एकनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे. माधवराव देशपांडे (शामा) और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे. ये दोनों ध्यानपूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे. उस समय 11वें स्कंध के द्वितीय अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोर्त्र, द्रुमिल, चमस और कर भाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझायी थी. राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान भी किया था. पठन समाप्त होने पर काकासाहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है. नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति

का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है. अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा. ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए कोई आशा ही नहीं है.

माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी नहीं लगी. वह कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है, जिसके फलस्वरूप ही हमें साई सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया है, तब फिर इस प्रकार का राग अलापना बड़ी निंदनीय बात है. यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है, तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है? माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेहपूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं. क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्रीहरि या गुरु के नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है. तब फिर भय और चिंता का स्थान ही कहां रह जाता है. परंतु फिर भी माधवराव के वचनों से काकासाहेब का समाधान न हुआ. वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही रहे.

दरअसल, यह विचार उनके मस्तिष्क में बार-बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी. एक महाशय, जिनका नाम आनंदराव पाखाडे था, माधवराव को ढूंढते-ढूंढते वहां आ पहुंचे. उस समय भागवत का पठन हो रहा था. श्री पाखाडे भी माधवराव के समीप जाकर बैठ गए और उनसे धीरे-धीरे कुछ वार्ता भी करने लगे. वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे. इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा. अतएव काकासाहेब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है? माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है. कल बाबा ने श्री पाखाडे को जो स्वप्न दिया है, उसे उनसे ही सुनो. उसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है. सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र इच्छा थी और सबसे अधिक काकासाहेब को. सभी के कहने पर श्री पाखाडे अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है. मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूं. पानी मेरी कमर तक है और अचानक जब मैंने ऊपर देखा, तो साईबाबा के श्री-दर्शन हुए. वे एक रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री-चरण जल के भीतर थे. यह दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देखकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ. इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा. मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावुकतापूर्ण शब्दों में कहा कि आनंदराव, बाबा के श्री-चरणों पर गिरो. मैंने उत्तर दिया कि मैं भी यही करना चाहता हूं. परंतु उनके श्री-चरण तो जल के भीतर हैं. अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं. मैं तो निस्सहाय हूं. इन शब्दों को सुनकर शामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपाकर अपने चरण बाहर निकालिए. बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं उनसे तुरंत लिपट गया. बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंदपूर्वक जाओ. घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अब तुम्हारा कल्याण होगा. उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक ज़री के किनारों की धोती मेरे शामा को दे देना, उससे तुम्हें बहुत लाभ होगा.

बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पाखाडे धोती लाए और काकासाहेब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं. कुछ तर्क-वितर्क के पश्चात काका ने दैवी आदेशसूचक पर्चियां निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया. काकासाहेब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो जाता, तो वे काग़ज़ की दो पर्चियों पर स्वीकार-अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते थे और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था, उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे. इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार ही दो पर्चियां लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रख दिया और एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा. बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई, तो वह स्वीकारसूचक पर्ची ही निकली और तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी. इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काकासाहेब का संदेह भी दूर हो गया.

इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी मां अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है. बाबा के इन वचनों को हृदयपटल पर अंकित कर लो. इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता (गुरु) ही सच्चा पिता (सच्चा गुरु) है. दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हों, परंतु अपने गुरु का उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए. संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर, उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार करो. तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है, जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का. सच तो यह है कि बाबा की हर कथा में कुछ न कुछ संदेश छिपा रहता है.■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सभी नाम सार्वजनिक हो

चीफ इंजीनियर यादव सिंह की बेहिसाब काली कमाई के किस्से चटखारे लेकर पूरे देश में सुने जा रहे हैं. आयकर अधिकारियों की टीमों ने जब उनके ठिकाने पर छापा मारा तो उन्हें हीरों, सोने के जेवरात करोड़ो के डिजाइनर कपड़े व भारी मात्रा में नोटों की गड्डियों के साथ ही वहां से उनकी एक निजी डायरी भी मिली थी, जिसमें सैकड़ो ऐसे नेताओं और अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिन्हें यादव सिंह ने कब कितना धन दिया इसका उल्लेख है. यूपी के लोग चाहते हैं कि उक्त डायरी में दर्ज सारे नाम सार्वजनिक किए जाएं.

– राज किशोर पाण्डेय, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

जिहादी जनून

आईएसआईएस पिछले दिनों जापान के 2 पत्रकारों का सर कलम करके व फिर जॉर्डन के एक पायलट को जिन्दा जला कर उनका वीडियो प्रचारित किया. इस्लामिक स्टेट(आईएसआईएस) का जिहादी जुनून अब मानवता के लिए जिहादी राक्षस बन चूका है. पूरा विश्व इस जिहादी राक्षस के जनून से त्रस्त है. पूरी मानवता शर्मसार हो रही है. कोई कहता है कि वे डरपोक नहीं होते वे हथियारों से खेलते हैं, तो क्या दुनिया में घृणा फैला कर दूसरो को भयभीत करके खूनखराबा करते रहने का उनको लाइसेंस मिल गया है? विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय संगठन व एजेन्सियां विश्व को शान्ति व विकास की राह पर चलाने के प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन धार्मिक कट्टरता से उपजते जिहादी राक्षस को ईश्वर की इस सुंदर बनाई पृथ्वी को भी लहुलूहान करके नष्ट करने में भी कोई संकोच नहीं. उनके लिए तो जन्नत का वास्ता व रास्ता ही काफी है. कौन है इसका उत्तरदायी, कौन करेगा इसका प्रायश्चित, कैसे थमेगा यह जलजला, कैसे होगा इसका समाधान, आज इस प्रकार के अनेक प्रश्न चारो ओर उठ रहे है. इसी दर्द से द्रवित संवेदनशील जनमानस अनिश्चितता व भय के एक अप्राकृतिक (मानव निर्मित) वातावरण में जीने को विवश

–विनोद कुमार सर्वोदय, *गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, ई-मेल के द्वारा.*

चुनाव मद्दों पर हो

जब तोप मुकाबिल हो-बहस से असल मुद्दा गायब है (02 फरवरी-08 फरवरी 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से असल मुद्दा गायब है. वह चाहे केजरीवाल हों या किरन बेदी कोई भी दिल्ली की जनता की परेशानी, दिल्ली की जनता नेताओं से क्या चाहती है उस पर कोई नेता बात करने को तैयार नहीं था. दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केवल एक दूसरे पर कीचड़ उछाले जा रहे थे. कौन किस पर कितना अधिक कीचड़ उछाल सकता है. नेताओं को अब जनता से ज्यादा उनको अपनी छवि की चिंता रहती है. नेताओं को व्यक्तित्व के बजाय मुद्दो पर चुनाव लड़ने चाहिए और अब केजरीवाल को जनता से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए.

–पुर्णिमा शर्मा, *पालम, दिल्ली.*

परमाणु समझौता

कवर स्टोरी-भारत-अमेरिका परमाणु समझौता, फ़ायदे में रहा अमेरिका(09 फरवरी-15 फरवरी 2015) पढ़ा. काफी विचोरत्तोक है. शफीक आलम ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि आज जबकि परमाणु ऊर्जा पर आश्रित बड़े उत्पादक देश अपने परमाणु रिएक्टर बंद कर रहे हैं, तो भारत नए रिएक्टर लगाने की होड़ में क्यों लग गया है? यह भी बिल्कुल सही है कि क्या भारत की ऊर्जा की मांग परमाणु ऊर्जा के बगैर पूरी नहीं हो सकती है? परमाणु ऊर्जा संयत्र में दुर्घटना कितनी भायनक हो सकती इससे कोई अंजान नहीं है इसे सरकार भी जानती है. फुकुशिमा सहति कई ऐसे स्थान हैं जो परमाणु ऊर्जा संयत्र में हुई तबाही के लिए जाने जाते हैं. सरकार को बिना परमाणु ऊर्जा सयंत्र के ऊर्जा बनाने के लिए कार्य करना चाहिए. यह लगता है सरकार केवल अमेरिकी दवाब में आकर अमेरिकी और पश्चिमी देशा की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए परमाणु समझौता किया है. इसलिए सरकार को ऐसे खतरनाक समझौतों से बचना चाहिए.

– रमेश सिंह, *वाराणसी, उत्तर प्रदेश.*

ओबामा की भारत यात्रा

चौथी दुनिया समाचर पत्र(09 फरवरी-15 फरवरी 2015) पढ़ा. काफी आकर्षक है. इस अंक में प्रकाशित सभी खबरें प्रभावति करने वाली हैं. पेज-5 पर प्रकाशित फोटो फीचर देखकर बहुत अच्छा लगा, जो हम टीवी और अन्य अखबारों में नहीं देख पाए वह इस समाचार के माध्यम से हमें देखने को मिली. अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा और वो भी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत आना काफी महत्वपूर्ण है, जो चीन और पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास भी कराना है. बराक ओबामा के दौरे से चीन और पाकिस्तान दोनों बोखलाए हुए थे. मोदी का ओबामा को खुद चाय बनाकर देना यह अपने आप में बड़ी बात है और यह भी दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से मजबूत हुए हैं. मोदी नेतृत्व में भारत ने पूरे विश्व में भारत की एक नई छवि पेश की है.

– गौरव ओझा, *बक्सर, बिहार.*

आप की बड़ी जीत

दिल्ली विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित चुनाव परिणाम ने दिखा दिया कि अगर जनता के खिलाफ फैसला लिए जाएंगे, तो आपको वह सबक सिखाएगी. यही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ हुआ, लेकिन दिल्ली में भाजपा के हारने का यही एक कारण नहीं है, कई कारण हैं. भाजपा का दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने का एक कारण नकारात्मक प्रचार भी रहा और दूसरा कारण किरन बेदी को एन वक्त पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना. किरण बेदी को लेकर भाजपा दिल्ली के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी थी. इसलिए भाजपा को अपनी गलतियों को सुधारना होगा और केन्द्र सरकार को जनता से किए गए वादों को पूरा करना होगा.

–ब्रजभूषण यादव, *बक्सर, बिहार.*

कहानी

सबसे बड़ा काम

एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक धनी व्यक्ति की मेज पर बीस डॉलर की सोने की गिन्नी रखते हुए कहा, सर, आपने बुरे समय में मेरी सहायता की थी. उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत के बल पर इतना सक्षम हो गया हूं कि आपका वह कर्ज लौटा सकूं यह सुनकर वह व्यक्ति उन्हें गौर से घूरते हुए बोला, क्षमा कीजिए, पर मैंने आपको पहचाना नहीं. न ही मुझे याद है कि मैंने किसी को बीस डॉलर उधार दिए थे.

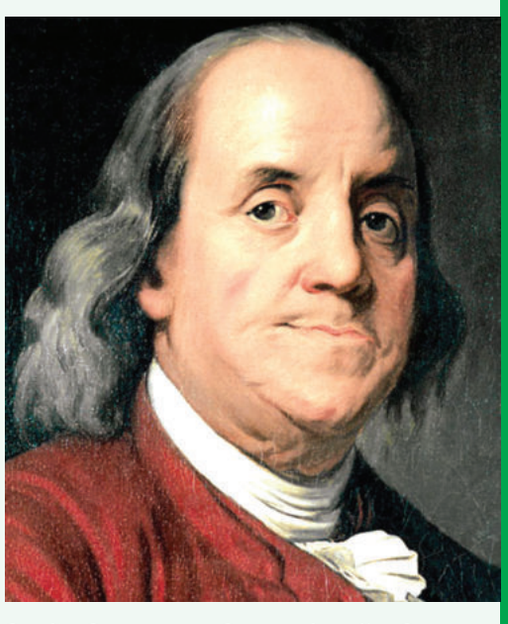

बेंजामिन बोले, मैं उन दिनों एक प्रेस में अखबार छापने का काम करता था. एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई. तभी मैंने आपसे बीस डॉलर लिए थे. उस व्यक्ति ने अपने बीते दिनों के बारे में सोचा तो उसे याद हो आया कि काफी पहले एक लड़का प्रेस में काम किया करता था और एक दिन उसने उसकी मदद भी की थी. इस पर वह बोला, हां मुझे याद आ गया. लेकिन दोस्त, यह तो मनुष्य का सहज धर्म है कि वह मुसीबत में सहायता करे. इन गिन्नियों को अब अपने पास ही रखें. कभी कोई जरूरतमंद आए तो उसे दे दें.

उसकी यह बात सुनकर बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अभिवादन कर वे गिन्नियां अपने साथ लौटा लाए. इसके बाद एक दिन उन्होंने एक जरूरतमंद व्यक्ति को वह गिन्नियां दे दीं. उस व्यक्ति ने बेंजामिन से गिन्नियां लौटाने की बात कही तो वह उससे बोले, दोस्त, जब तुम सक्षम हो जाओगे तो अपने जैसे किसी जरूरतमंद को ये गिन्नियां दे देना. मैं समझूंगा कि मेरी गिन्नियां मुझे मिल गईं. किसी जरूरतमंद की वक्त पर मदद करना ही सबसे बड़ा काम है.■

शिक्षा-संकट में पड़े व्यक्ति की मदद करना ही सबसे बड़ा काम है

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

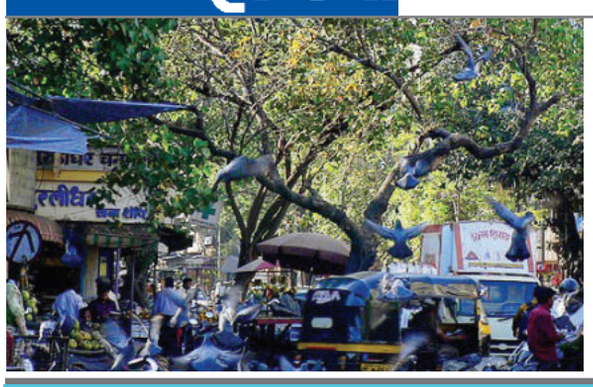

जा-जा आगे बढ़ा, अंग्रेजी मत छांटा इहां, लंबू ने अपने फैले पैर बटोरने की कोई कोशिश नहीं की. अंग्रेज थोड़ी देर उन तीनों को देखता रहा, फिर तिरछा होकर निकल गया. फिर का हुआ, जब तुम अंदर घुसे? मोटा उत्सुक था. जब वह भीतर घुसा, तो उसके मन ने एक बार कहा कि दोस्त वाले मकान में सीढ़ियां दाईं तरफ़ से थीं, लेकिन इस मकान में तो बाईं तरफ़ से हैं. लेकिन, उसने मन को एक चपत लगाई और समझाया कि इतनी मेहनत के बाद उस मकान से मिलता-जुलता मकान उसने खोजा है, अब इसे भीतर से चेक किए बिना जाना बेवकूफ़ी है.

विवादों से परे विमर्श

अनंत विजय

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को मशहूर करने में विवादों की बड़ी भूमिका रही है, चाहे वह समाजशास्त्री आशीष नंदी के पिछड़ों पर दिए गए बयान और आशुतोष के प्रतिवाद से उपजा विवाद हो या फिर सलमान रश्दी के जयपुर आने को लेकर मचा घमासान हो. उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उसी वक्त जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सलमान रश्दी आमंत्रित थे. उस वक्त सियासी दलों ने सलमान रश्दी की भागीदारी और भारत आगमन को भुनाने की कोशिश की थी. मामला इतना तूल पकड़ गया था कि सलमान रश्दी का भारत दौरा रद्द करना पड़ा था. उस विवाद की छाया लंबे समय तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को प्रसिद्धि दिलाती रही. पिछले साल अमेरिकी उपन्यासकार जोनाथन फ्रेंजन ने यह कहकर आयोजकों को झटका दिया था कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसी जगहें सच्चे लेखकों के लिए ख़तरनाक हैं, वे ऐसी जगहों से बीमार और लाचार होकर घर लौटते हैं. दरअसल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साहित्य के साथ-साथ बहुधा राजनीतिक टिप्पणियां भी होती रही हैं. पिछले साल नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने आम आदमी पार्टी के उभार को भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती के तौर पर पेश किया था. वहीं अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के नेत्रहीन लेखक वेद मेहता ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनका प्रधानमंत्री बनना देश के लिए घातक हो सकता है. साहित्य से व्यवसायिकता की राह पर चल पड़े जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को तमाम लटके-झटकों के बावजूद इस बात का श्रेय तो दिया ही जाना चाहिए कि इसने पूरे देश में साहित्यिक उत्सवों की एक संस्कृति विकसित की है, जिससे देश में एक साहित्यिक माहौल बनने में मदद मिली है.

इस बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बगैर किसी विवाद के ख़त्म हुआ. दो साल पहले इस फेस्टिवल की आयोजक नमिता गोखले ने मुझसे कहा था कि उनकी विवादों में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इससे गंभीर विमर्श नेपथ्य में चला जाता है. वह लगातार हो रहे विवादों से चिंतित भी थीं. इस बार उनकी यह चिंता दूर हो गई और जनवरी में ख़त्म हुए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साहित्य की कई विधाओं पर जमकर विमर्श हुआ और लेखकों एवं साहित्य प्रेमियों की भागीदारी रही. हिंदी को भी इस बार मेले में काफी प्रमुखता मिली. फेस्टिवल के पहले दिन हिंदी के वरिष्ठ लेखक विनोद कुमार शुक्ल का सत्र हुआ, जिसमें कविता को लेकर गंभीर बातें हुईं. वैसे भी इन दिनों हिंदी कविता को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं. बड़े पैमाने पर लिखी जा रही हिंदी कविता की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि इस वक्त हिंदी में हज़ार से ज़्यादा कवि सक्रिय हैं. कविता पर आलोचना के इस जाले को साफ़ करने में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हुए विमर्श आने वाले दिनों में काफी मददगार साबित होंगे. वरिष्ठ कवि विनोद कुमार शुक्ल ने कहा कि कविता कुएं का पानी होती है, जिसकी ताजगी हमेशा बरकरार रहती है. उनका मानना था कि बेशक कुएं का पानी एक जगह जमा रहता है, लेकिन जितनी बार उससे पानी बाहर निकालो, तो वह पीने लायक और ताजा होता है. उन्होंने कुएं के पानी की इसी ताजगी से कविता की तुलना करते हुए कहा कि वह भी हर वक्त नई रहती है.

फिल्म गीतकार प्रसून जोशी ने भी कविता को लेकर अपनी राय प्रकट की. प्रसून के मुताबिक, कविताएं मनोरंजन मात्र के लिए नहीं होती हैं. उनके अंदर हमेशा कोई न कोई संदेश छिपा होता है, जो समाज के लिए हितकारी होता है. उन्होंने कविता को सम्मान का हक़दार भी बताया और कहा कि वह चाहे किसी भी ज़ुबान में लिखी जाए, उसे इज्जत बख्शनी चाहिए. उन्होंने कविता और संवाद के फ़र्क़ पर भी विस्तार से प्रकाश डाला. गीतकार जावेद अख्तर ने भी गीतों और उनके चित्रण पर अपनी बात रखी. उनका मानना था कि गीत और उसका चित्रण दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और एक के बगैर दूसरे की कल्पना भी बेमानी है. अगर गीतों का चित्रण प्रभावी नहीं है, तो वह प्रभावोत्पादक नहीं हो सकता है. हिंदी कविता के बारे में उक्त बातें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन जिस तरह से कविता का स्तर लगातार गिर रहा है, उस पर इन कवियों ने कोई बात नहीं की. कविता के जनता से दूर जाने को लेकर और उसके लगातार बदलते फॉर्म पर भी गहन विमर्श होना चाहिए. इसके अलावा एक बेहद दिलचस्प सत्र था स्त्री शक्ति पर, जिसे संचालित कर रहे थे संपादक एवं लेखक ओम थानवी और प्रतिभागी थीं लता शर्मा, अंशु एवं मृदुला बिहारी. यह सत्र शुरुआत में थोड़ा उबाऊ था, पर संचालक के सवालों और सत्र में हिस्सा ले रहे लोगों ने इसे दिलचस्प बना दिया. यह भी दिलचस्प संयोग था कि चर्चा में शामिल सभी लोगों का संबंध राजस्थान से था.

इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए मृदुला बिहारी ने साफ़ कहा कि इन दिनों स्त्री विमर्श के नाम पर देह विमर्श हो रहा है और कुछ नई लेखिकाएं अपनी रचनाओं में देह का वर्णन करती हैं, जो काफी अश्लील होता है. इस चर्चा में ही स्वतंत्रता और स्वाधीनता पर भी बहस हुई, लेकिन वहां मौजूद युवा साहित्य प्रेमियों ने लेखिकाओं को घेर लिया. बहस में हस्तक्षेप करते हुए कहानीकार गीताश्री ने मृदुला बिहारी को कठघरे में खड़ा किया और उनसे अश्लील लेखन करने वाली लेखिकाओं के नाम पूछे, तो सभागार में सन्नाटा छा गया. मृदुला बिहारी सफ़ाई देतीं, इसके पहले ओम थानवी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जो हिंदी के समूल महिला लेखन पर प्रश्नचिन्ह लगाता है. ओम थानवी ने कहा कि सती प्रथा राजस्थान के चेहरे पर एक दाग है, लेकिन इस कुरीति पर स्त्री लेखन ने अब तक आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? स्त्री विमर्श की दुंदुभि बजाने वाली लेखिकाओं को यह सवाल क्यों नहीं मथता है? यह हिंदी साहित्य के स्त्री विमर्श पर एक बड़ा सवाल है.

इसी तरह से एक दिलचस्प सत्र था, सेवन डेडली सिन्स ऑफ ऑवर टाइम. सत्र में हिस्सा ले रहे थे अशोक वाजपेयी, इस्थर डेविड और एमियर मैकब्राइड. इस सत्र में होमी भाभा ने चर्चा में हिस्सा ले रहे लेखकों से उनके पापों के बारे में पूछ लिया. अपनी वाकपटुता के लिए मशहूर अशोक वाजपेयी ने साफ़ कहा कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा पाप कोई नहीं है. इस सत्र में कई मनोरंजक अवधारणाएं भी सामने आईं. एक अन्य सत्र में पौराणिक धर्मग्रंथों और पौराणिक मिथकीय चरित्रों पर लिखने वाले देवदत्त पटनायक ने भी आम जीवन में मिथक की भूमिका पर अपने विचार रखे. सच क्या है, जैसे विराट सवाल से मुठभेड़ करते हुए पटनायक ने कहा कि एक सच वह होता है, जिसे देखा या नापा जा सकता है और दूसरा सच वह होता है, जिसे महसूस किया जाता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विज्ञान यह तो बता सकता है कि आप दुनिया में कैसे आए, लेकिन आप क्यों आए, इस सवाल के सामने जाकर विज्ञान बेबस हो जाता है. दरअसल, सत्रहवीं-अट्ठारहवीं शताब्दी यानी बुद्धिवाद के आरंभिक युग में मिथकों को कपोल कल्पना माना जाता था, परंतु बदलते समय के साथ उन्हें इतिहास या विज्ञान लेखन के पूरक के तौर पर देखा जाने लगा. साहित्य में कई बार ख्यात और अख्यात लोक मिथक का जबरदस्त प्रयोग हुआ है. डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने लेखन में मिथकों और लोक ख्यात संकेतों का प्रयोग किया है.

सोनिया गांधी की फिक्शनालाइज्ड जीवनी के लेखक जेवियर मोरो, फ्लोरेंस नोविल और मधु त्रेहान का सत्र भी विचारोत्तेजक रहा. मोरो ने कहा कि उन्हें यह बहुत रहस्यमयी लगा था कि कैसे इटली के एक गांव की लड़की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे ताकतवर महिला बन गई. इस सत्र में जीवनी लेखन से लेकर मानवीय संबंधों की रचनाओं पर विमर्श हुआ, जिसके केंद्र में नोविल की रचना अटैचमेंट रही. इस रचना में एक युवा लड़की और उसके प्रोफेसर के बीच के प्रेम संबंध को उकेरा गया है. एक और बेहद महत्वपूर्ण सत्र रहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और मिहिर शर्मा की भागीदारी वाला, जिसे अपनी विद्वतापूर्ण टिप्पणियों से युवा अंग्रेजी लेखिका अमृता त्रिपाठी ने नई ऊंचाई दी. विवादों की छाया से दूर इस बार का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मीना बाज़ार सरीखा तो रहा, लेकिन साहित्य पर गंभीर विमर्श ने एक बार फिर से नमिता गोखले के सपने को सच किया. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

विमल चंद्र पांडेय

लोकल

एक दिन लंबू नौकरी खोज कर बहुत दु:खी हो गया, तो उसने किसी सस्ते बार में बैठ कर कुछ पेग मार लिए. दोस्त ने कहा था कि आज वह थोड़ा देर में कमरे पर पहुंचेगा, इसलिए वह थोड़ी देर चाहे, तो इधर-उधर घूम सकता है. उसने समय काटने की गरज से दो-तीन अतिरिक्त पेग मारे और जब देर रात दोस्त के बताए समय पर पहुंचा, तो गड़बड़ हो गई. उसे हालांकि याद था कि दोस्त का कमरा गली नंबर छह में है, लेकिन वह ग़लती से गली नंबर सात में घुस गया. काफी मशक्कत के बाद भी जब उसे दोस्त वाला मकान समझ में नहीं आया, तो उसने दोस्त को फोन लगाने की कोशिश की. दोस्त का फोन स्विच ऑफ था. उसे इस इलाके की सारी गलियां एक जैसी लग रही थीं और नशे की हालत में फोन स्विच ऑफ पाने पर वह इस कदर दबाव में आया कि भूल गया कि गली का नंबर क्या था.

उसने फिर से गली के बाहर निकल कर उस चाय की दुकान से अंदाज़ा लगाना चाहा, जहां वह पिछले चार-पांच दिनों से रोज़ सुबह चाय पी रहा था. लेकिन, उसकी बदकिस्मती देर रात दबे पांव आई थी, क्योंकि चाय की दुकान क्या, एक लाइन से सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं. उसने सिर को झटका और आंखें फाड़ कर एक बार फिर से गली को पहचानने की कोशिश की. उसने अपने मन पर भरोसा किया और उस झूठे आत्मविश्वास पर भी, जो एक बार हां कहने के बाद एक गली की ओर इशारा करने लगा. उस गली के मकानों को देखकर उसे लग रहा था कि यह वही गली हो सकती है. वह मकानों को देखकर अंदाज़ा लगाने लगा कि दोस्त किसमें रहता है. उसे दोस्त पर गुस्सा आया कि उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया और उसकी कोई खोज-ख़बर नहीं ले रहा. आख़िरकार दसेक क़दम चलने के बाद एक काले गेट ने उसे अपनी ओर बुलाया और उसके कानों में कहा कि वह वही गेट है, जिसकी वह तलाश कर रहा है. उसने अपने भीतर के झूठे आत्मविश्वास की पीठ थपथपाई और गेट खोल कर भीतर प्रवेश कर गया.

हम्में इधर-उधर कहीं नहीं जाना. बनारस में जीना है और इहें मरना है, पूछो काहे? लंबू ने आपबीती का अध्याय रोक कर पूछा, जो दरअसल मुख्य बात पर आने से पहले की भूमिका बनाने की कोशिश थी.

क्यों? सवाल आया.

काहे कि यहां आज़ादी है, कहीं बैठो, कहीं उठो, जो मन में आए करो. मुंबई दूसरे देस जइसा है हम लोगों के लिए... उसकी बात से सहमत होने लायक अनुभव दोनों में से किसी के पास नहीं था, क्योंकि एक ने मुंबई की शक्ल ही नहीं देखी थी और एक ने मुंबई में सिर्फ़ गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा की गुफाएं देखी थीं.

आज़ादी वाली बात करने के बाद उसे प्रायोगिक तौर पर समझाने के लिए लंबू ने एक लंबा कश खींचा और अपने दोनों लंबे पांव घाट की सीढ़ी से नीचे लटका कर सीधा फैला दिए. उसके पांव फैलाने से वहां से गुज़र रहे श्रद्धालुओं को परेशानी हुई, लेकिन उसने अपना पांव नहीं हटाया. एकाध गुज़रने वालों ने भृकुटि टेढ़ी कर उसकी ओर देखा, तो उसने बत्तीसी खोल दी. वे समझ गए कि यह लड़का लोकल है और चुपचाप गुज़र गए. इसके बाद उसने दोनों लड़कों की ओर इस उम्मीद भरी नज़र से देखा कि वे अब समझ गए होंगे कि आज़ादी से उसका क्या मतलब था. अचानक एक अंग्रेज उधर से गुज़रा और कैमरे के ज़रिये किसी दृश्य पर ध्यान केंद्रित होने के कारण लड़के के फैले पैर को देख नहीं पाया और टकरा गया.

आज़ादी वाली बात करने के बाद उसे प्रायोगिक तौर पर समझाने के लिए लंबू ने एक लंबा कश खींचा और अपने दोनों लंबे पांव घाट की सीढ़ी से नीचे लटका कर सीधा फैला दिए. उसके पांव फैलाने से वहां से गुज़र रहे श्रद्धालुओं को परेशानी हुई, लेकिन उसने अपना पांव नहीं हटाया. एकाध गुज़रने वालों ने भृकुटि टेढ़ी कर उसकी ओर देखा, तो उसने बत्तीसी खोल दी. वे समझ गए कि यह लड़का लोकल है और चुपचाप गुज़र गए. इसके बाद उसने दोनों लड़कों की ओर इस उम्मीद भरी नज़र से देखा कि वे अब समझ गए होंगे कि आज़ादी से उसका क्या मतलब था.

हे यू..., वह कैमरे से आंखें हटाकर चिल्लाया. उसकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन कैमरे के बाहर जो दुनिया दिखी, उसने उसे बताया कि वह अपने देश से कई समुंदर पार एक अजनबी शहर में है. उसकी आवाज़ की तपिश गायब हो गई और उसने संयत होकर मुस्कराते हुए कहा, प्लीज, सिट प्रॉपरली एंड लेट पीपल गो.

जा-जा आगे बढ़ा, अंग्रेजी मत छांटा इहां, लंबू ने अपने फैले पैर बटोरने की कोई कोशिश नहीं की. अंग्रेज थोड़ी देर उन तीनों को देखता रहा, फिर तिरछा होकर निकल गया. फिर का हुआ, जब तुम अंदर घुसे? मोटा उत्सुक था.

जब वह भीतर घुसा, तो उसके मन ने एक बार कहा कि दोस्त वाले मकान में सीढ़ियां दाईं तरफ़ से थीं, लेकिन इस मकान में तो बाईं तरफ़ से हैं. लेकिन, उसने मन को एक चपत लगाई और समझाया कि इतनी मेहनत के बाद उस मकान से मिलता-जुलता मकान उसने खोजा है, अब इसे भीतर से चेक किए बिना जाना बेवकूफ़ी है.

उसने उस कमरे का दरवाजा खटखटाया, जो उसके हिसाब से उसके दोस्त का था. कमरे में से एक महिला निकली और उसने उससे मराठी में कुछ पूछा, जिसका जवाब उसने लड़खड़ाती हिंदी में दिया. फिर उसका पति निकला. उसने उससे एकाध सवाल पूछे और उसके किसी भी उत्तर से संतुष्ट न होने पर उसे धकेलता हुआ नीचे ले आया. शोर से अगल-बगल के भी लोग जाग गए थे और फिर उस मकान का मालिक उसे गली में थप्पड़ों एवं लातों से मार रहा था. एकाध पड़ोसियों ने उससे मराठी में कुछ पूछा और जब उसने जवाब हिंदी में दिया, तो उन्होंने क्रोधित होकर बिना पूरा मामला जाने एकाध झापड़ रख दिए. लेकिन, कुछ मराठी पड़ोसियों ने ही बीच-बचाव किया और मारने वाले को समझाया कि वह आदमी चोर नहीं हो सकता, क्योंकि चोर आजकल दिन में आते हैं. वह सिर्फ़ शराबी है और काफी चांस है कि जो वह बोल रहा है, उसमें सच्चाई हो. उसने लोगों को बनारस के एक लोकल चैनल का अपना प्रेस कार्ड दिखाया था. तब लोगों ने उसकी सच्चाई पर विश्वास किया था और जाने दिया था. ■

क्रमशः

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

टाटा मोटर्स की हवा से चलने वाली कार

पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है. टाटा मोटर्स हवा से चलने वाली कार जल्द ही लॉन्च करने वाली है. कुछ साल पहले टाटा मोटर्स ने फ्रेंच की एक फर्म मोटर डेवलपमेंट इंटरनेशनल (MDI) के साथ एक ऐसी कार बनाने के लिए साझेदारी की थी जो हवा से चलेगी. लेकिन काफी समय के लिए हवा से चलने वाली कार की बात भी हवा-हवाई हो गई. इस प्रोजेक्ट पर टाटा मोटर्स की ओर से कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब टाटा मोटर्स हवा से चलने वाली कार को 2015 में लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी ने हवा से चलने वाली इस कार का नाम एयरपॉड (airpod) दिया है. टाटा मोटर्स काफी पहले से कम्प्रेस्ड एयर से चलने वाली कार पर काम कर रही है टाटा ने 2007 में एमडीआई के साथ एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत टाटा मोटर्स भारत में एयर कम्पैस्ड इंजन कारें बनाएगा और बेचेगा. ■

एसर ने हाइब्रिड टैबलेट-लैपटॉप लॉन्च किया

एसर ने एक एक हाइब्रिड लैपटॉप कम टैबलेट 2 इन वन लॉन्च किया है. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एसर वन एस1001 नाम का यह हाइब्रिड आपके सस्ते लैपटॉप के बजट में आसानी से आ जाएगा. अच्छी बात यह है कि आप जब चाहें इसे टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कंपनी ने इसके दो मॉडल पेश किए हैं. दोनों मॉडल के बीच करीब दो हजार रुपये का अंतर है. सस्ते वाले मॉडल में 1 जीबी डीडीआर 3 एल और महंगे मॉडल में 2 जीबी डीडीआर 3 एल रैम लगी है. इसे नोटबुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट, डिस्प्ले और टैंट मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. टैबलेट को कीबोर्ड डॉकिंग स्टेशन के साथ जोड़ने पर यह पूरी तरह से नोटबुक बन जाता है और कीबोर्ड सेक्शन में 500 जीबी की हार्ड डिस्क भी लगी है. इस हाइब्रिड टैबलेट में 10 इंच की एचडी स्क्रीन लगी है. 64 बिट का 1.3 गीगाहर्ट्ज इंटेल एटॉम प्रोसेसर, 2एमबी कैशे मेमोरी व इंटेल एचडी ग्राफिक्स इसे बेहतरीन हाइब्रिड बनाते हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस इस हाइब्रिड में 2 मेगापिक्स का मुख्य कैमरा और 0.3 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है. टैबलेट में 32 जीबी की इनबिल्ट मेमोरी है और इसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 32 जीबी और बढ़ाया जा सकता है. इस हाइब्रिड में 6000 एमएएच की बैटरी लगी है जो इंस्टेंट-गो नाम के एक पॉवर सेविंग फीचर के साथ आती है. कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी फीचर के कारण लैपटॉप 16 घंटे में सिर्फ 5 फीसदी बैटरी का ही इस्तेमाल करता है. इस हाइब्रिड में दो 2.0 यूएसबी पोर्ट, 1 एचडीएमआई पोर्ट, वाईफाई और ब्लूटुथ 4.0 जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन भी हैं. इसके 1जीबी मॉडल की कीमत 19,999 रुपये है और 2जीबी मॉडल की कीमत 21,999 रुपये है. ■

12 घंटे का टॉक टाइम देगा लुमिया 435

माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में लुमिया सीरीज का स्मार्टफोन 435 पेश किया है. यह डुअल सिम फोन है और इसका स्क्रीन 4 इंच की है, जो 800 गुणा 480 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. यह 1.2 जीएचजेड डुअल कोर स्नैपड्रैगन 200 से लैस है. यह एक विंडोज फोन है और विंडोज 8.1 पर आधारित है. इसमें 1जीबी रैम है, 8जीबी का ट्रिनल स्टोरेज है, 128 जीबी एक्सपैंडेबल मेमोरी है. इसमें 2एमपी फिक्स्ड फोकस रियर कैमरा है. आडियो की बात करें तो 3.5 मिमी आडियों, एफएम रेडियो है. इसमें अन्य फीचर-3जी, वाई-फाई 802.11, ब्लूटुथ 4.0, जीपीएस जैसी सुविधाए हैं.

इसकी बैटरी 1560 एमएएच है जो 11.7 घंटे टॉक टाइम देती है. इसकी कीमत 5,999 रुपये है. ■

माइक्रोमैक्स लाया 699 रुपये में डुअल सिम फोन

माइक्रोमैक्स कंपनी इस बार फिर दो ऐसे फोन लेकर आई है जिनकी कीमतें हैरान कर देंगी. ये हैं जॉय एक्स1800 और जॉय एक्स1850. खास बात यह है कि पहली बार किसी कंपनी ने प्लास्टिक पाउच में ये फोन उतारे हैं. अब तक मोबाइल फोन डिब्बे में ही आया करते थे. इन दोनों फोन के स्क्रीन 1.77 इंच के हैं और इनका रेजोल्यूशन है 128 गुणा 160 पिक्सल. ये कलर फोन हैं और इनमें डुअल सिम की व्यवस्था है, इनमें एक रियर कैमरा है और उसके अलावा ब्लूटुथ 3.0 तथा 4जीबी इंटरनल मेमोरी है. इसके अलावा इसमें फ्लैशलाइट और एफएम रेडियो भी है. जॉय एक्स1800 में डस्ट प्रूफ कीपैड है. इसकी बैटरी 750 एमएएच की है और इसका टॉक टाइम 3 घंटे का है. जॉय एक्स1850 की बैटरी 1800 एमएएच की है जो 7.5 घंटे का टॉक टाइम देती है. जॉय एक्स1800 की कीमत 699 रुपये है जबकि जॉय एक्स1850 की कीमत 749 रुपये है. ■

नए फीचर्स के साथ सुजुकी का 125 सीसी स्कूटर

सुजुकी मोटर इंडिया प्राइवेड लिमिटेड ने अपने ऑटोमैटिक स्कूटर स्विश 125 को नए फीचर्स के साथ बाजार में उतारा है. 2015 सुजुकी स्विश 125 की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 56,482 रुपये है. नए कॉस्मेटिक बदलाव के साथ सुजुकी स्विश 125 स्कूटर 124 सीसी, एयर कूल्ड इंजन और सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक के साथ काम करता है. सुजुकी स्विश 8.58बीएचपी पर 9.8एनएम का अधिकतम टार्क उत्पन्न करता है. सुजुकी स्विश125 किक स्टार्ट और इलेक्ट्रिक दो विकल्प के साथ मौजूद है. कंपनी ने सुजुकी स्विश 125 को पांच नए रंग ग्लास स्पार्कल ब्लैक, कैंडी एंटरेस रेड/ग्लास स्पार्कल ब्लैक, मैटेलिक सोनिक सिल्वर/ग्लास स्पार्कल ब्लैक, पर्ल ग्लेसियर व्हाइट और मैटेलिक ट्राइटॉन ब्लू/ग्लास स्पार्कल ब्लैक के साथ पेश किया है. ■

स्मार्टफोन से जानें एचआईवी पॉजिटिव हैं या नहीं

शोधकर्ताओं के एक ग्रुप ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसे स्मार्टफोन के साथ अटैच करके कोई भी यह पता लगा सकता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं. इस डिवाइस के जरिए खून की एक बूंद से महज 15 मिनट में तीन संक्रामक बीमारियों का पता लगाया सकता है. कोलंबिया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में इस डिवाइस को तैयार किया गया है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल बिना किसी संग्रहित ऊर्जा के भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए जरूरी ऊर्जा स्मार्टफोन से भी ली जा सकती है. इस डिवाइस को ऑडियो जैक के जरिए स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है. इस डिवाइस के जरिए रवांडा के 96 मरीजों के खून की जांच की गई. इनमें से 97 प्रतिशत लोगों ने इस डिवाइस को इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है. इस डिवाइस के जरिए घर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि आप एचआईवी पॉजिटिव हैं या नहीं. इस डिवाइस की कीमत लगभग 2100 रुपये है. ■

दो करोड़ रुपये की सुपर लग्ज़री कार

लग्ज़री कार निर्माता कंपनी पोर्श ने अपनी नई स्पोर्ट्स कार 911 टार्गा भारत में पेश कर दी है. पोर्श ने कार के दो मॉडल 911 टार्गा और 911 टार्गा 4एस उतारे हैं. 911 टार्गा 4 में 6 सिलेंडर वाला 3.4 लीटर इंजन है और जो 0-100 किलोमीटर की रफ्तार पर केवल 5.2 सेकेंड में दौड़ सकती है. यह अधिकतम 282 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है. जबकि 3.8 लीटर इंजन वाली टार्गा 4एस 4.6 सेकेंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है और अधिकतम 296 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखती है. कंपनी ने कहा कि यह कार दुनिया की आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और ड्राइविंग डायनैमिक्स से लैस है. ये दो मॉडल हैं 911 टार्गा 4 और टार्गा 4एस पहली वाली की कीमत है 1.59 करोड़ रुपये और दूसरी वाली की 1.78 करोड़ रुपये. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

खेलों में मुक्केबाजी के मुक़ाबले काफी गरमागरम माहौल में शुरु हुए. बॉक्सिंग इंडिया की प्रतिबंध लगाने की धमकी के बावजूद 27 राज्यों और सेना ने प्रतियोगिता के लिये पंजीकरण करवाया, लेकिन उन्हें उस वक्त झटका लगा जब नया सॉफ्टवेयर नहीं होने की वजह से स्कोरिंग के पुराने तरीके के तहत मुक़ाबले कराये गये. इस पर मुक्केबाजों ने विरोध करना शुरु कर दिया. मुक्केबाजों का कहना था कि यदि पुरानी स्कोरिंग प्रणाली से मुक़ाबले होने हैं तो उन्हें हेडगार्ड पहनने की अनुमति मिलनी चाहिए.

35वां राष्ट्रीय खेल

नाम बड़े दर्शन छोटे

नवीन चौहान

एक बार फिर राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया. 35 वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 31 जनवरी से 14 फरवरी के बीच केरल में हुआ. इन खेलों में 35 खेलों की विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन हुआ. पदक तालिका में सर्विसेज एक बार फिर पहले स्थान पर रहा. मेजबान केरल ने पिछले राष्ट्रीय खेलों के मुक़ाबले इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि पिछले राष्ट्रीय खेलों में केरल कुल 87 पदकों के साथ सातवें स्थान पर था. हरियाणा ने पिछले खेलों की तरह इस बार भी तीसरे स्थान पर रहा, लेकिन उसे पिछली बार के मुक़ाबले कम पदकों से संतोष करना पड़ा. राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह तिरूवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड स्टेडियम में आयोजित हुआ. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था. उन्हें इन खेलों के लिए ब्रांड ऐंबेस्डर भी बनाया गया था. पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन एक से ज्यादा जिलों में किया गया. खेलों का आयोजन केरल के सात जिलों के 30 विभिन्न स्थानों पर हुआ. 35 वें राष्ट्रीय खेल देश में अबतक आयोजित खेल आयोजनों में से एक है. जहां तकरीबन 10 हजार एथलीटों ने हिस्सा लिया. इस खेल आयोजन में लगभग 611 करोड़ रुपये खर्च हुए. जिसमें से 450 करोड़ रुपये खेलों की मूलभूत संरचना तैयार करने में खर्च किए गए.

धर्मवीर और दुती चंद सबसे तेज भारतीय धावक

राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 100 मी दौड़ हरियाणा के धावक धर्मवीर ने 10.46 सेकेंड में दौड़ पूरी की. उन्होंने 200 मी स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया, उन्होंने 200 मीटर की दौड़ 21.12 सेकेंड में पूरी की. महिलाओं की 100 मी दौड़ ओड़िशा की दुती चंद ने जीती, उन्होंने 11.76 सेकेंड में रेस पूरी की और नया मीट रिकॉर्ड बनाया.

पदक तालिका

राज्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
सर्वसेज	91	33	35	159
केरल	54	47	61	162
हरियाणा	40	40	27	107
महाराष्ट्र	30	43	49	122
पंजाब	27	34	32	93
मध्य प्रदेश	23	27	41	91
मणिपुर	22	21	26	69
तमिलनाडु	16	15	20	51
गुजरात	10	04	06	20
असम	09	05	11	25
कर्नाटक	08	21	24	53
तेलंगाना	08	14	11	33
झारखंड	08	03	12	23
उत्तर प्रदेश	07	31	30	68
प. बंगाल	06	13	30	49
ओडिशा	06	05	04	15
अंडमान निकोबार	06	04	03	13
आंध्र प्रदेश	06	03	07	16
दिल्ली	05	12	29	46
राजस्थान	05	06	07	18
त्रिपुरा	05	00	00	05
जम्मू कश्मीर	03	02	10	15
छत्तीसगढ़	02	04	04	10
उत्तराखंड	01	05	12	18
गोवा	01	03	07	11
चंडीगढ़	01	02	13	16
मिज़ोरम	01	02	03	06
अरुणाचल प्रदेश	01	02	01	04
हिमाचल प्रदेश	01	02	01	04
मेघालय	01	01	01	03
बिहार	00	02	05	07

रिचा मिश्रा,तैराक मध्य प्रदेश (7 पदक)

स्पर्धा	पदक
400 मीटर फ्री स्टाइल	कांस्य
200 मीटर बैक स्ट्रोक	कांस्य
100 मीटर फ्री स्टाइल	स्वर्ण
200 मीटर बटर फ्लाई	स्वर्ण
200 मीटर व्यक्तिगत मेडले	स्वर्ण
400 मीटर व्यक्तिगत मेडले	स्वर्ण
1500 मीटर फ्री स्टाइल	रजत

सजन कुमार,तैराक, केरल (8 पदक)

स्पर्धा	पदक
200 मीटर फ्री स्टाइल	रजत
400 मीटर फ्री स्टाइल	स्वर्ण
1500 मीटर फ्री स्टाइल	स्वर्ण
100 मीटर बटर फ्लाई	स्वर्ण
200 मीटर बटर फ्लाई	स्वर्ण
4 गुणा 100 मीटर रिले	रजत
4 गुणा 100 मीटर रिले फ्री स्टाइल	स्वर्ण
800 मीटर फ्री स्टाइल	स्वर्ण

विश्वस्तरीय खेल गांव

35 वें राष्ट्रीय खेलों के लिये तैयार किया गया खेल गांव खिलाड़ियों को खूब पसंद आया. इसमें केरल की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकों और खिलाड़ियों का स्वागत करते सदभावना दूत सचिन तेंदुलकर के आदमकद पोस्टरों से घिरे कई झोपड़ीनुमा खूबसूरत घर बनाए गए थे. तिरूवनंतपुरम से 20 किमी दूर मेनामकुलम में स्थित खेल गांव में खिलाड़ियों के लिए लगभग सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थीं. इनमें बैंक, फिटनेस केंद्र, फूड कोर्ट के आलवा कॉफी पार्लर, आयुर्वेदिक केंद्र और मनोरंजन केंद्र प्रमुख थे. खेल गांव मेंवेस्ट मैनेजमेंट की शानदार प्रणाली थी. खेल गांव में खेलों के ब्रांड एंबेस्डर तेंदुलकर को हर जगह देखा जा सकता था, खेल गांव में उनके बड़े-बड़े पोस्टर लगे थे. जिनमें उन्हें खिलाड़ियों का स्वागत करते दिखाया गया था. यहां खिलाड़ियों के खाने-पीने के लिए बेहतरीन इंतजाम किया गया था, फूड कोर्ट लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें स्थानीय पकवानों के अलावा वहां देश के विभिन्न क्षेत्रों के पकवान भी उपलब्ध थे. पिछले खेलों तक घटिया सुविधाओं वाले खेल गांव देखने वाले अधिकतर खिलाड़ियों, कोच और अधिकारियों ने इस बार खेल गांव की खुले दिल से तारीफ की. खेल गांवों में आने से पहले अधिकांश खिलाड़ियों को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरह की सुविधायें मिलेंगी. बीस एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले खेल गांव को तैयार करने में 60 करोड़ रुपये की लागत आयी. खेल गांव में पांच हजार से अधिक खिलाड़ियों और अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था थी.■

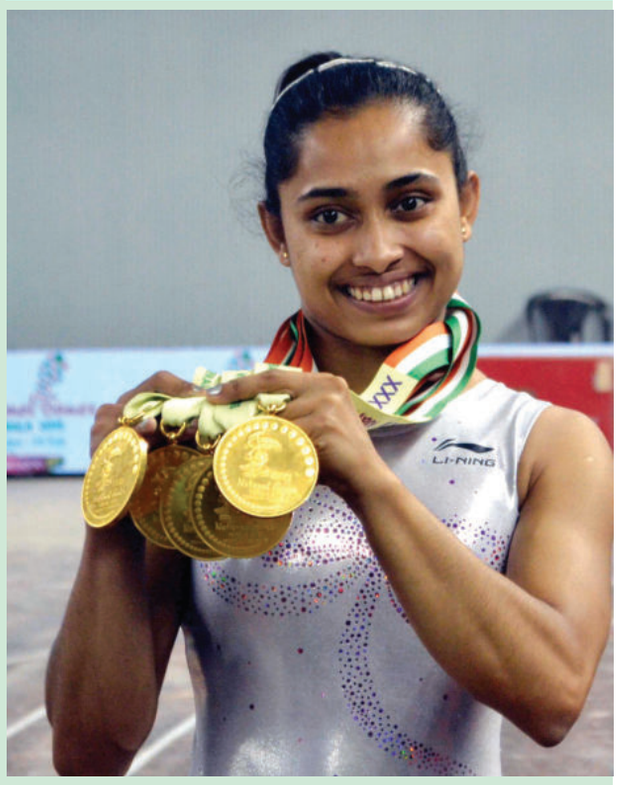

हॉकी इंडिया लीग की तारीखों के नेशनल गेम्स के साथ क्लैश होने की वजह से हॉकी खिलाड़ियों ने हॉकी लीग में खेलने को वरीयता दी. हॉकी टीमें दूसरे दर्जे की टीमों के साथ मैदान में उतरीं.

इस तरह के खेल आयोजनों का कोई फायदा नहीं है केवल समय और संसाधनों की बर्बादी है. जब तक इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को देश के सर्वश्रेष्ठ और विश्वस्तरीय खिलाड़ियों से चुनौती नहीं मिलेगी तो उनके पदक जीतने का कोई महत्व नहीं रह जाता है. जब तक खिलाड़ियों के सामने कड़ी चुनौती न हो, उनके खेल के स्तर में सुधार नहीं हो सकता है. भले ही इन खेलों में कुछ खिलाड़ी अप्रत्याशित रूप से उभरकर सामने आये हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है. खिलाड़ियों ने नये रिकॉर्ड कायम करने की चुनौती अपने सामने नहीं रखी. खेल और खिलाड़ी दोनों को फायदा तब होता है जब पदक के लिए हर स्तर पर कांटे की टक्कर हो. नामी खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को पार करने और उन्हें पछाड़ने की खिलाड़ियों के सामने चुनौती हो. युवा खिलाड़ियों को अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने का अनुभव हासिल हो. यही खिलाड़ियों की वास्तविक पूंजी होती है. यही अनुभव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके काम आता है.

यदि देश में राष्ट्रीय खेलों को लेकर यही रवैया बना रहा तो सीनियर-जूनियर और राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं के बीच का अंतर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने जूनियर स्तर पर जिन खिलाड़ियों का सामना किया उन्हीं के साथ वे सीनियर स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. तीनों स्तरों पर उनके लिए कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है. ऐसे में खिलाड़ियों के खेल के स्तर में सुधार की संभावना न के बराबर या कहें नगण्य हो जाती है. अनुभवी और सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति की वजह से युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों का सामना करना के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, यह सालों से हमारे देश के खिलाड़ियों के ओलंपिक और एशियाई खेलों जैसी विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं में फिसड्डी साबित होने के प्रमुख कारणों में से एक है.

तैराकी इस बार राष्ट्रीय खेलों में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा. खेलों में गोल्डन बॉय के रूप में केरल के तैराक सजन कुमार उभरकर सामने आए. उन्होंने 6 स्वर्ण और दो रजत पदकों के सहित कुल आठ पदक जीते. वह राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहे. महिला वर्ग में मध्यप्रदेश की तैराक रिचा शर्मा ने चार स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक सहित कुल पांच पदक जीते. राष्ट्रीय खेलों में भाग ले रहे तैराकों को सिर्फ पदक ही नहीं मिला बल्कि खिलाड़ियों को विश्व चैंम्पियनशिप का कोटा स्थान भी हासिल करने का मौका मिला था. फिना ने इन खेलों को इस साल के आखिर में होने वाली विश्व चैंम्पियनशिप के क्वालीफायर के रूप में मंजूरी दी थी. इसी वजह से देश की तैराकी के अधिकांश बड़े खिलाड़ी तैराकी स्पर्धाओं में भाग लेते दिखाई दिए. तैराकी में कुल 16 नए नेशनल गेम्स रिकॉर्ड बने.

खेलों में मुक्केबाजी के मुक़ाबले काफी गरमागरम माहौल में शुरु हुए. बॉक्सिंग इंडिया की प्रतिबंध लगाने की धमकी के बावजूद 27 राज्यों और सेना ने प्रतियोगिता के लिये पंजीकरण करवाया, लेकिन उन्हें उस वक्त झटका लगा जब नया सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं होने की वजह से स्कोरिंग के पुराने तरीके के तहत मुक़ाबले कराये गये. इस पर मुक्केबाजों ने विरोध करना शुरु कर दिया. मुक्केबाजों का कहना था कि यदि पुरानी स्कोरिंग प्रणाली से मुक़ाबले होने हैं तो उन्हें हेडगार्ड पहनने की अनुमति मिलनी चाहिए. बॉक्सिंग इंडिया की धमकी का एक असर यह हुआ कि टॉप बॉक्सरों ने खेलों से किनारा कर लिया, जो भी बॉक्सर अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की तैयारियों के लिए शुरू होने वाले नेशनल कैंप के लिए चुने गए थे. विवाद से बचने के लिए विजेंदर सिंह, अखिल, मनोद कुमार, सुमित सिंह, और देवेंद्रो जैसे बॉक्सरों ने इन खेलों में भाग नहीं लिया.

राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली जिम्नास्ट दीपा करमाकर ने राष्ट्रीय खेलों में त्रिपुरा के लिये पांच स्वर्ण पदक जीते. राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट करमाकर ने 2011 में हुए राष्ट्रीय खेलों के प्रदर्शन को दोहराते हुए खुद को फिर से शीर्ष जिम्नास्ट साबित किया. उन्होंने व्यक्तिगत आलराउंड, टेबल वाल्ट, बैलेंसिंग बीम, अनइवन पैरलल बार्स और फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक हासिल किया. जिम्नास्टिक में ही पुरुष वर्ग में एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले आशीष कुमार ने पैरलल बार्स में रजत और टेबल वाल्ट में कांस्य पदक जीता.

जिन देशों में स्पोर्ट्स कल्चर है या कहें जिन देशों में खेलों को प्रमुखता से लिया जाता है वहां राष्ट्रीय खेल देश के स्पोर्ट्स कैलेंडर का प्रमुख हिस्सा होते हैं. प्रशंसक ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की तरह राष्ट्रीय खेलों की प्रतीक्षा करते हैं. देश का हर खिलाड़ी उन खेलों में भाग लेता है जिससे कि देश के जूनियर खिलाड़ियों को उनके अनुभव का फायदा मिल सके. वह अपनी कमियों और मजबूतियों से वाकिफ हो सकें. लेकिन हमारे यहां चार साल में एक बार आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों को अहमियत नहीं देते हैं. इसलिए देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की न तो पहचान हो पाती है और न ही देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो पाते हैं. कुल मिलाकर राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के तरीके में बदलाव करना चाहिए. खेलों को ऐसे समय पर आयोजित किया जाना चाहिए जब कोई बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो रही है. खिलाड़ियों को शासकीय मदद राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने पर ही दी जानी चाहिए. चार साल में एक बार खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों के लिए वक्त निकाल सकते हैं. इससे युवा खिलाड़ियों के खेल के स्तर में निश्चित तौर पर सुधार देखने को मिलेगा■

navinonline2003@gmail.com

बेगम अख्तर

तुम्हें याद हो कि न याद हो...

चौथी दुनिया ब्यूरो

फैज़ाबाद की सरजमीं से दो ऐसी शख्शियतें उभरकर सामने आईं, जिनकी चमक आज भी मंद नहीं पड़ी है. उनमें से एक हकीकत थी और दूसरी अफसाना. लोगों ने अफसाने को हक़ीकत समझ लिया और हक़ीक़त को अफसाना. मिर्ज़ा हादी रुसवा ने अपने उपन्यास में उमराव जान अदा एक ऐसा जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया, कि इसके छपने के बाद ही उमराव जान से मुलाकात करने के लिए लखनऊ में लोगों की भीड़ लगने लगी. लेकिन उमराव हक़ीकत नहीं थीं. उमराव के ऊपर के ऊपर बहुत कुछ लिखा जाता रहा है और आगे भी लिखा जाता रहेगा लेकिन हम यहां उस दूसरी सख्शियत की बात करेंगे जिनके जीवन से ऐसी-ऐसी बातें जुड़ी हैं जिन्हें सुनकर लोगों को लगने लगा कि वह अफसाना हैं ये शख्शियत थी गायिका बेगम अख्तर की.

बेगम अख्तर ने अपनी गायकी से दादरा-ठुमरी को एक ऐसे मुक़ाम पर पहुंचा दिया कि इंतकाल के चार दशक बाद भी वह हिंदुस्तान में संगीत की इन विधाओं का पर्याय बनी हुई हैं. उन्होंने हिंदुस्तान में गज़ल गायकी को एक अलग पहचान दी. दीवाना बनाना है तो मुझे दीवाना बना दे, वरना कहीं किस्मत तुम्हें मुझसा न बना दे, वो जो हममे तुममे करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो,जाने क्यूं तेरे नाम पे आज रोना आया, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुज़र जाती थी, आज कुछ बात थी जो शाम पे रोना आया जैसी गज़लें आज भी सुनने वालों के कानों में शहद घोलती हैं. हमरी अटरिया पे आओ न बालम, ओ राजाजी सौतन के लंबे लंबे बाल, जैसी कई बेहतरीन नज़मों के बल पर उन्होंने दुनियाभर के लोगों का अपना मुरीद बना लिया था.

अख्तरी का जन्म 1914 में फैजाबाद में हुआ था. मां मुस्तरी बाई अदा और गायन दोनों में माहिर थीं. अख्तरी को मुख्य रूप से अता मुहम्मद खां और अब्दुल वाहिद खां से संगीत की तालीम हासिल हुई. उनकी जवानी कलकत्ता में गुजरी जहां, थियेटर में काम करने के अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया. इसी बीच मेगाफोन रिक़ॉर्डिंग कंपनी की वजह से अख्तरी बाई का नाम देश भर में मशहूर होता जा रहा था. लेकिन उनका मन फिल्मों में नहीं लगा. लंबे अरसे बाद सत्यजीत रे के कहने पर उन्होंने फिल्म जलसाघर में शास्त्रीय संगीत गायिका की भूमिका अदा की. 1940 में वह अपनी मां के साथ कलकत्ते से लखनऊ लौट आईं और लखनऊ के चीना बाज़ार मोहल्ले में रहना शुरू किया. इसके बाद उनके पास दूर-दूर की रियासतों से गाने बजाने के न्योते आने लगे.

उनकी शख्शियत में कोई भी चीज फीकी नहीं रही. दुःख, दर्द, मुहब्बत, खुशी, हंसी, हर चीज उनकी जिंदगी में बहुत रंग लेके आती थी. वह शौकीन मिज़ाज थीं, उन्हें अच्छे परफ्यूम और अच्छा खाने-पीने का शौक था. वह बड़ी खुशमिज़ाज, सबके साथ हंसी खुशी से बात करने वाली व्यक्ति थीं. उनकी शख्शियत ऐसी थी कि वह सबसे मोहब्बत करती थीं, रामपुर के नवाब उनके चाहने वालों में से एक थे. वह एक बार उनके चीना बाजार के घर पर ही उनकी गज़लें सुनने पहुंचे. नवाब साहब ने उन्हें एक सतलड़ा दिया था जिसकी आखिरी लड़ी उनके पैरों तक आती थी, नवाब साहब कहा करते थे कि उस सतलड़े में लगे आखिरी हीरे से ज्यादा चमक अख्तरी की मुस्कुराहट में थी. नवाब का लगाव अपनी ओर बढ़ता देख उनसे बचने के लिए अख्तरी ने अपनी नज़रे इश्तियाक अहमद अब्बासी की ओर कीं, इश्तियाक साहब काकोरी के ताल्लुकदार थे. वह लंदन में पढ़े थे और बार एट लॉ थे. दूसर रईसों की तरह उन्हें भी गाने का शौक था. वह ओल्ड शेवरले में बैठकर कोर्ट जाते थे. उनकी वकालत के तो कोई चर्चे मशहूर नहीं थे न ही उनका घर वकालत के बल पर चलता था. उनकी शख्शियत के बहुत से रंग थे, वह बहुत ही चार्मिंग और मनमोहक इंसान थे. वह बच्चों के साथ बच्चों में मिल जाते थे, बड़ों के साथ बड़े हो जाते थे.

बेग़म सइदा रज़ा ने अख्तरी के निकाह में उनकी मदद की थी, वह उस दौरान ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में काम करती थीं. वह इश्तियाक साहब की करीबी थीं. इसलिए अख्तरी एक दिन उनसे मिलने एआईआर लखनऊ पहुंच गईं. उन्होंने उनसे बड़ी ही तहजीब से कहा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं. आप इश्तियाक अहमद अब्बासी को जानती हो, तो उन्होंने कहा

उनके अपने दौर के शायरों के साथ भी बड़े अच्छे रिश्ते थे. बहज़ाद जैसे शायर ने केवल बेग़म अख्तर के लिए ही शेर लिखे, वह उनके दरबारी शायर जैसे थे. वह उन्हीं के साथ चलते थे, ऐसा लगता है कि दीवाना बनाना है जैसी गज़ल उनके लिए ही लिखी गई हो. शकील की बहुत सी ग़ज़लें उन्होंने गाईं हैं लेकिन उनके साथ उनके संबंध बहुत करीबी नहीं थे. ज़िगर मुरादाबादी से जुड़े किस्से वो खुद ही सुनाया करती थीं. क़ैफी आज़मी से उनके अच्छे संबंध थे. एक दूसरे के साथ हंसी मज़ाक करते रहते थे, दोनों के बीच फ्लर्ट भी होता था.

जी हां वह बड़े ही नेक इंसान हैं और हमारे मित्र हैं. उन्होंने उनसे पहली मुलाकात में आगे-पीछे कोई भूमिका बांधे बगैर सीधे अपनी शादी की बात करवाने के लिए कहा. जिस तरह अख्तरी ने उनसे कहा था वैसे ही सइदा रज़ा ने भी उसे लिया, उन्होंने उनसे कहा कि मैं कोशिश कर सकती हूं लेकिन वादा नहीं कर सकती. बहरहाल ऐसे ही कुछ वक्त गुज़र गया. एक हफ्ते बाद बेगम अख्तर फिर से आईं, इस दौरान सइदा ने इश्तियाक को अपने घर बुलाया, और जिस तरह अख्तरी की बात इश्तियाक भाई से कह दी. उस दिन वह बात आई गई हो गई, लेकिन कुछ समय बाद सइदा को मालूम हुआ कि दोनों मिल रहे थे. और दोनों एक दूसरे से वाकिफ थे. अख्तरी चाहती थीं कि उन्हें समाज का कोई मजबूत सहारा मिल जाए, इस तरह के हालात बने और शादी तक पहुंच गई. सइदा, उनके शौहर, अख्तरी, इश्तियाक, मौलवी साहब और नौकर गुलाब को मिलाकर कुल छह लोगों की उपस्थिति में निकाह मुकम्मल हुआ.

बेगम अख्तर के लिए निकाहनामे के साथ पर्दे की जकड़ने आईं. शादी के बाद अख्तरी, बेगम अख्तर हो गईं और उनके लिए गाना हराम. इसके बाद उनकी मां का देहांत हो गया, बेगम अख्तर बीमारी और डिप्रेशन का शिकार हो गईं. इनको इतनी ज्यादा तकलीफ थी, कि वह बिस्तर पर लेट भी नहीं पाती थीं. पेट में दर्द की वजह से उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती थी, उस जमाने में उन्हें दवा लेने की लत पड़ गई थी, वह मोर्फिन के इंजेक्शन लेती थीं लेकिन अचानक से एक दिन उन्होंने इंजेक्शन लेना बंद कर दिया. उन्होंने निकाह के बाद गाने को बहुत मिस किया साथ ही शराब पीनी शुरू कर दी. कुछ समय बाद बेगम अख्तर लोगों से मिलने जुलने भी लगीं थीं, ये सब इश्तियाक साहब के लिए काबिल-ए-एतराज़ था लेकिन उन्होंने इसे बर्दाश्त किया. बाद में उन्होंने उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए उन्हें लखनऊ से बाहर गाने की इज़ाजत दे दी. सात साल लंबी खामोशी के बाद बेगम अख्तर एआईआर लखनऊ के जरिये फिर गाने लगीं. पिंजरे में कैद इस परिंदे को जैसे परवाज की ताकत मिल गई. अब उन्हें रोकने वाला कौन था?

आम तौर पर लोगों को छोटी सी बात बुरी लगती है फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन बेगम अख्तर को छोटी-छोटी बातों से भी बड़ी तक़लीफ होती थी. यदि कहीं थोड़ी सी बदगुमानी या मिस अंडर स्टैंडिंग हो जाये, तो ऐसा लगता कि हक़ीकत में उन्हें किसी ने खंजर मारा हो. वह खंजर उनके सीने में तब चुभा रहता था जब तक कि वह उसका पूरा मज़ा न ले लें. वह इश्क के बगैर भी नहीं रह सकती थीं, वह हमेशा उसकी तलाश में रहती थीं. वो चाहती थीं कि वो इश्क करें और उसकी तकलीफ में डूबी रहें, तब जिंदगी का पूरा फ्लेवर उन तक पहुंचता था. वह कान की बेहद कच्ची थीं, वह धड़ुले से झूठ बोलती थीं. लेकिन वह दिल की बड़ी साफ थीं, उन्होंने लोगों की हर तरह से मदद की. वह जिस महफिल में जाती थीं उस महफिल का माहौल खुद-ब-खुद खुशगवार हो जाता था. इस वजह से उनके सच और झूठ सबको माफ कर दिया जाता था.

वह बहुत छोटी सी जमीन में नज़ाकत के साथ बड़ी बात कर गईं. संगीत से तालल्लुक रखने वाले लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. उस जमाने में ख्याल गाने वाले ठुमरी-दादरी गाते ही नहीं थे. ऐसा करने को वह अपनी तौहीन समझते थे. बेगम अख्तर उसे उठाकर कॉन्सर्ट लेवल पर ले आईं, उनको ठूमरी दादरा गाने की कुदरती देन थी. वह अपने समकालिक गायिकाओं सिद्धेश्वरी देवी और रसूलन बाई से हटकर थीं, हालांकि ठुमरी-दादरा उनकी भी ज़मीन थी. लेकिन उनका म्यूजिकल एटीट्यूड उन्हें सबसे अलग करता था. इस एटीट्यूड में उतनी ही नज़ाकत भी थी. इसका सीधा ताल्लुक उनके व्यक्तित्व से था.

उनके अपने दौर के शायरों के साथ भी बड़े अच्छे रिश्ते थे. बहज़ाद जैसे शायर ने केवल बेग़म अख्तर के लिए ही शेर लिखे, वह उनके दरबारी शायर जैसे थे. वह उन्हीं के साथ चलते थे, ऐसा लगता है कि दीवाना बनाना है जैसी गज़ल उनके लिए ही लिखी गई हो. शकील की बहुत सी ग़ज़लें उन्होंने गाईं हैं लेकिन उनके साथ उनके संबंध बहुत करीबी नहीं थे. ज़िगर मुरादाबादी से जुड़े किस्से वो खुद ही सुनाया करती थीं. क़ैफी आज़मी से उनके अच्छे संबंध थे. एक दूसरे के साथ हंसी मज़ाक करते रहते थे, दोनों के बीच फ्लर्ट भी होता था. फिराक़ गोरखपुरी, के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते थे. बहुत से गुमनाम शायरों की पहचान बेग़म अख्तर की वजह से ही बनी. उन्हें इस बात का कतई गुरूर नहीं था, अगर था भी तो वह कभी दिखाई नहीं देता था. उस दौर में बेगम अख्तर किसी की गज़ल गा दें तो उसके लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी.

आखिरी दिनों में वो शराब और अकेले पन में खो गईं. उन्हें खुद नहीं मालूम था कि क्या चाहिए उन्हें, उन्हें जो चाहिए था वह उन्हें मिल चुका था. पैसा, शोहरत, दोस्त सब कुछ था. 30 अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद में उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से देहांत हो गया. उन्हें लखनऊ के पसंद बाग़ में सपुर्द-ए -ख़ाक किया गया. ऐसा लगता है कि वह आज भी अपने चाहने वालों से पूछ रही हैं कि मुझे याद है सब ज़रा-ज़रा तुम्हें याद हो कि न याद हो...■

feedback@chauthiduniya.com

बेगम अख्तर के जीवन पर आधारित डॉक्युमेंट्री हाय अख्तरी बनाने के अनुभव पर वरिष्ठ पत्रकार और लेखक एस कालीदास की चौथी दुनिया संवाददाता नवीन चौहान से हुई बातचीत के मुख्य अंश...

बेगम अख्तर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की प्रेरणा आपको कहां से मिली?

इसकी शुरूआत एक जर्नलिस्टिक असांइनमेंट के रूप में हुई थी. उनकी 20 वीं पुण्यतिथि का मौका था, मल्लिका पुखराज पाकिस्तान से आईं थीं. सबसे पहले मैंने मल्लिका पुखराज से उनके बारे में बातें करनी शुरू की, इस दौरान मुझे लगा कि बेगम अख्तर की कहानी पर और इंटरव्यू किए जायें. शीला धर हमारी बड़ी शुभचिंतक थीं, मुझे बहुत प्यार करती थीं, मैंने उनसे मुलाकात की, फिर सईदा रज़ा से, शांती हीरानंद से मुलाकात की, उनके तबला वादक मुन्ने खां के साथ बेगम अख्तर के घर में शूटिंग की. इस पूरी कवायद में एक साल लगा. हालांकि शुरूआत डॉक्यूमेंट्री बनाने के इरादे से नहीं की थी, लेकिन जो कहानी तीन मिनट की रिपोर्ट से शुरू हुई उसने एक साल के अंदर डॉक्यूमेंट्री का रूप ले लिया. इसे बनाने में परेशानियां तो नहीं आईं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान मुझे लगा कि इससे पहले ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनी, बननी चाहिए थी, जब मैंने शुरूआत की उस समय तक उनसे जुड़े काफी लोग गुजर चुके थे, बहुत सारी चीजें बिखर चुकी थीं, मैं तो अपने आपको धन्य मानता हूं कि मैंने इतना कर लिया नहीं तो इतना भी नहीं बचता. जो लोग बेगम अख्तर को उनकी जिंदगी में व्यक्तिगत तौर पर जानते थे वे लोग भी जाते रहे, ऐसे में मुझे कुछ लोगों से अच्छे इंटरव्यू और कुछ अच्छी जानकारियां मिलीं.

रामपुर के नवाब से बेगम अख्तर के प्रेम प्रसंग के बारे में डॉक्योमेंट्री में विस्तार से बातचीत नहीं हो सकी, इसकी क्या वजह है?

जी हां, उस दौर में डॉक्योमेंट्री में जो कहा गया है वह ही ज्यादा था, मुझे लग रहा था कि कोई मुझ पर कानूनी कार्रवाई न कर दे. मेरी नवाब साहब के परिवार वालों से जान-पहचान थी, लेकिन मैं उनसे नवाब साहब की एक भी तस्वीर हासिल नहीं कर सका. बड़ी मुश्किल से मुझे उनकी एक तस्वीर मिल पाई. नवाब साहब बेगम अख्तर के साथ से मुतआ (कॉन्ट्रेक्ट मैरिज) करना चाहते थे. इसके लिए वह तैयार नहीं थीं. बेगम रामपुर ने कर्नल जैदी से कहा कि मेरे मियां का पीछा इस औरत से छुड़ाओ. उस दौरान अख्तरी रामपुर में थीं. उन्हें रामपुर से अगवा कर लखनऊ लाया गया. गाड़ी पर काला पर्दा लगाकर कर्नल जैदी खुद ड्राइव करके बेगम अख्तर को रामपुर स्टेट की सीमा के बाहर तक छोड़ आये. रामपुर स्टेट के बाहर अंग्रेजों का राज था. इस तरह की बहुत सारी बातें थीं जो इस डॉक्यूमेंट्री में फिट नहीं बैठती थीं.

शायरों के अलावा म्यूजीशियन्स के साथ उनके कैसे संबंध थे?

उनके शायरों के साथ बहुत याराना रहता था, रसूलन बाई उनके साथ रहीं थीं, और वहीद खां साहब तकरीबन एक साल तक उनके पास रहे. मेरा गिला यही है कि मैं उस जमाने के टेप संभाल कर नहीं रख पाया. उसे उसी कंपनी में छोड़ कर आ गया. वह जमाना डिजिटल नहीं था. बड़े बड़े टेप हुआ करते थे, मैनें शूट तो बहुत किया था, अगर आज वो होते तो एक घंटे से ज्यादा की डॉक्योमेंट्री बन जाती.

सरकार ने उनकी विरासत को संभालने की कोशिश नहीं की, पिछले साल फैज़ाबाद का उनका मकान भी बिक गया. इस पर आपकी क्या राय है?

जी हां, सरकार ने बिलकुल कोशिश नहीं की, लखनऊ का उनका मकान अभी भी है. सलीम किदवई और शांति हीरानंद ने सरकार

से भी और लखनऊ के अमीर लोगों से भी मिन्नतें कीं कि बेगम अखतर की विरासत को बचाया जाए. उनके मकान में अभी भी कोई बंगाली परिवार रहता है, मौका मिलेगा तो वे भी उस मकान को एक-दो करोड़ में बेच देंगे. सरकार ने पिछले साल उनकी याद में सिक्का जारी किया. जो भी काम कर रही है केंद्र सरकार ही कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कोई कोशिश नहीं की. एक तरफ तो मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश कहते हैं कि हम इस्लामिक कल्चर के हित में काम कर रहे हैं लेकिन बेगम अख्तर के मामले में उन्होंने कुछ भी नहीं किया. उत्तर प्रदेश के सियासतदानों और नौकरशाहों की अपनी विरासत के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है.

विरासत को संभालने के लिहाज से क्या यह मुश्किल दौर है?

कोई मुश्किल नहीं है लोगों ने इसे मुश्किल बना दिया है. हम विरासत को संजोने के लिए बहुत थोड़े से पैसों की मांग कर रहे हैं. यूपी सरकार के लिए एक-डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करना कोई बड़ा काम नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार बेगम अख्तर की याद में एक फेस्टिवल आयोजित नहीं कर सकी यह खेद का विषय है.एक तरफ जन्मदिन पर सरकार लाखों खर्च कर रही है लेकिन विरासत को संजोने के नाम पर उनका खजाना खाली है. जो हो रहा है केंद्र सरकार की पहल से हो रहा है, और हम उनकी याद में एक जलसा आयोजित करने वाले हैं.

जब बेगम अख्तर की धरोहरों का यह हाल है तो उनके समकक्ष रहीं सिद्धेश्वरी देवी और रसूलन बाई जैसे लोगों की विरासत का क्या हुआ?

ये दोनों भी बहुत बड़ी गवइया थीं, रसूलन बाई की कोई औलाद नहीं थी, न ही उन्होंने कोई शागिर्द बनाया. इसलिए उन्हें आज कोई पूछने वाला नहीं है. सिद्धेश्वरी देवी की बेटियां हैं वह जरूर उनकी याद में थोड़े-बहुत कार्यक्रम कराती हैं. सरकार और समाज की ओर से भी कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं.

आज ठुमरी-दादरा को कौन से कलाकार आगे लेकर चल रहे हैं.

कई हैं, किसी विशेष का नाम नहीं ले सकता, सभी अच्छा कर रहे हैं. पिछले 10-15 सालों में कई कलाकार आए हैं उत्तर प्रदेश में भी हैं, कोलकाता में भी हैं, मुश्किल की बात यह है ठुमरी-दादरा लोगों की रोजमर्रा की भाषा होती थी, वह भाषा गावों की भाषा होती थी, अब उस भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है लोग सीख के गा रहे हैं, लेकिन वो क्या गा रहे हैं उनमें उसकी समझ नहीं है. उसका वजन समझने के लिए वह भाषा ही नहीं रहेगी तो उसे आगे लेकर कौन चलेगा. इसके लिए जो सांस्कृतिक वातावरण था वह जाता जा रहा है, खास तौर पर भाषा के लेवल पर. अवधी जैसी भाषा खोती जा रही है. औसतन खड़ी बोली वाली हिंदी का उपयोग अब सभी करते हैं. कई बोलियां थीं उनमें कवितायें लिखी नहीं जाएंगी और ग़जल नहीं लिखी जायेंगी तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा. इसका सीधा असर दादरा और ठुमरी पर पड़ेगा.■

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

23 फरवरी–01 मार्च 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बाइस फीसदी वाले मांझी

जीतन राम मांझी के गृह प्रमंडल मगध की बात करें तो महादलितों की यहां जबरदस्त गोलबंदी हुई है.जीतनराम मांझी ने आने वाले विधान सभा चुनाव में जदयू को गंभीर धक्का देने का खाका तैयार कर दिया है. नीतीश कुमार बिहार में जिस महादलित और अति पिछड़ा कार्ड के सहारे अपनी मजबूत पकड़ की बात करते थे उसमें जीतन राम मांझी नें जबरदस्त सेंध लगा दी है. बिहार के अनुसूचित जाति-जनजाति के 22 प्रतिशत की आबादी को जीतन राम मांझी यह समझाने में सफल रहे कि महादलित वर्ग के मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार स्वतंत्र होकर काम नहीं करने दे रहे थे, और जब मैं खुलकर काम करने लगा तो नीतीश कुमार का महादलित प्रेम का ढोंग सामने आ गया.

सरोज सिंह

सत्ता की सियासत में कब और कैसे क्या हो जाएगा इसका अंदाजा लगाने में कभी-कभी राजनीतिक पंडित भी चूक कर बैठते हैं. आज बिहार की सियासत जिस दोराहे पर खड़ी है और जीतन राम मांझी की ताकत जिस कदर बढ़ी है, उसे लेकर अधिकांश लोगों के पूर्वानुमान गलत साबित हुए हैं.

महज साल भर पहले जिस जीतन राम मांझी को बिहार और देश की जनता ठीक से पहचानती तक नहीं थी आज वही मांझी इस समय बिहार की राजनीति की इतनी मजबूत ताकत बन चुके हैं, जो सूबे बिहार की चुनावी राजनीति की दशा और दिशा तय करने की हैसियत रखते हैं. दरअसल जीतन राम मांझी ने दलितों और महादलितों से सीधा संवाद किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वही उनके सही नुमांइदे हैं और बिना किसी की चिंता किए वह उनके पक्ष में काम कर रहे हैं. कहा जाए तो वंचित समाज के लिए लालू प्रसाद ने जो आग़ाज़ किया था उसे सही तरीके से और सही समय पर जीतन राम मांझी ने मंजिल तक पहुंचाने का काम किया. आज पूरे बिहार में जिस तरह महादलितों की गोलबंदी सीएम के पक्ष में हुई है उससे साफ हो गया है कि बाइस फीसदी वाली इस आबादी के नेता जीतन राम मांझी ही हैं. यह आबादी केवल जीतन राम मांझी का इशारा समझ रही है और बिहार के आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में वह जीतन राम मांझी का दिल खोलकर साथ देगी. सीएम के हाथ में ताकत आई तो उन्होंने दलितों और महादलितों के लिए अपनी सरकार का ख़जाना खोल दिया. हर उस योजना को उनके प्रति समर्पित किया, जिससे अंतिम पायदान में बैठा यह समुदाय कुछ सीढ़ी आगे बढ़ सके. यही वजह रही कि कल तक लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की बात सुनने और समझने वाला यह वर्ग आज पूरी तरह जीतनराम मांझी के पीछे गोलबंद हो चुका है.

जीतन राम मांझी के गृह प्रमंडल मगध की बात करें तो महादलितों की यहां जबरदस्त गोलबंदी हुई है.जीतनराम मांझी ने आने वाले विधान सभा चुनाव मे जदयू को गंभीर धक्का देने का खाका तैयार कर दिया है. नीतीश कुमार बिहार में जिस महादलित और अति पिछड़ा कार्ड के सहारे अपनी मजबूत पकड़ की बात करते थे उसमें जीतन राम मांझी नें जबरदस्त सेंध लगा दी है. बिहार के अनुसूचित जाति-जनजाति के 22 प्रतिशत की आबादी को जीतन राम मांझी यह समझाने में सफल रहे कि महादलित वर्ग के मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार स्वतंत्र होकर काम नहीं करने दे रहे थे, जब खुलकर काम करने लगे तो नीतीश कुमार का महादलित प्रेम का ढोंग सामने आ गया. पूरे बिहार, खासकर मगध, के महादलितों में यह बात बैठ गयी कि नीतीश कुमार सिर्फ महादलितों के वोट बैंक का उपयोग करना चाहते थे, महादलितों का विकास नहीं. इसी बात पर मगध के पांच जिलों के 26 विधान सभा क्षेत्रों के महादलित अब जीतनराम मांझी के साथ खड़े हैं. इस बात का पता तब चला जब जीतनराम मांझी को मुख्यमत्री पद से हटाये जाने की घोषणा किये जाने के बाद मगध के सभी पांच जिलों में महादलितों के सभी संगठनों ने एकजुट होकर नीतीश कुमार और शरद यादव के खिलाफ रैली निकाली तथा जीतनराम मांझी को एकमात्र नेता माना. जिला व अनुमंडल मुख्यालय में निकाले गये जुलूस में महादलितों में इस बात का आक्रोश था कि नीतीश कुमार ने साजिश कर महादलितों को बेइज्जत किया है. मगध की करीब एक करोड़ आबादी में महादलितों का करीब 20-22 प्रतिशत हिस्सा है. ऐसे में बिहार मे होने वाले विधान सभा चुनाव में मगध की 26 सीटों पर जदयू को महादलितों के वोट से वंचित होना पड़ेगा. यदि राजद ने नीतीश कुमार को अपना खुला समर्थन दिया तो इसका खमियाजा विधानसभा चुनाव में राजद को भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में विकास मित्र व टोला सेवकों की बहाली में सिर्फ महादलित का जो प्रावधान अपने वोट बैंक के लिए किया था, उनमें से अधिकतर जीतन राम मांझी के साथ हो गये हैं. विकास मित्र व टोला सेवक का संगठन मगध मे तो पूरी तरह जीतनराम मांझी के साथ हो गया है. ऐसे में आने वाले विधान सभा चुनाव मे महादलितों का वोट बैंक का कुछ प्रतिशत भी भाजपा की ओर चला गया तो मगध की 26 विधान सभा क्षेत्रों की वर्तमान तस्वीर बदल जायेगी, इसमें कोई संशय नही है. बात अगर चंपारण प्रमंडल की करें तो नीतीश कुमार व जीतन राम मांझी के बीच छीड़ी राजनीतिक जंग व टकराव का व्यापक असर चम्पारण की राजनीति पर भी दिखने लगा है. कहीं नीतीश कुमार को दलित विरोधी बताया जा रहा है और आगामी चुनाव में उन्हें सबक सिखाने की बात चल रही है तो कहीं उनके समर्थक जश्न भी मना रहे हैं. नीतीश कुमार से पूर्व में खार खा चुकी भाजपा इसका लाभ लेने के लिए सबसे आगे दिख रही है और एक बेहतर कार्ययोजना बनाकर दलितों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करने लगी है. जीतन राम मांझी की प्रशंसा कर वह दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए हर तरह की कसरत कर रही है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है.अभी दलितों को अपने पक्ष में जोड़ने के लिए इससे बड़ा कोई गर्म मुद्दा शायद भाजपा के पास नहीं है. यहां बताते चलें कि पूर्वी चम्प-ारण जिले में बारह विधान सभा क्षेत्र हैं जहां दलितों की आबादी अच्छी खासी है और इनका वोट हमेशा निर्णायक होता है. राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि प्राय: सभी विधान सभा क्षेत्रों में इनकी आबादी है और वे अभी पूरी पार्टी से जोड़ रही है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय समेत कई दिग्गजों का आगमन यहां लगातार हो रहा है और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. नीतीश कुमार से पूर्व से ही खार खाई भाजपा इस बार कोई कसर नही छोड़ना चाह रही और चुनाव में औकात दिखाने के लिए लगातार कार्यक्रमों, बैठकों व अन्य आयोजनों के माध्यम से अपनी मुहिम में जुटी हुई है. भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनील मणि तिवारी के नेतृत्व में भाजपाई अपनी मिशन में लगातार जुटे

फोटो-प्रभात पाण्डेय

हुए हैं और केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को ले जनता तक पहुंच रहे है. इधर रविदास युवा मंच के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रेम चन्द्र कुमार प्रभाकर ने नीतीश कुमार पर दलितों को अपमानित करने का आरोप लगाया और बताया कि एक साजिश के तहत ऐसा किया गया. इनका मानना है कि मांझी के नेतृत्व में दलितों का काफी विकास हो रहा था जिसे नीतीश ने रोक दिया है. वे बताते हैं कि आगामी चुनाव में जनता इसका हिसाब लेगी और नीतीश कुमार को सबक सिखायेगी. भाजपा अगर जीतन राम मांझी को समर्थन दे रही है तो इसके पीछे महादलितों की उनके साथ गोलबंदी है. भाजपा को अहसास है कि जीतन राम मांझी अब बिहार की चुनावी राजनीति में एक बड़ी हस्ती हो चुके हैं और इनको नजरअंदाज करना अब आत्मघाती कदम होगा.■

ईमानदारी के साथ मांझी के इशारे पर खड़े हैं.यहां यह भी बतातें चलें कि पूर्व राज्य सभा सांसद स्व. ब्रहमदेव राम शास्त्री के निधन के बाद अभी चम्पारण में दलित समाज का कोई ऐसा जदयू में नहीं है जो उन्हें मांझी के साथ जाने से रोक सके. ऐसी स्थिति में आगामी चुनाव में जदयू की क्या स्थिति रहेगी,इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है. दूसरी तरफ बीते दिनों रविदास युवा मंच के बैनर तले दलित समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर नीतीश के विरोध में अपनी भड़ास निकाली और एकजुट हो मांझी के पक्ष में गोलबंद होने का सकंल्प ले जदयू समेत अन्य राजनीतिक दलों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब होती रही. वहीं पूर्वी चम्पारण जिले में भाजपा सदस्यता अभियान के बहाने कसरत तेज कर दी है और प्राय: सभी इलाकों में कैंप कर अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाकर

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

विधायक व पार्षद को बधाई

सीतामढ़ी जदयू जिलाध्यक्ष राम जीवन प्रसाद की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई. जिसमें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में रहने वाली गन्ना उद्योग मंत्री डॉ. रंजू गीता, विधायक गुड्डी देवी, सुनीता सिंह चौहान एवं विधान पार्षद राज किशोर कुशवाहा को बधाई दी गई. बैठक में अनिल कुमार सिंह चुम्मन, भरत प्रसाद, किरण गुप्ता, रामबली सिंह, धीरेंद्र कुमार पटेल, बब्लू मंडल, डॉ. अवधेश नायक, राजगीर सिंह, युगल किशोर सिंह, सुनील मंडल, राम छबीला मंडल, रघुनाथ सिंह, वंशलाल प्रसाद, कैलाश राय, गोपाल महतो, सिकंदर राय, अमरनाथ चौधरी, ओमनाथ प्रसाद, दिलीप कुमार यादव व तरुण कुमार समेत अन्य थे. **– ब्रजेश कुमार**

सफल छात्र-छात्राओं को मिला पुरस्कार

सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत भुतही मध्य विद्यालय परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया. शिक्षक संघ के मंत्री हरि नारायण राय की अध्यक्षता में राम एकबाल पासवान के तत्वावधान में आयोजित समारोह का उद्घाटन बीडीओ रितेश कुमार, पूर्व एईओ सीताराम यादव, केंद्र के संचालक डॉ. नवल प्रसाद यादव व प्रधान शिक्षक राज किशोर राउत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया. ग्रामीण विकास परिषद दलकावा के तत्वावधान में शशि शिक्षण केंद्र की ओर से आयोजित कुशाग्र बुद्धि जांच परीक्षा में सफल छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया. पुरस्कार पाने वालों में राजीव कुमार, करण कुमार, मनोज कुमार, मो. इजहार, मो शम्से आलम, मो. अकरम, सोनी कुमारी, मेघा कुमारी, श्रुति कुमारी, शिल्पा कुमारी, अनामिका कुमारी, रेखा कुमारी शामिल है. मौके पर गीतकार गीतेश, सुभाषचंद्र सिंह, रामजतन सिंह, जनार्दन महतो, पूर्व प्रमुख संजय कुमार महतो, पैक्स अध्यक्ष संजय पूर्वे व उदय पंजियार समेत अन्य थे. **– अमरनाथ**

पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि

सीतामढ़ी के डुमरा रोड स्थित मोहित कुटीर परिसर में स्वतंत्रता सेनानी मोहित ठाकुर मेमोरियल सामाजिक सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में चौथी पुण्य तिथि मनायी गयी. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रो. राम लगन झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में संयोजक चंद्रभाग शर्मा, प्रमोद कुमार नील, रुद्र प्रताप सिंह, राजीव कुमार काजू, संजय कुमार वीरस्य, नेहाल अहमद, राम चंद्र प्रसाद सिंह, राजेंद्र सिंह, डॉ. कल्याणी शाही, जगत नारायण सिंह व मो. अफाक खां समेत अन्य थे. **– विकास कुमार**

सम्मान समारोह में विदाई

विदाई सह सम्मान समारोह उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवादा, के प्रांगण में किया गया. पूर्व प्रधान शिक्षक लियाकत अली खां के सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में यह समारोह आयोजित किया गया था. प्रधान शिक्षक श्री खां ने विद्यालय का प्रभार सहायक शिक्षक अनिल कुमार को सौंप दिया. आयोजित समारोह में संकुल संसाधन केन्द्र मच्छरगांवा के शिक्षक, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रमुखन्दन प्रसाद, मनीर खां, व्यास सिंह, रामचन्द्र द्विवेदी, डीडीओ गोरख यादव, पूर्व प्रधानाध्यापक परसा नन्द प्रसाद सिन्हा आदि ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये और सेवा निवृत्त प्रधान शिक्षक लियाकत अली को भाव-भीनी विदाई दी. उनके कार्यों की सराहना सभी ने की और विद्यालय में शिक्षा का और बेहतर माहौल कायम करने पर बल दिया गया. मौके पर अनिल कुमार, अजीत कुमार गुप्ता, अशोक कुमार, धर्मेन्द्र मिश्रा, गीता कुमारी, पम्मी सिंह, किरण कुमारी, रीना कुमारी व नूतन कुमारी, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य निरंजन पांडेय, मदन मिश्रा, अशोक सिंह, जंगाली दास आदि उपस्थित थे. समारोह का संचालन संकुल समन्वयक अजीत कुमार उपाध्याय ने किया. मौके पर ऑल बिहार उर्दू टीचर एसोसिएशन के संगठन सचिव ओजैर सालिम, मो. अफताब आलम आदि ने भी संबोधित किया. **– इंतेजारुल हक**

गरीबों के बीच वस्त्र वितरण

बोधगया के पचहट्टी में सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार सिंह के आवास पर कनाडा से आये कपड़ा व्यवसायी फ्रेड ने गरीबों के बीच वस्त्र व खाद्य सामग्री का वितरण किया. बोधगया के कन्हौल पंचायत के मोरा टाल, सैदपुर, जोधपुर, हरली गांव से आये 70 गरीबों को साड़ी, धोती, शॉल, लुंगी समेत खाद्य सामग्री का वितरण किया. इस अवसर पर बोधगया इंटरनेशनल बौद्ध मठ के प्रभारी भंते साई सना, भंते खम्बेले आदि उपस्थित थे. कार्यक्रम संचालन अनीता कुमारी ने किया. ज्ञात हो कि कनाडा के कपड़ा व्यवसायी फ्रेड पिछले तीन सालों से बोधगया आकर गरीबों के बीच वस्त्र व खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं. फ्रेड ने बताया कि भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि पर गरीबों की सेवा कर मुझे अपार शांति मिलती है. **– सुनील सौरभ**

चुनावी जातीय गोलबंदी की कवायद

बेहतर विकल्प का भरोसा, दलित-पिछड़ों का हमदर्द, बेरोजगारों का मददगार, सरकारी उदासीनता पर प्रहार जैसे चुनावी भाषणों का दौर सीतामढ़ी जिले में जोर पकड़ने लगा है. एक ओर बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं के बीच दलगत संभावित प्रत्याशी अपने बुरे राजनीतिक दिन को कोसने में लगे हैं तो दूसरी ओर नये-नये राजनीतिक दल इस बीच अपनी जगह बनाने की कवायद में जुट गये हैं. पार्टी के साथ जाति का मेल-जोल एवं कार्यकर्ताओं की छीना-झपटी का खेल भी शुरू हो गया है. शहर के गांधी मैदान में पिछले दिनों नव अंकुरित नेशनल पीपुल्स पार्टी के तत्वावधान में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे बिहार की सरकार व शासन व्यवस्था पर नेताओं ने करारा प्रहार किया .

वाल्मीकि कुमार

यह कोई पहला मौका नहीं, जब चुनावी मौसम में किसी दल के नेताओं ने एक बार फिर सूबे की जनता को बेहतर शासन का विकल्प देने का भरोसा दिलाया है. अंतर केवल इतना है कि इस साल एक और नई राजनीतिक पार्टी ने सीतामढी जिला में चुनावी दस्तक दी है. नेशनल पीपुल्स पार्टी जिला नहीं, बल्कि बिहार की जनता के लिए एक पहेली बनी है. जाति व पार्टी की पटरी पर दौड़ रही बिहार की राजनीति में एनपीपी कहां तक अपनी गति बना पायेगी, फिलहाल कहना मुश्किल है. लेकिन इतना तो जरूर है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इस पार्टी की हाजरी कई दलों के लिए मुसीबत साबित हो सकती है. यह भी साफ है कि वर्तमान में यह पार्टी सत्ता के इर्द-गिर्द चहलकदमी भी नहीं कर पायेगी, लेकिन हार-जीत के समीकरण का असर पर कहीं न कहीं प्रभाव डाल सकता है. कारण कि चुनाव में एक-एक वोट मायने रखता है.

अब सीतामढी जिले की राजनीति पर चर्चा करना मुनासिब है. 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के रालोसपा प्रत्याशी राम कुमार शर्मा जदयू के तत्कालीन सांसद डॉ अर्जुन राय को करारी शिकस्त देकर सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब रहे. इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी लहर को दिया जा रहा है. जाति-पार्टी के चुनावी खेल में तब सबकुछ एक सा लगने लगा था. लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद धीरे-धीरे स्थिति में बदलाव का संकेत आना शुरू हो गया है. इसको लेकर तर्क यह दिया जा रहा है कि इस वक्त केंद्र में भाजपा की सरकार बनाना था. लेकिन अब बिहार में सरकार बनाने की बारी है. चर्चा चल रही है कि हालात ने 2014 में बिहार की राजनीति को उलट-पलट कर रख दिया. विकास पुरुष का प्रतीक बने तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के जनादेश को कुछ पल में ही गिरवी रख दिया. महज कुछ माह बाद ही इन्हे अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पुन: सत्ता के करीब आने की कवायद में जुट गये हैं. इस बीच सूबे की राजनीति में गठबंधन की राजनीति ने गहरी जड़ जमा ली है. हालत यह हो गया है कि बिना गठबंधन का कोई भी दल चुनावी दरिया पार करने का साहस नहीं कर पा रहा है. ऐसे में कोई नयी पार्टी केवल वोटों का नुकसान कर सकता है. वह अपना कुछ बना तो नहीं सकता है, मगर सामने वाले के नुकसान की पूर्ण संभावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता है.

मंजू देवी | मो. शफीक खां | मोहन कुमार सिंह | रमेश्वर कुमार महतो | नागेन्द्र प्रसाद सिंह | मोहन झा

अब नेशनल पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का जिक्र करना आवश्यक हो गया है. सीतामढी शहर के गांधी मैदान में 9 फरवरी को पार्टी के जिलाध्यक्ष एहतेशामुल हक की अध्यक्षता व रितेश कुमार गुड्डू के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय वर्मा ने जदयू के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनता को छलने व समाज को बांटने का आरोप लगाया. वहीं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीति आयोग एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मांझी प्रकरण पर जमकर निशाना साधा. कहा कि अब कहां चला गया है नीतीश का दलित प्रेम जब जीतन राम मांझी को हटाने की साजिश चल रही है. पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तारिणी प्रसाद सिंह, युवा महासचिव उदय कुमार कुशवाहा, उस्मान हलालखोर, राजीव मिश्रा, हरेंद्र मिश्रा, जय मंगल सिंह कुशवाहा, शंभू सिंह कुशवाहा, अलाउद्दीन अंसारी, ईशा अंसारी समेत अन्य की मौजूदगी में सीतामढी जिला छात्र लोजपा अध्यक्ष रजनीश यादव व मुन्ना सिंह यादव ने एनपीपी की सदस्यता ग्रहण की. इस दौरान राष्ट्रीय सचिव ने आगामी 23 मार्च को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीए संगमा के नेतृत्व में सीतामढी समाहरणालय का घेराव करने की घोषणा की.

एनपीपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटी भीड़ को लेकर सीतामढी में चर्चाओं का बाजार गर्म है. चल रही चर्चा पर यकीन करे तो कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता की कमी रही, जो सच्चाई भी है. कारण कि अभी इस पार्टी का सीतामढी जिला में नींव भी सही तौर पर नहीं डाला जा सका है. कार्यक्रम के तत्काल बाद ही जिले में राजनीतिक बयानों की चर्चा शुरू हो गयी. जिला जदयू के भूतपूर्व अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह का कहना है कि अभी इस दल का जिला में कोई स्थान नहीं है. चुनाव के समय लाख प्रयास के बाद भी वोट बर्बाद के सिवा यह पार्टी कुछ नहीं कर सकती है. जदयू की मजबूती के सामने सीतामढी में कोई नहीं टिक नहीं सकता है. जदयू नेता रामेश्वर कुमार महतो ने कहा कि एनपीपी के राष्ट्रीय सचिव राघवेंद्र सिंह कुशवाहा अब तक अपना ही बजूद नहीं बना सके है. ऐसे में पार्टी को पहचान दिलाने की बात महज एक सपना हो सकता है. कहा कि चुनावी बुखार में तप रहे राष्ट्रीय सचिव को पता होना चाहिए कि सीतामढी में सभी नीतीश कुमार के पक्ष में गोलबंद है. राजद जिलाध्यक्ष मो शफीक खां का कहना है कि सीतामढी में यह पार्टी जीरो पर बोल्ड होगी. आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी कोई पूछ होने वाली नहीं है. 2010 के विधानसभा चुनाव में सीतामढी से राघवेंद्र राजद के बूते बतौर लोजपा प्रत्याशी बेहतर वोट हासिल कर सके थे.

लोजपा जिलाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ झा उर्फ मोहन झा का कहना है कि पार्टी अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रही है. जिसे लोजपा ने कतिपय कारणों से निकाल दिया था, इसे एनपीपी अपने दल में शामिल कर रही है. इससे लोजपा पर कोई असर पडने वाला नहीं है. लोजपा सीतामढी जिला में मजबूती के साथ है. रालोसपा के प्रदेश नेता मोहन कुमार सिंह का कहना है कि इस पार्टी का फिलहाल कोई आधार नहीं है. कुशवाहा बिरादरी को मनाने का सपना पुरा होने वाला नहीं है. कारण कि बिहार में कुशवाहा बिरादरी समेत अन्य उपेंद्र कुशवाहा के साथ है. भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष मंजू देवी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में सभी एकजुट है. जाति-पार्टी पीछे रह गया है. किसी भी दल के आने से भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

कुल मिला कर देखा जाये तो सभी को इस बात की ही चिंता है कि यह पार्टी अगर बिहार विधानसभा चुनाव में दस्तक देती है तो कुछ हद तक वोटों की बर्बादी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. ऐसे में किसी भी दल का प्रत्याशी संकट में पड़ सकता है. वैसे अभी एनपीपी का प्रदेश स्तरीय सम्मेलनों का दौर बाकी है तो अन्य दलों का चुनावी अभियान भी अभी शुरू नहीं हो सका है. फिलहाल सभी पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रमों में भागीदारी दे रहे हैं. अभी समय है. देखना है कि बिहार में एनपीपी कहां तक चुनावी दंगल में कसरत कर पाने में सफल होता है.■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा में बाहरी नेताओं का जमघट

सुरेश चौहान

केन्द्र में भाजपा सरकार के सत्तारूढ़ होते ही बिहार में पार्टीगत हलचल तेज हो गयी है इस मामले में बेगूसराय जिला भी अछूता नहीं है. विधान सभा की चुनावी आहट करीब आते ही भाजपा में गोलबंदी शुरू हो चुकी है. जिला भाजपा का मौजूदा परिदृश्य आयातीत राजनेताओं से पटा हुआ है. विगत पांच साल के राजनीतिक यात्रा पर नजर डालते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि तकरीबन एक दर्जन नेता भिन्न-भिन्न दलों का दड़वा छोड़कर सीधे भाजपा में आ धमके हैं और उसी दल के सहारे अपना अगला भविष्य सुरक्षित एवं संरक्षित करने में जुटे हैं. आयातित नेताओं की सूची में पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद डॉ मोनाजिर हसन, पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ, पूर्व विधान पार्षद राम बदन राय, उपेन्द्र प्रसाद सिंह, सर्वेश कुमार, रामानन्द राम, ललन कुंवर, सुरेन्द्र मेहता, अमर कुमार सिंह एवं पूर्व विधायक शिवदानी सिंह सहित अन्य शामिल हैं.

डॉ मोनाजिर हसन ने जनता दल से राजनीति प्रारंभ की और राजद, जदयू से होते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं. वे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं बेगूसराय के सांसद रह चुके हैं. जमशेद अशरफ लोजपा से राजनीति की शुरूआत कर जदयू, कांग्रेस से होते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है. वे बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं. रामबदन राय जनता दल से राजनीति में प्रवेश किया. उन्होंने समता पार्टी, जदयू, राजद से होते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है. वे विधान सभा एवं लोक सभा का चुनाव कई बार लड़ चुके हैं लेकिन हर बार उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा है. लेकिन वह विधान पार्षद रह चुके हैं.

डॉ. मोनाज़िर हसन | जमशेद अशरफ | सरवेश जी | सुरेंद्र मेहता

उपेन्द्र प्रसाद सिंह लोजपा से राजनीति प्रारंभ कर विधान सभा का चुनाव लड़े लेकिन सफलता नहीं मिली. उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है. सर्वेश कुमार ने भारत सरकार के लोक सेवक पद से त्यागपत्र देकर राजनीति में प्रवेश किया और गत विधान सभा चुनाव में मटिहानी विधान सभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और सम्मानजनक मत प्राप्त किए, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके. इस बार उन्होंने निर्दलीय की बजाय दलीय राजनीति को अपनाया और भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है. सुरेन्द्र मेहता वामपंथी खेमे से राजनीति प्रारंभ की और अब भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है. संप्रति बेगूसराय विधान सभा सीट से भाजपा के विधायक हैं. रामानन्द राम राजद से राजनीति प्रारंभ कर भाजपा में प्रवेश किया. वे बखरी (आरक्षित) विधान सभा क्षेत्र के विधायक हैं. अमर कुमार सिंह ने जदयू से राजनीति की शुरूआत की. साहेबपुर कमाल विधान सभा उप चुनाव के समय दल बदलकर भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं हासिल हुई. भाजपा के पूर्व विधायक शिवदानी सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है. यहां रोचक तथ्य यह है कि भाजपा में आए ये राजनेताओं को पार्टी की रीति, नीति एवं सिद्धांत की जानकारी भले ही नहीं हो लेकिन अगामी विधान सभा चुनाव को निशाने पर रखकर टिकट पाने की जुगात में अपने समर्थकों के साथ सक्रिय हैं. पटना-दिल्ली के रास्ते पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से सीधे सरोकार साधे हैं और टिकट पाने का दावा कर रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

वैश्य प्रत्याशी रोकेगा भाजपा का तेज !

देश का सिरमौर दिल्ली में संपन्न विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के साथ ही सीतामढी में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी चौपालों पर रौनक लौटने लगी है. साल 2010 से पूर्व तक सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के नाम से चर्चित सीट अब परिहार विधानसभा सीट में परिवर्तित हो गई है. आजादी के बाद से लेकर अब तक इस क्षेत्र से जन नायक कर्पूरी ठाकुर के अलावा चार बार यादव, 6 बार वैश्य एवं दो बार अल्पसंख्यक प्रतिनिधि निर्वाचित हो चुके है. बताया जाता है कि वैश्य बाहुल्य इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाता दूसरे तो यादव तीसरा स्थान रखते हैं. वर्तमान में भाजपा के राम नरेश प्रसाद यादव इस क्षेत्र से विधायक हैं. 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनावी अखाड़ा में पटखनी देने की तैयारी अब जोर पकड़ने लगी है .....

डॉ. रामचंद्र पूरवे | महेंद्र सिंह यादव | मो. अनवर उल हक | परवेज आलम अंसारी | रामजीवन प्रसाद | रामनरेश प्रसाद यादव

वाल्मीकि कुमार

भारत - नेपाल सीमा पर स्थित सीतामढी जिला का सोनबरसा व परिहार प्रखंड दोनों देश के बीच का सेतु रहा है. खुली सीमा होने के कारण इस इलाका से होकर लोगों का आवागमन एक घर से दूसरे घर के दरवाजे की तरह होता रहा है. हाल के दशक में सुरक्षा को लेकर सीमा पर एसएसबी की तैनाती कर दी गयी है. मगर दोनों ही देश के बीच की रोटी-बेटी का संबंध अब भी अपनेपन का एहसास कराता है. आजादी के बाद से लेकर साल 2010 से पूर्व तक सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र रहा है. जहां से सिंघेश्वर यादव, रामनंदन राय, राजनंदन राय, सीताराम महतो, तिलकधारी महतो, आलम बाबू, मो अनवारूल हक, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, राम जीवन प्रसाद, डॉ रामचंद्र पूर्वे को प्रतिनिधित्व का मौका मिला है. साल 2010 में सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र का नाम बदल कर परिहार विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया. वर्तमान में इस क्षेत्र से भाजपा के राम नरेश प्रसाद यादव विधायक हैं.

बताया जाता है कि इस क्षेत्र का विकास को लेकर दशकों से चल रही कवायद के बाद भी जन समस्याओं का निदान अब भी गंभीर चुनौती बना है. तकरीबन साढे तीन दशक पूर्व 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर सोनबरसा से मो अनवारूल हक को प्रतिनिधित्व का मौका मिला था. 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने नये चेहरे के रूप में बैद्यनाथ प्रसाद को चुनावी समर में उतारा था, लेकिन लोकदल प्रत्याशी रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर को सीधा मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी रहे मो अनवारूल हक से ही हुई थी. बैद्यनाथ प्रसाद चुनाव में असर नहीं डाल सके थे. तब कर्पूरी ठाकुर सम्मानजनक मतों से निर्वाचित हुए थे. 1990 में जनता दल एवं 1995 में राजद की टिकट पर राम जीवन प्रसाद को प्रतिनिधित्व का मौका मिला था. वर्ष 2000 के चुनाव में राजद ने डॉ रामचंद्र पूर्वे को पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा था, तब डॉ पूर्वे निर्वाचित होकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का कमान थामा था. वर्ष 2005 के चुनाव में राजद ने डॉ पूर्वे को ही टिकट देकर लड़ाया था, जिसमें दुबारा इनकी जीत हुई थी. यानी कि सोनबरसा विधानसभा सीट के अंतिम विजेता यही रहे. साल 2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा-जदयू गठबंधन के तहत नवगठित परिहार विधानसभा क्षेत्र से बतौर भाजपा प्रत्याशी राम नरेश प्रसाद यादव चुनावी समर में भाग्य आजमाया था. तब इन्हें जीत हासिल हुई थी. हालांकी इस साल के चुनाव में राजद से डॉ रामचंद्र पूर्वे, कांग्रेस से परवेज आलम अंसारी, बसपा से राघवेंद्र कुमार रवि व निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव ने भी अपना भाग्य आजमाया था. कुल मिलाकर आजादी के बाद से साढे छह दशक की अवधि में सर्वाधिक वैश्य बिरादरी को 6, यादव को 4 एवं अल्पसंख्यक बिरादरी को 2 बार प्रतिनिधित्व का मौका मिला है. अब तक के चुनावी नतीजा से लगभग यह साफ हो गया है कि इस क्षेत्र पर वैश्य, यादव व अल्पसंख्यक बिरादरी का वर्चस्व है.

अब मामला 2015 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का है. एक ओर जातिगत आकड़ों की बाजीगरी खेली जा रही है तो दूसरी ओर गठबंधन की राजनीति ताल ठोक रही है. इसके बीच इस चुनाव में बाजी कौन मारेगा? इस बात को लेकर चुनावी बहस का दौर अब जोर पकड़ने लगा है. चल रही चर्चाओं पर गौर करें तो 2014 में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर का जो वेग रहा, अब धीरे-धीरे सामान्य हो चला है. इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम ने भाजपा की मजबूती पर सवाल खड़ा करने लगा है. लोगों का मानना है कि जब दल के नेता सत्ता व कुर्सी की खातिर किसी के साथ गठबंधन को तैयार है तब मतदाता अपनी समस्या के निदान के लिए खुद निर्णय क्यों नही कर सकती है ? इसे राजनीतिक दल के लोग चाहे जिस रूप में ले, लेकिन मसले की गंभीरता को किनारा नहीं किया जा सकता है. अब सवाल यह उठता है कि अगर बिहार में जदयू के नीतीश कुमार व राजद के लालू प्रसाद के बीच अगर चुनाव को लेकर गठबंधन हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए चुनावी वैतरणी पार करना कितना मुश्किल हो सकता है ? एक ओर जदयू - राजद गठबंधन की पार्टी कैडर के अलावा गैर भाजपा वोटों पर नजर टिकी है, जिसमें अल्पसंख्यक मत भी शामिल है, तो दूसरी ओर भाजपा गठबंधन को लोजपा के दलित व रालोसपा के कुशवाहा समेत अन्य मतों का भ्रम हो रहा है. चुनाव के वक्त तक राजनीतिक स्थिति कैसी रहेगी, फिलहाल कहना मुश्किल है. लेकिन इतना तो तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढी जिले के परिहार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लिए अपनी सीट को बचाना आसान नहीं है. जानकारों की मानें तो अगर कोई मजबूत वैश्य प्रत्याशी जदयू-राजद गठबंधन से आ जाता है तो चुनावी तस्वीर बदल सकती है. वैसे अल्पसंख्यक भी इस क्षेत्र को निशाना बना सकता है. कारण कि पूर्व में दो बार इस बिरादरी को भी सफलता मिल चुकी है. यादव बिरादरी भी सीट पर कब्जा के भगीरथ प्रयास से खुद को अलग नहीं रख सकता है. कारण कि इस बिरादरी ने भी 4 बार प्रतिनिधित्व का कमान थाम चुका है. कुल मिलाकर जाति व पार्टी के चुनावी समर में किसका किस्मत चमकेगा, यह चर्चा के केंद्र में है.

जहां तक चुनावी वादों का सवाल है तो इस मसले पर कुछ कहना उचित नहीं लगता है. आलम यह है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक सोनबरसा व परिहार क्षेत्र में सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत विकास कार्यो की आधारशिला रखी गयी. कुछ हद तक समस्या का निदान भी कराया गया है, लेकिन अब भी जमीनी समस्या का निदान नहीं हो सका है.

अगर एक परिहार प्रखंड की ही चर्चा करें तो सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के कई मामले अखबारों में सुर्खियां बटोर चुकी हैं. मामला चाहे इंदिरा आवास का हो अथवा छात्रवृत्ति, पोशाक व अन्य योजनाओं का. पंचायतो में चापाकल का मामला हो अथवा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का. चर्चा के मुताबिक स्थानीय प्रतिनिधियों की उदासीनता, प्रशासनिक ला-परवाही व माफिया सरीखे लोगों की मिलीभगत का आलम है कि परिहार प्रखंड के भिसवा बाजार पर दशकों पूर्व निर्मित 6 बेड का सरकारी अस्पताल का लाभ आम लोगों को नहीं मिल सका है. वहीं भिसवा बाजार के तकरीबन 12 एकड़ जमीन के अतिक्रमण पर लगाम लगाने की दिशा में भी कोई पहल नहीं की जा रही है. नतीजतन बाजार का अस्तित्व खतरा में पड़ता दिख रहा है. इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुरक्षा का हाल यह है कि कोई भी अपराधी गिरोह आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर बेखौफ घुमता रहता है, लेकिन अविकसित भौगोलिक संरचना के कारण प्रशासन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है. भारत - नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के लोग अकसर दहशत में रहने को विवश हैं. जहां तक क्षेत्र के विकास का सवाल है तो गुमनामी की शर्त पर लोगों का कहना है कि समस्या निदान में विफल प्रतिनिधि चुनावी साल में समस्या निदान को लेकर धरना-प्रदर्शन कर लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हैं.

वैसे विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है. सूबे में राजनीतिक जोड़-तोड़ की कवायद चल रही है. गठबंधन को लेकर दलगत आधार पर उतार-चढाव जारी है. यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा कि जाति व पार्टी में मतदाता किसे अपनाता है. संभव है मतदाता इन दोनों को किनारा कर स्वविवेक का परिचय देते हुए नये राजनीतिक समीकरण को मजबूती देकर अपनी आवाज को बुलंद करने में लग जाये. वैसे परिहार में भाजपा के यादवी रथ को रोकने को लेकर वैश्य बिरादरी का चुनावी कसरत शुरू होने की चर्चा है. अब देखना है इसमें कौन-कौन संभावित प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

झाविमो को ले डूबा बाबूलाल का अहंकार

मंगलानंद

झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के अहंकार पर आखिरकार झाविमो के विधायकों की महत्वाकांक्षा ही भारी पड़ी और एक साथ पार्टी के छह विधायक भाजपा में शामिल हो गए. अब झारखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित हो चुकी है और आजसू के बारगेन की राजनीति पर भी विराम लग चुका है. झाविमो के इन छह विधायकों में कई ऐसे भी विधायक हैं जो पहले तो आजसू में थे लेकिन भाजपा के साथ आजसू के गठबंधन के बाद उन्हें आजसू ने टिकट ही नहीं दिया था और वे सीटिंग विधायक थे. जब आजसू ने टिकट नहीं दिया तो वे झाविमो में शामिल होकर विधायक बने और अब अंततः इन विधायकों ने भी एक साथ दो शिकार कर लिए. पहले तो झाविमो छोड़ कर भाजपा शामिल हुए और फिर भाजपा में शामिल होकर आजसू की बारगेन की राजनीति पर विराम सा लगा दिया. झारखंड विकास मोर्चा से नाता तोड़ भाजपा में जाने वाले विधायकों में अमर कुमार बाउरी, गणेश गंझू, नवीन जायसवाल, रणधीर सिंह, आलोक चौरसिया और जानकी यादव शामिल हैं. इन सभी विधायकों ने पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में भाजपा विधायकों के साथ बैठने की अपील की थी. आखिरकार ये सभी विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में इन विधायकों ने भाजपा का दामन थामा था. गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव से ही झारखंड विकास मोर्चा के विधायकों के भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे. यही नहीं चुनाव के दौरान राजनीतिक गलियारों में झाविमो के बाबू लाल मरांडी के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चाऐं गर्म रहीं लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बहरहाल झारखंड विकास मोर्चा के छह विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से मरांडी को तगड़ा झटका लगा है. झाविमो के छह विधायकों ने दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. अब झारखंड विधानसभा में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल चुका है और विधायकों की संख्या 42 हो चुकी है.■

feedback@chauthiduniya.com

बस ठगे गए मुसलमान

बिहार विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव को लेकर होने वाली तैयारियों में जोर-शोर से जुट गई हैं. जनता दल राष्ट्रवादी भी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है लेकिन उसका अभियान लीक से कुछ हटकर है. यह पार्टी सिर्फ ऊपरी राजनीति नहीं बल्कि जमीनी राजनीति करने में विश्वास रखती है. वह छोटे-छोटे कस्बों से लेकर समाज से वंचित तबकों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में लगी हुई है. इस संदर्भ में जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक अशफाक रहमान से चौथी दुनिया ने बातचीत की. प्रस्तुत है प्रमुख अंश:-

जनता दल राष्ट्रवादी का उद्देश्य क्या है?

हमारा उद्देश्य साफ-सुथरी राजनीति करने का है. जनता को उन सारी पार्टियों से छुटकारा दिलाना जिन्हें जनता को मजबूरी में वोट देना पड़ता है. और इसके अलावा जनता को एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करना है.

मांझी सरकार जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है?

मेरा मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति योग्य ना हो तब तक उसे सत्ता के शिखर पर नहीं बैठना चाहिए. नीतीश कुमार ने तो अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए जीतराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया है. और ऐसा कर के नीतीश ने पूरे दलित समाज का मजाक ही बनाया है. मुख्यमंत्री तो कोई भी बयान देने से पहले सोचते तक नहीं हैं, और ऐसा करना उनको शोभा नहीं देता है. अब चाहे वो बयान सरकारी कार्य में करोड़-दो करोड़ के घपले को घपला नहीं मानने का हो या बिजली बिल समायोजन में घूस देने की बात हो या फिर बाढ़ के समय चूहे खाने की बात, ये सारी बातें उनकी प्रशासनिक अपरिपक्वता को दर्शाती हैं.

राजनितिक उथल- पुथल पर आप क्या कहेंगें?

मैं दूसरों पर कमेंट नहीं करता और जहां तक बिहार के राजनीतिक उथल-पुथल की बात है तो मेरा मानना है कि जातिवादी राजनीति का अंत निकट है. नीतीश कुमार और लालू यादव खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे.

सरकार से मुस्लिम समाज को क्या लाभ मिल रहा है?

नीतीश तो कम से कम लॉलीपॉप देते थे, जीतन राम मांझी तो वो भी नहीं दे पाते हैं. लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने मुसलमानों को कुछ दिया तो नहीं लेकिन लॉलीपॉप जरूर दिखाते रहे. जीतनराम मांझी की सरकार में तो वो भी नसीब नहीं हुआ. भाजपा तो सपने ही बेच रही है. जनता दल राष्ट्रवादी आबादी के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी की मांग का पूरा समर्थन करती है. समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वंचित तबके के योग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता की बागडोर सौंपने की वकालत भी करती है. इन मुद्दों को लेकर पार्टी गांव-गांव में जागरूकता पैदा कर रही है.

क्या भारत को भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सकता है?

भ्रष्टाचार को 100 प्रतिशत तो नहीं हटाया जा सकता है लेकिन 90 प्रतिशत तक इसमें कामयाबी पाई जा सकती है. भ्रष्टाचार की तो ऐसी हालत है कि किस पर उंगली उठाई जाए ये कहना मुश्किल है. इस मामले में अधिकतर राजनीतिक दल गिरोह की तरह काम रहे हैं. जहां तक नरेंद्र मोदी की सरकार की बात है तो वो आम जनता को सही जानकारी नहीं दे रही है. इसके अवाला भ्रष्टाचार विरोधी कानून लोकपाल पर सरकार का लचीला रवैया इसे शक के दायरे में खड़ा कर देता है. हमारी पार्टी का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि इसे ऐसे किसी दल से न जोड़ा जाए जिसे जनता ने खारिज कर दिया हो. यह पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाने और दंगा विरोधी कानून को लागू करवाने में जुड़े कार्यकर्ताओं को तरजीह देगी. उन्हें जनता का प्रतिनिधि निर्वाचित करा विधानसभा में भेजने का प्रयास करेगी, ताकि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके. ■

एक नज़र

चुरिहरवा टोला का मामला सुलझा

जबतक समाज में आपसी सौहार्द्र कायम नहीं होगा तबतक खुशहाली व तरक्की संभव नहीं है. दोनों समाज के लोगों को इस मुद्दे पर काफी गंभीरता से सोचना चाहिए और आपसी सौहार्द्र व भाईचारा कायम रहे इसके लिए काफी सूझ-बूझ से काम लेना चाहिए. पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में उक्त बातें सदर के अनुमंडलाधिकारी ज्ञानेन्द्र कुमार ने कहीं. मंच का संचालन लालबाबू प्रसाद ने किया जबकि मौके पर जिला पार्षद पति ओजैर अंजुम, अंचलाधिकारी आईडी राम, मुफसिल इन्स्पेक्टर शशिभूषण सिंह, बंजरिया थानाध्यक्ष आरके सिंह, शांति समिति के सत्याशरण यादव, नसीमा खातून, विनोद श्रीवास्तव, ललन सहनी, शेख जैनुल हक, अलीशेर अंसारी, दीपक सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे. इस अवसर पर चुरिहरवा गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बाइस सदस्यीय शांति समिति का गठन किया गया. दोनों समुदायों से ग्यारह-ग्यारह लोगों का चयन हुआ. मौके पर दोनों समुदायों के दो-दो लोगों को सम्मानित किया गया. जैनुल हक, अलीशेर अंसारी, ललन सहनी व दीपक सिंह को शांति व्यवस्था कायम रखने में सहयोग करने के लिए शांति समिति द्वारा शॉल व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया.

जश्न-ए-इकरा का आयोजन

शहर के मठिया जिरात में संचालित इकरा इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में रजत जयंती वार्षिकोत्सव सह जश्न-ए-इकरा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन सिंचाई विभाग बेतिया के एसडीओ कमरुज़्ज़मा ने किया. मौके पर उन्होंने विद्यालय की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है और इसके बगैर विकास संभव नहीं है. उन्होंने गुणवता पूर्ण शिक्षा के साथ-साथ नैतिकता पर भी जोर दिया और कहा कि शिक्षा में नैतिकता का समावेश निहायत जरूरी है. मौके पर छात्र-छात्राओं ने अनेक रंगा-रंग कार्यक्रम प्रस्तुत किये और उपस्थित समूह को झुमाया. इसी क्रम में नात, नज्म, तराना, मानोलॉग, पॉलीलॉग, मुशायरा व ड्रामा का आयोजन छात्र-छात्राओं ने किया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत जेबा अफरोज ने कुरआन पाठ से किया. तत्पश्चात अलमाश फातमा ने इसका अनुवाद किया और तालियां बटोरी. मौके पर छात्र जयद रहमान, सूफिया आरिफ, तौसीफ, जाहेदा कौशर, शोएब एकबाल, शौकत अली, अफजल सफी, आमना परवीन आदि छात्र-छात्राओं ने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किये. इस अवसर पर एमएस कॉलेज के प्राध्यापक प्रो. शकील अहमद खां, शायर तफजील अहमद, डॉ. मोहसीन सिद्दीकी, विद्यालय के निदेशक जफरूस्सलाम, अनिल कुमार सिंह, मुख्तार आलम, अनवर कमाल, अकिल मुस्ताक आदि इपस्थित थे. मंच का संचालन विद्यालय के प्राचार्य मिसबाहूस सलाम व एहसानुल्लाह ने संयुक्त रूप से किया.

अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना

चकिया में अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश केके त्रिपाठी प्रभारी न्यायाधीश सुरेश कुमार श्रीवास्तव एवं जिलाधिकारी जितेन्द्र श्रीवास्तव ने चकिया अनुमंडल के कार्यालय के भवन का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि तीन न्यायालयों क्रमशः एक सबजज, एक मुंसिफ और एक न्यायीधीश दंडाधिकारी के कार्यालय व न्यायालय के लिए चकिया चीनी मिल की दस एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. जिसका प्रस्ताव शीघ्र ही उच्च न्यायालय के निबंधन विभाग को भेजा जा रहा है. स्वीकृति के तत्काल बाद भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. निरीक्षण के क्रम में एसडीओ चित्रगुप्त कुमार, बीडीओ गंगा सागर सिंह, इन्स्पेक्टर थानाध्यक्ष अशोक कुमार आजाद आदि शामिल थे. **– इंतेजारुल हक**

कविता संग्रह का लोकार्पण

पत्रकार सुनील सौरभ की प्रकाशित कविता संग्रह मै सपने बुनता हूं का लोकार्पण सांसद (राज्य सभा) आरके सिन्हा ने बोधगया के होटल रायल रेंजिडेन्सी में किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति कविता की रचना नहीं कर सकता है. इसीलिए महाकवि नीरज ने कहा है कि मानव होना भाग्य की बात है, लेकिन कवि होना सौभाग्य है. सांसद ने कहा कि यथार्थ की भूमि और कल्पनाओं के आकाश में विचरण करते हूए कवि जो कुछ व्यक्त करता है, वह समाज व व्यक्ति के लिए आईना का काम करता है. सुनील सौरभ की कविता संग्रह मैं सपने बुनता हूं की सकारात्मक कविताएं समाज व व्यक्ति को एक संदेश देती नजर आती हैं. मै इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं. इस अवसर पर कुछ विदेशी मेहमानों, बोधगया मंदिर प्रबंधकारणी समिति के सदस्य डॉ. अरविन्द कुमार सिंह, डीपीएस के प्रो वाइस चेयरमैन संजीव कुमार,घाराना ऐसोसियएट के संजय कुमार पप्पू, संजू श्रीवास्तव समेत अन्य प्रबुद्ध लोगों के अलावा बड़ी संख्या में पत्रकार-छायाकार, सहित्यकार मौजूद थे. ज्ञात हो कि इससे पूर्व सुनील सौरभ की दो पुस्तकें अतीत की पगडंडियो पर (कविता संग्रह), मोक्षधाम गयाजी प्रकाशित हो चुकी है. तीन दशक से पत्रकारिता में सक्रिय सुनील सौरभ को पत्रकारिता के लिए कई एर्वाड, सम्मान से नवाजा जा चुका है.■

– अनिल कुमार

चंपारण

> बेगूसराय जिले में राजकीयकृत माध्यमिक एवं परियोजना विद्यालयों की संख्या-84 तथा स्थापना की स्वीकृति प्राप्त वित्त रहित उच्च विद्यालयों की संख्या 13 है. उक्त विद्यालयों में पढ़ने वाले नवम एवं दशम वर्ग के छात्रा-छात्राओं की संख्या लगभग एक लाख पच्चीस हजार है. जिले में शिक्षकों के स्वीकृत पद 870 है. छात्र-छात्राओं के लिए उच्च विद्यालयों में भवन का सर्वथा अभाव है. शिक्षकों के स्वीकृत 870 पद के लिए लगभग 200 शिक्षक ही कार्यरत हैं. जिले में मात्रा 19 प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं.

हाशिए पर बिहार के वित्तपोषित शिक्षक

बिहार की मांझी सरकार एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने का दावा करती है और लाखों-करोड़ो रुपये खर्च कर नए-नए विद्यालय व महाविद्यालय खोलने का प्लान बना रही है तो दूसरी तरफ वित्तरहित से वित्तपोषित हुए महाविद्यालयों व उच्च विद्यालयों की लगातार उपेक्षा कर रही है.हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परीक्षाफल के आधार पर मिलने वाली अनुदान की राशि सरकार ने मात्र 243 महाविद्यालयों को वर्ष 2008-10 तक की उपलब्ध कराई है जबकि शेष महाविद्यालयों का 2009-11, 2010-12, 2011-13 एवं 2014-15 की राशि बकाया है.

फोटो-वित्तसम्पोषित शिक्षकों का कार्यक्रम

इंतेज़ारुल हक़

अनुदानित इंटरमीडिएट महाविद्यालयों व उच्च विद्यालयों के में कई दशक से अपनी सेवा दे रहे हजारों वित्त सम्पोषित शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के प्रति सरकार गंभीर क्यों नहीं है? आखिर उनकी जायज़ मांगें कब पूरी होंगी और वे कब तक सरकार की दोहरी शिक्षा नीति का शिकार होते रहेंगे? इस मुद्दे पर इन दिनों एक गरम बहस छिड़ी हुई है और सरकार की शिक्षा नीति पर अनेक तरह के सवाल खड़े किये जाने लगे हैं. बिहार के 535 अनुदानित इंटर महाविद्यालयों व 900 वित्तरहित उच्च विद्यालयों के करीब बीस हजार से अधिक शिक्षक व दूसरे कर्मचारी अभी सरकार की दोहरी नीति का शिकार हो अनेक कठिन चुनौतियों से जूझ रहे हैं और अपनी किस्मत को कोस रहे हैं.

बिहार की मांझी सरकार एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने का दावा करती है और लाखों-करोड़ो रुपये खर्च कर नए-नए विद्यालय व महाविद्यालय खोलने का प्लान बना रही है तो दूसरी तरफ वित्तरहित से वित्तसम्पोषित हुए महाविद्यालयों व उच्च विद्यालयों की लगातार उपेक्षा कर रही है.हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परीक्षाफल के आधार पर मिलने वाली अनुदान की राशि सरकार ने मात्र 243 महाविद्यालयों को वर्ष 2008-10 तक की उपलब्ध कराई है जबकि शेष महाविद्यालयों का 2009-11, 2010-12, 2011-13 एवं 2014-15 की राशि बकाया है. यह कब मिलेगी, इसकी तो कोई निर्धारित तिथि नहीं है किंतु जिस तरह से सरकार व विभाग इनकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इनके भविष्य को अधर में लटका दिया है उससे उससे एक बात तो तय है कि आगामी चुनाव में सत्ताधारी दल को यह काम काफी महंगा साबित हो सकता है.

सबसे अहम बात यह है कि बिहार में तत्काल एक हजार पांच सौ डिग्री कॉलेज तथा उन्नीस हजार नौ सौ इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा देने वाले इंटरमीडिएट कॉलेज की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को राज्य सरकार व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वीकार भी करते हैं. जबकि अंगीभूत डिग्री कॉलेजों की संख्या-231 व संबद्ध डिग्री कॉलेजों की संख्या-225 है. वहीं इंटरमीडिएट कॉलेजों की संख्या 535, राजकीय, अल्पसंख्यक व प्रोजेक्ट विद्यालयों की संख्या करीब तीन हजार है.

इसके अलावा नौ सौ वित्तरहित हाई स्कूल व एक हजार संस्कृत विद्यालय संचालित है, जो एक तिहाई से भी कम है.बावजूद इसके

> बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब इन महाविद्यालयों व उच्च विद्यालयों को वित्तरहित से वित्तसम्पोषित किया था और अन्य कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी तो शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों में एक बड़ी उम्मीद जगी थी और उन्हें लगा था कि वर्षों की कड़ी तपस्या अब रंग लाने वाली है. दूसरी तरफ जानकार यह बताते हैं कि इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद नियमावली 1994 के मापदंड पर स्वीकृत महाविद्यालयों को खरा उतरने के लिए बाध्य किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की अनदेखी भी की गयी है. कोठारी कमीशन की अनुशंसा के आलोक में इंटर शिक्षा को स्वतंत्र रूप से संचालित कराने के लिए विश्वविद्यालय आयोग भी कई बार निर्देश दे चुका है.

डिग्री की पढ़ाई संबद्ध डिग्री कॉलेजों में वित्तसम्पाषित शिक्षकों की बदौलत टिकी हुई है.चूंकि अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है.कभी पटना साइंस कॉलेज में ही एक विषय भौतिकी में विभाग में 44 शिक्षक हुआ करते थे, आज वहीं 5-6 शिक्षकों के सहारे काम चल रहा है. इतना ही नहीं बिहार में कई एसे अंगीभूत कॉलेज हैं जहां भौतिकी व अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षकों की भारी कमी है.

ऐसी परिस्थिति में वित्तसम्पोषित शिक्षकों व दूसरे कर्मचारियों की भूमिका काफी बढ़ जाती है और सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून में शामिल कराने अर्थात 12वीं कक्षा तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू कराने में अहम रोल अदा करते हैं.यहां शायद यही कारण है कि वित्तसम्पोषित कॉलेजों के इंटर परीक्षा परिणाम अन्य कॉलेजों की अपेक्षा काफी बेहतर होते है जिसकी चर्चा परीक्षा परिणाम के बाद होती रहती है. यहां एक बात और जानने योग्य है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब इन महाविद्यालयों व उच्च विद्यालयों को वित्तरहित से वित्तसम्पोषित किया था और अन्य कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी तो शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों में एक बड़ी उम्मीद जगी थी और उन्हें लगा था कि वर्षों की कड़ी तपस्या अब रंग लाने वाली है.

दूसरी तरफ जानकार यह बताते हैं कि इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद नियमावली 1994 के मापदंड पर स्वीकृत महाविद्यालयों को खरा उतरने के लिए बाध्य किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की अनदेखी भी की गयी है. कोठारी कमीशन की अनुशंसा के आलोक में इंटर शिक्षा को स्वतंत्र रूप से संचालित कराने के लिए विश्वविद्यालय आयोग भी कई बार निर्देश दे चुका है.आयोग अपने निर्देश में स्पष्ट कर चुका है कि इंटरमीडिएट शिक्षा पर किसी प्रकार का व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वहन नहीं करेगी.बावजूद इसके आयोग के नियमों पर चलने वाले अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों व संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा इंटरमीडिएट की पढ़ाई करायी जा रही है.इस बीच वित्तसम्पोषित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी कल्याण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. गणेश प्रसाद सिंह ने चौथी दुनिया को दूरभाष पर बताया कि शिक्षा विभाग की दोहरी नीति से वितसम्पोषित व शिक्षकेत्तर कर्मचारी काफी परेशान हैं. उन्होंने सम्पोषित शिक्षकों व कर्मियों को नियमित वेतनमान देने की मांग सरकार से की और कहा कि इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ी जायेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

बेगूसराय में अंधेरे में शिक्षा

सुरेश चौहान

शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मृतप्राय हो चुकी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण नीति ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की सरकार की नीति का मखौल बना डाला है. बेगूसराय जिले की शिक्षा व्यवस्था इसका अपवाद नहीं है. जिले में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति चरमरा गयी है. एक ओर जहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए उच्च विद्यालयों की संख्या कम पड़ रही है, वहीं छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की काफी कमी है तो दूसरी ओर जिले के शिक्षा पदाधिकारियों की रुचि भी विभागीय नीतियों के अनुपालन में नहीं दिख रही है. वर्तमान में शिक्षक से पदाधिकारी बने लोगों में प्रशासनिक अनुभव एवं विकास योजनाओं की जानकारी की कमी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में बाधक बन रही है.

बेगूसराय जिले में राजकीयकृत माध्यमिक एवं परियोजना विद्यालयों की संख्या-84 तथा स्थापना की स्वीकृति प्राप्त वित्त रहित उच्च विद्यालयों की संख्या 13 है. उक्त विद्यालयों में पढ़ने वाले नवम एवं दशम वर्ग के छात्रा-छात्राओं की संख्या लगभग एक लाख पच्चीस हजार है. जिले में शिक्षकों के स्वीकृत पद 870 है. छात्र-छात्राओं के लिए उच्च विद्यालयों में भवन का सर्वथा अभाव है. शिक्षकों के स्वीकृत 870 पद के लिए लगभग 200 शिक्षक ही कार्यरत हैं. जिले में मात्रा 19 प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं. शेष विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन चल रहा है. जिले के 21 उच्च विद्यालयों को +2 विद्यालय में उत्क्रमित किया गया जिसमें अधिकांश के पास भवन नहीं है. 21 में से सिर्फ 11 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों को ही शिक्षक मिल पाए हैं. यक्ष प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में कैसे हो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास. अब जरा जिले के उच्च विद्यालयों की अन्य आधारभूत संरचना को देखें.

कम्प्यूटर शिक्षा : राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक उच्च विद्यालय को 17 लाख रुपये की लागत से कम्प्यूटर सेट, जेनरेटर, तेल एवं कम्प्यूटर टीचर देना था. बेगूसराय जिले के मात्र 54 उच्च विद्यालयों को कम्प्यूटर मिला. इसे लागू कराने के लिए बेलट्रॉन एजेंसी को तीन वर्ष के अनुबंध पर दिया गया. शर्म की बात यह है कि जिले के अधिकांश

विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा चालू नहीं हुई और कुछ विद्यालयों से कम्प्यूटर की चोरी हो गयी. आज की तारीख में जिले के एक भी उच्च विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा चालू नहीं है. कम्प्यूटर की खरीद में घोटाले के भी आरोप लगते रहे.

पुस्तकालय : प्रदेश सरकार की ओर से प्रत्येक उच्च विद्यालय को एक लाख रुपये की पुस्तकें विद्यालय पुस्तकालय के लिए दी गईं. अधिकांश विद्यालयों में पुस्तकों का पैकेट खुला ही नहीं और वह गल-पच गया. बालिका उच्च विद्यालय महना एवं बालक उच्च विद्यालय महना सहित अनेक विद्यालयों को तो पुस्तक मिली ही नहीं. पुस्तकालयाध्यक्ष के अभाव में पुस्तकालय कक्ष का ताला खुलता ही नहीं. आज की तिथि में सभी पुस्तकालय ठप हैं.

प्रयोगशाला : जिले के सभी उच्च विद्यालयों को सरकार द्वारा प्रायोगिक उपकरण प्रदान किया गया. लेकिन जिले के एक भी उच्च विद्यालय की प्रयोगशाला नहीं खुलती है. छात्रा-छात्राओं को प्रयोगशाला के उपकरण एवं इसके इपयोग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है.

खेल-कूद : राज्य सरकार ने खेल-कूद के विकास के लिए प्रत्येक उच्च विद्यालय को दो लाख की राशि प्रदान की. बेगूसराय जिले के किसी भी उच्च विद्यालय में जिम नहीं खुला और खेल-कूद पूर्णत: बंद है. विभागीय खेल-कूद कैलेन्डर की पूर्ति के लिए बाहरी छात्र-छात्राओं की टीम बनाकर प्रतियोगिता में भाग लेने भेज दिया जाता है. आयोजन की राशि का पदाधिकारीगण बंदरबांट कर लेते हैं.

बानगी के तौर पर जिले के सर्वोत्तम विद्यालयों में से एक मुख्यालय के कॉलेजिएट स्कूल की चर्चा करना लाजिमी होगा. पिछले 20 वर्षों से प्रयोगशाला नहीं खुली है. छात्रों को पुस्तकालय से किताब नहीं मिली हैं. कम्प्यूटर का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है. हमेशा खेल-कूद आयोजन के लिए चर्चित सर्वोत्तम खेल मैदान वीरान पड़ा है. दूसरी घंटी के बाद छात्रों का कक्षा से पलायन हो जाता है. अधिकांश शिक्षक समय का अनुपालन नहीं करते हैं. विभागीय पदाधिकारियों को अभिभावकों द्वारा सूचित करने पर भी निरीक्षण-पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जब जिला मुख्यालय के कालेजिएट विद्यालय का यह हाल है तो अन्य का क्या होगा.

जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव सुधाकर राय कहते हैं कि 'ज्यादा योगी मठ उजाड़' वाली कहावत स्थानीय विभागीय पदाधिकारियों पर लागू होती है. जिला स्तर पर इनकी संख्या तो बढ़ा दी गयी है. लेकिन इन्हें प्रशासन का अनुभव एवं विकास-योजनाओं की जानकारी नहीं है. कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल है. पुस्तकें कार्टून की शोभा बढ़ा रही हैं. प्रायोगिक उपकरण भी पैकेट में बंद रहकर अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं. खेलकूद का सामान किसी कमरे में बंद होकर अपनी किस्मत का रोना रो रहा है. किसी विद्यालय में 4-5 विषयों में एक भी शिक्षक नहीं है तो किसी विद्यालय में एक ही विषय के 4-5 शिक्षक कार्यरत है. विभागीय शासन-प्रशासन को माध्यमिक शिक्षा पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करने की जरूरत है तभी माध्यमिक शिक्षक अपने पुराने तेबर के साथ नये समृद्ध बिहार के निर्माण में योगदान दे सकेंगे. न जाने कब शिक्षा से जुड़े महापुरुषों की तंद्रा भंग होगी.

बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के छात्र कल्याण कोशांग के संयोजक डॉ. सुरेश प्रसाद राय कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार नियम 2010 एवं भारतीय संविधन द्वारा प्रदत्त अधिकारों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पूर्व से सृजित एवं स्वीकृत शिक्षक पद को जीवित करते हुए छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों को वेतनमान पर नियुक्त करें, विद्यालय का आधारभूत संरचना सुदृढ़ करे, रिक्त पदों पर वेतनमान में लिपिक अनुसेवक एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करे, निरीक्षण-पर्यवेक्षण व्यवस्था सुदृढ़ करे तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना सार्थक हो पाएगी.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

23 फरवरी-01 मार्च 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड

राज्यपाल से रार में आजम खान ने धर्म को घसीटा

सब सपा करा रही है...

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक से रार ठान कर साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. चुनाव आते-आते प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए सपा ने राज्यपाल का ही कंधा चुना है. राज्यपाल को पत्र लिख कर आजम खान ने उन पर प्रदेश में धार्मिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया है. प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान का अमर्यादित प्रहार लगातार तेज होता जा रहा है. राजनीतिक नब्ज जानने वाले लोग बताते हैं कि राज्यपाल और आजम के बीच के विवाद को सुनियोजित तरीके से तीखा बनाया जा रहा है. राज्यपाल के खिलाफ लगातार आग उगल रहे आजम खान के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत की ही गई थी कि आजम ने राज्यपाल को एक लम्बा पत्र लिख कर फिर से आग में घी डाल दिया है. समाजवादी पार्टी नाइक-आजम विवाद को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिशों में तेजी से लगी है और इसके लिए आजम खान को खुली छूट दे रखी है कि वे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की अवमानना करते रहें और इसे धर्म की धुरी पर खेलते रहें. आजम खान ने पत्र लिख कर उन सारी पुरानी छीछालेदर को फिर से दोहरा दिया है, ताकि राज्यपाल इस मसले पर बौखलाएं और समाजवादी पार्टी इसका सियासी मजा ले. सूत्रों का तो यह भी कहना है कि यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री के अमर्यादित बयानों से दुखी राज्यपाल वापस लौटने का मन बना रहे हैं. दिल्ली में प्रधानमंत्री से पिछले दिनों हुई उनकी मुलाकात को इसी बात से जोड़ कर देखा जा रहा है. सपा के एक नेता ने कहा कि नाइक-आजम विवाद जितना गहराएगा उतना ही सपा नेतृत्व को राहत मिलेगी, क्योंकि सपा नेतृत्व एक तीर से दोनों शिकार ढेर करना चाहता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की जीत पर आजम खान ने जिस तरह क्रीज छोड़ कर अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा की और बधाइयां दीं, उससे सपा नेतृत्व अंदर-अंदर काफी नाराज है. आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत आखिरकार समाजवादी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने वाली है. ऐसे में आजम खान की आप से बढ़ती पेंगें सपा नेतृत्व के लिए नागवार गुजर रही हैं.

बहरहाल, दिल्ली में आप की जीत पर आजम खान जितने प्रसन्न हैं उतने वे सपा की जीत पर भी नहीं हुए थे. आजम खान की सार्वजनिक प्रसन्नता उत्तर प्रदेश के वोटरों पर असर डालने वाली साबित होगी, क्योंकि उन्होंने इतना तक कह दिया है कि दिल्ली में आप को मिला प्रचंड जन समर्थन दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे देश का जनादेश है. आजम खान ने कहा कि दिल्ली में आप के पक्ष में आए चुनावी नतीजों से देश के अल्पसंख्यकों की लोकतंत्र के प्रति आस्था और बढ़ी है. उन्होंने कहा, हम सब एक परिवार हैं और नफरत, घृणा, अराजकता तथा धार्मिक स्तर पर भेद-भाव किया जाना असहनीय है. मुजफ्फरनगर जैसे कई दंगों का दंश झेल रही समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान का यह बयान बेधक है और कई संकेत भी देने वाला है. आप की जीत पर समाजवादी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को औपचारिक बधाई देते हुए आधिकारिक तौर पर केवल इतना ही कहा कि यह भाजपा के अहंकार की हार है.

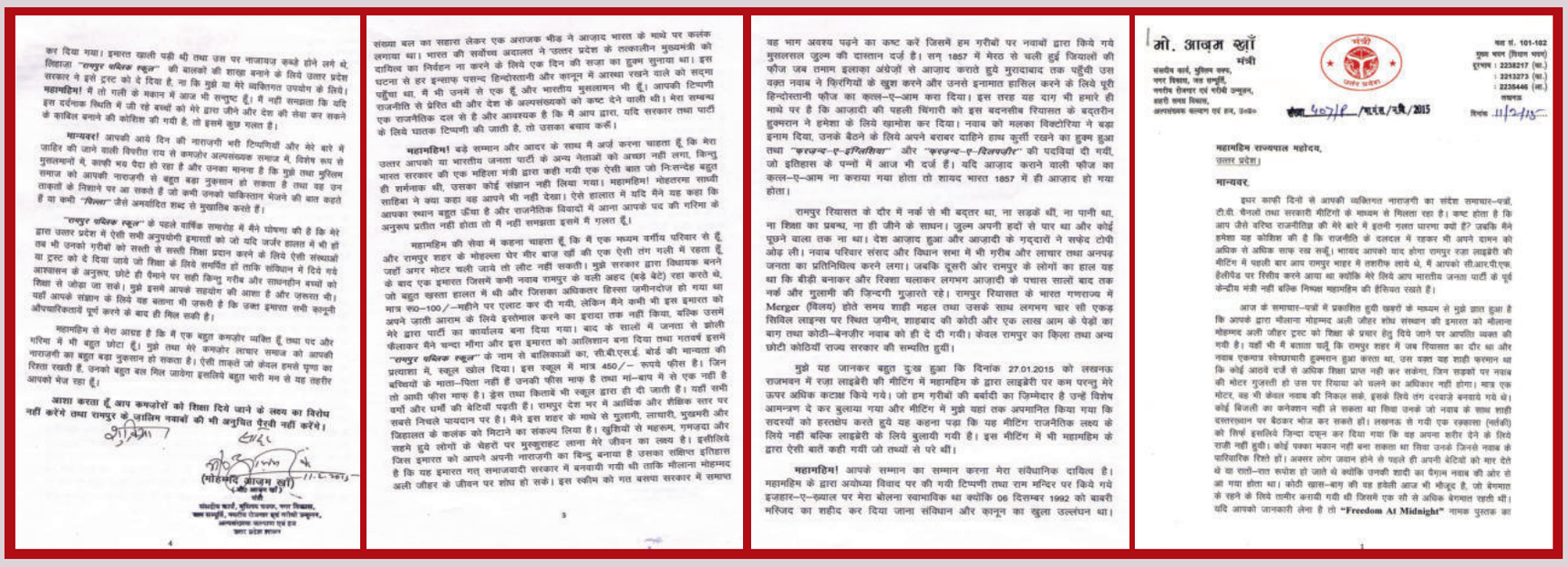

जहां तक राज्यपाल राम नाइक के खिलाफ आजम खान की बेजा टिप्पणियों का सवाल है, अभी पिछले ही दिनों राज्यपाल ने आजम खान की टिप्पणियों को उनकी गरिमा के खिलाफ बताया था. राज्यपाल ने कहा था कि आजम खान का इलाज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा मुखिया मुलायम सिंह ही करें. आपको याद ही होगा कि कुछ ही दिन पहले प्रदेश स्तर के एक भाजपा नेता ने आजम खान की दिमागी हालत खस्ता बताते हुए उन्हें बरेली जाकर इलाज कराने की सलाह दी थी. आजम खान की विवादास्पद बयानबाजियों के पीछे सपा नेतृत्व का संरक्षण है, यह इस बात से ही जाहिर हुआ है कि आजम खान के बयान को सपा के वरिष्ठ नेता उचित ठहरा रहे हैं. राज्यपाल राम नाइक से इस्तीफा मांगने के बारे में दिए गए विवादास्पद बयान पर सपा नेता व प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि आजम पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्होंने जो कहा है ठीक ही कहा है.

यह विवाद चल ही रहा था कि आजम खान ने राज्यपाल को चार पेज का खत लिख कर इस मामले को फिर से भड़का दिया. इस चार पेजी खत में आजम खान ने राज्यपाल का गुरु बनने की कोशिश की है और उन्हें इतिहास की शिक्षा दी है. अपने नेताजी का रामपुर में नवाबी सामंती हरकतों से भरा आलीशान जन्मदिवस समारोह मनवाने वाले आजम खान ने रामपुर नवाब की ऐतिहासिक अय्याशियों का हवाला देकर अपने निजी ट्रस्ट के लिए सरकारी जमीन और कोठियां कौड़ियों के मोल लेने की अपनी करतूत को वाजिब ठहराया है. आजम खान ने अपने पत्र के जरिए नवाब के बरक्स खुद को रामपुर के मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट किया है. अपने पत्र में उन्होंने राज्यपाल पर सीधे-सीधे आरोप लगाया है कि वे प्रदेश में धार्मिक भेदभाव की भावनाएं भड़का रहे हैं. आजम खान राज्यपाल पर इसलिए अधिक नाराज हैं, क्योंकि राज्यपाल ने आजम के निजी ट्रस्ट को सौ रुपये सालाना किराए पर सरकारी जमीन और सरकारी भवन लीज पर दिए जाने पर विरोध जाहिर किया था. उल्लेखनीय है कि सरकारी जमीन और भवन रामपुर में मुलायम का भव्य जन्मदिन मनाने पर आजम खान को रिटर्न गिफ्ट के बतौर दिया गया. विडंबना यह है कि जौहर अली ट्रस्ट को महज सौ रुपये की लीज पर 30 साल के लिए सरकारी जमीन दे दिए जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही हरी झंडी दिखाई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

आजम ने मुलायम को ही लपेटा

गुजरात के राजकोट में कुछ अहमकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति एक मंदिर में स्थापित कर दिए जाने का सीधा असर उत्तर प्रदेश में आजम खान पर पड़ा और उन्होंने मुलायम सिंह यादव का मंदिर बनाने की घोषणा कर दी. हालांकि प्रधानमंत्री ने अपनी मूर्ति स्थापित किए जाने के बारे में जानकारी मिलते ही नाराजगी जताई और तत्काल प्रभाव से मूर्ति हटवाने का आदेश जारी किया. इसके बाद आयोजकों ने कहा कि अब वहां पर भारत माता का मंदिर बनाया जाएगा. लेकिन आजम खान पर मोदी के मंतव्य और मूर्ति हटाने के फैसले का कोई असर नहीं पड़ा. उल्टे मंदिर और मूर्ति का असर उनके मस्तिष्क पर इतना अधिक गहरा गया है कि उन्होंने गुजरात में बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर की तर्ज पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का भी मंदिर बनवाए जाने का प्रस्ताव रख दिया. आजम ने प्रस्ताव दिया है कि मुलायम सिंह यादव का भी मंदिर बने. मंदिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने कि उनके पैतृक जिले इटावा में या उनका नवाबी जन्मदिवस मनाने वाले आजम के जिला रामपुर में बने, यह अभी तय नहीं हुआ है. आजम ने अपने प्रस्ताव में यह जरूर जोड़ा है कि मंदिर बनाने का अपना प्रस्ताव वे मुलायम सिंह यादव के समक्ष रखेंगे और यदि इस प्रस्ताव पर नेताजी अपनी सहमति देते हैं तो उनके भी मंदिर बनेंगे. यानी, मुलायम सहमति दें तो आजम खान उनके कई मंदिर बनवा सकते हैं. आजम ने कहा कि मुलायम सिंह भी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और उनके करोड़ों अनुयायी हैं तो फिर उनका मंदिर क्यों नहीं बने? जब अन्य जीवित नेताओं और अभिनेताओं के मंदिर बने हुए हैं तो फिर नेताजी का मंदिर क्यों नहीं? आजम ने कहा कि बशर्ते कि नेताजी इस बात की इजाजत दे दें. पार्टी के ही नेता कहते हैं कि मुलायम का मंदिर बनाने और इसके लिए मुलायम से सहमति लेने की बात कहने वाले आजम खान अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अपनी राजनीति में लपेटने की कोशिश कर रहे हैं. ■

पीएम से मिले तो कयास लगने शुरू

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले दिनों दिल्ली में हुई मुलाकात को लेकर कई चर्चाएं हैं. लोग यह भी कहते हैं कि सपा सरकार के मंत्री के अमर्यादित आचरण से क्षुब्ध राज्यपाल वापस लौटने का मन भी बना सकते हैं. राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से जो अंदरूनी बातें कीं, उसका तो कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर के मसलों पर हुई चर्चा का विषय जरूर सार्वजनिक तौर पर साझा किया गया. उन्होंने देश के परमवीर चक्र से सम्मानित 21 लोगों के भित्ति चित्र दिल्ली में योग्य स्थान पर स्थापित किए जाने के बारे में और अंडमान की सेलुलर जेल में स्वातंत्र्यवीर सावरकर की प्रतिमा की स्थापना का सुझाव रखा. राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि कुष्ठ पीड़ितों के लिए उन्होंने 2007 में जो याचिका संसद में प्रस्तुत की थी उस याचिका पर संसदीय समिति की सिफारिशों को अमल में लाया जाए. राम नाइक ने स्वच्छ गंगा अभियान के साथ-साथ शवों को गंगा नदी में प्रवाहित किए जाने से बढ़ते प्रदूषण की ओर भी प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया. राज्यपाल ने महाराष्ट्र के तारापुर परमाणु ऊर्जा परिकल्प के विस्थापित लोगों के पुनर्वास और उन्हें शीघ्र न्याय दिलाने का भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया. शीर्ष सत्ता गलियारे के कुछ जानकारों का कहना है कि यूपी के राज्यपाल और प्रधानमंत्री के बीच प्रदेश के कुछ जरूरी मसलों पर भी चर्चा भी हुई जिसमें आजम की बेजा टिप्पणियों का मसला भी शामिल है. राम नाइक ने अपनी नाराजगी जाहिर की. राम नाइक की इच्छा राजनीति की मुख्यधारा में फिर से उतरने की है, लेकिन दिल्ली सूत्रों ने कहा कि राम नाइक को यूपी में रुकने और स्थितियों का आकलन कर केंद्र को अवगत कराते रहने के लिए कहा गया है. ■

फतेह बहादुर और जुगल किशोर का परिवार भाजपा में शामिल

शत्रुंजय सिंह रैकवार

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की पुत्रवधू, पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह की पत्नी व गोरखपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष साधना सिंह और उनके बेटे विश्वास सिंह की राजनीतिक पहल से पूर्वांचल की राजनीति में सरगर्मी आ गई है. कांग्रेसी पिता के बेटे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता की पत्नी साधना सिंह ने अपने बेटे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर भविष्य की राजनीति में बनने वाले नए समीकरणों का ठोस संकेत दिया है. भाजपा में शामिल हुई साधना सिंह उस पूर्व मुख्यमंत्री की बहू हैं, जिन्होंने 1987 में अयोध्या के राम मन्दिर का ताला खुलवाया था. भाजपा को इस फैसले का फायदा मिलेगा. साधना सिंह के पति फिलहाल तो कैंपियरगंज से राकांपा के विधायक हैं, लेकिन आगे क्या होगा इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा रहा, पर चर्चा और कयासबाजियों का दौर चल रहा है. पूर्व मंत्री रह चुके पूर्वांचल के ताकतवर विधायक फतेह बहादुर सिंह ने 2010 में पडरौना विधानसभा के उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को जिता कर अपनी राजनीतिक ताकत का परिचय दिया था. आजादी के बाद पहली बार वहां से बसपा जीती थी. लेकिन 2012 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नेतृत्व की अराजकता के कारण वे बसपा से अलग हो गए थे. पूर्वांचल की राजनीति में बसपा के लिए यह जबरदस्त नुकसान वाला साबित हुआ था.

बहरहाल, राजनीतिक गलियारे के जानकार लोगों का कहना है कि 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले फतेह बहादुर ने भाजपा का दामन थामना चाहा था लेकिन गोरक्षपीठ से ही हरी झंडी नहीं मिलने के कारण उस समय ऐसा नहीं हो सका. फिर उन्होंने सपा से भी जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी. चुनाव सिर पर था, लिहाजा वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गए और जीत भी गए. सपा की लहर के विपरीत अपनी जीत दर्ज करा कर फतेह बहादुर सिंह ने अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की सियासी प्रतिष्ठा बचाई बल्कि सपा नेतृत्व की प्रतिष्ठा को भारी आघात भी पहुंचाया. बसपा को नुकसान तो पहुंच ही चुका था. सपा सरकार ने फतेह बहादुर के सामने कई किस्म की बाधाएं खड़ी कीं. पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी रहीं चिंता यादव की वजह से भी स्थानीय दिक्कतें बढ़ीं. तेजी से बदलते जा रहे राजनीतिक घटनाक्रम ने कांग्रेसी वीर बहादुर सिंह के परिवार के भाजपा की तरफ उन्मुख होने का रास्ता खोल दिया. क्षेत्र में चर्चाएं भी खूब होने लगी थीं. गोरक्षपीठ के प्रमुख व गोरखपुर के सांसद महंत आदित्यनाथ के कार्यक्रमों में फतेह बहादुर की मौजूदगी ने इसके संकेत देने शुरू कर दिए थे. हाल में [illegible] मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री के कार्यक्रमों में उनकी बढ़चढ़ कर [illegible] चर्चा में रही.

एनसीपी के मौजूदा विधायक होने के नाते भाजपा से सीधे जुड़ाव का रास्ता फिलहाल नहीं था. लिहाजा, फतेह बहादुर सिंह ने अपनी पत्नी साधना सिंह और बेटे विश्वास को भाजपा में शामिल करा दिया. इससे एक ही तीर से कई शिकार सध रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इससे पूर्वांचल में भाजपा को मजबूती मिली है और राजपूत समुदाय को संतुष्टि, जो बसपा और सपा के कारण घनघोर असंतुष्ट चल रहे थे. राजनीतिक प्रेक्षक बिल्कुल यह मानते हैं कि चुनाव के ऐन पहले फतेह बहादुर भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे और भाजपा के ही प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे. गोरखपुर के रवींद्र प्रताप सिंह उर्फ नन्हे सिंह ने आलोक विसेन कहते भी हैं कि साधना सिंह का भाजपा में आना तुरुप की चाल है. आगे-आगे देखिए होता है क्या.

फतेह बहादुर सिंह की पत्नी और बेटे के भाजपा में शामिल होने के साथ-साथ मायावती को दलित विरोधी बता कर उनके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले बसपा नेता जुगल किशोर की पत्नी दमयंती सिंह और पुत्र सौरभ सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए. जुगल किशोर दलित नेता हैं और बसपा से राज्यसभा सदस्य हैं. भाजपा के लखनऊ मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा सांसद जुगल किशोर की पत्नी दमयंती सिंह तथा उनके पुत्र सौरभ सिंह को पार्टी में शामिल कराया. सौरभ सिंह लखीमपुर की कस्ता सीट से बीते विधानसभा चुनाव में दावेदार भी थे. लेकिन मायावती ने अपनी पार्टी के नेता के बेटे को टिकट देने के लिए भी पैसे मांगे थे. इसी आरोप के साथ जुगल किशोर ने मायावती के खिलाफ विद्रोह किया. उक्त दो प्रमुख नेताओं के पारिवारिक सदस्यों के अलावा आजमगढ़ के बसपा नेता अमित तिवारी व बॉबी अवस्थी भी अपने समर्थकों के भाजपा में शामिल हो गए. अमित तिवारी बसपा के दिल्ली तथा बिहार के प्रभारी थे, लेकिन जुगल किशोर का साथ देते हुए उन्होंने भी मायावती के खिलाफ बगावत कर दी थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

बसपा की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता छिन सकती है

सूफी यायावर

राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से भी वंचित रह गई बहुजन समाज पार्टी अब धीरे-धीरे विलुप्त ही होने के रास्ते पर है. डॉ. अखिलेश दास, जुगल किशोर, दद्दू प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेताओं के बसपा से बगावत कर हटने के बाद सारे प्रमुख नेताओं के पार्टी त्यागने का रास्ता बनता जा रहा है. जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा, पार्टी से बाहर होने वाले नेताओं का नाम सुर्खियों में आता जाएगा. मायावती से बगावत करने वाले जुगल किशोर ने मीडिया से कहा भी था कि धीरे-धीरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य और सतीश चंद्र मिश्र जैसे वरिष्ठ नेता भी बाहर हो जाएंगे. जुगल किशोर ने भ्रष्टाचार से जमा की गई मायावती की अकूत सम्पत्ति के साथ-साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य और सतीश चंद्र मिश्र की भी अकूत सम्पत्ति का जिक्र किया था. जुगल किशोर ने आरोप लगाया था कि मायावती केवल विधानसभा टिकट देने में ही दो करोड़ रुपये नहीं लेतीं, बल्कि राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों के लिए भी पैसे लेती हैं. उन्होंने वीर सिंह को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाकर उनसे सौ करोड़ रुपये लिए और राजाराम को हरियाणा का प्रभारी बनाकर उनसे 50 करोड़ रुपये की सौदेबाजी करके उन्हें राज्यसभा में दोबारा भेजा. जुगल किशोर ने कहा था कि मायावती के रवैये से खिन्न 80 में से 70 विधायक बसपा छोड़ने को तैयार हैं. चुनाव में दो वर्ष बाकी होने के कारण वे अभी चुप हैं. उन्होंने कहा था कि पार्टी के कमजोर होने पर सबसे पहले नसीमुद्दीन व सतीश चंद्र मिश्र जैसे लोग ही बसपा छोड़ेंगे. इसके पहले हमेशा यह चर्चा चलती रहती थी कि बसपा में टिकट वितरण में और राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में कोई पार्दिशता नहीं रहती. डॉ. अखिलेश दास, जुगल किशोर और दद्दू प्रसाद के प्रकरण में यह आधिकारिक तौर पर उजागर हुआ कि बसपा नेता मायावती पर टिकट बेचने का जो आरोप लगता रहा, वह बेबुनियाद नहीं था. हाल ही में डॉ. अखिलेश दास ने भी आरोप लगाया था कि मायावती पैसे लेकर टिकट बेचती हैं. यहां तक कि राज्यसभा के लिए भी उनसे रकम मांगी गई थी. इसके बाद मायावती के करीबी दलित नेता और राज्यसभा सदस्य जुगल किशोर ने भी मायावती पर अखिलेश दास जैसे ही आरोप लगाए. पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने भी मायावती पर निशाना साधते हुए तमाम गंभीर आरोप लगा दिए. दद्दू ने कहा कि बसपा के डूबने से पहले मायावती उसे पूरी तरह बेचने में लगी हैं. कांशीराम के मिशन को छोड़ कर मायावती जो कुछ कर रही हैं उससे बसपा बचने वाली नहीं है. दद्दू ने भी मायावती पर करोड़ों रुपये में टिकट बेचने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांशीराम के मूल सिद्धांतों से हटकर अब वह दलित समाज को बेच रही हैं. बसपा में लोकतंत्र तो है ही नहीं, यहां तक कि विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तक के बोलने पर मायावती उन्हें सबके सामने डांट देती हैं. मायावती ने मौर्य का टिकट काटकर उनके कुशीनगर जाने पर भी रोक लगा दी थी. कभी बसपा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े वोट बैंक वाली पार्टी रही, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की हरकतों के कारण आज वह भयावह स्थिति में आ खड़ी हुई है. मायावती की दुर्दशा यह है कि घटते जन-आधार के साथ-साथ वे अपनी कोर टीम में भी अलोकप्रिय हो रही हैं. विधानसभा में बसपा को 80 सीटें मिली थीं. लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई. बसपा की हालत सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बिगड़ी है बल्कि उन राज्यों में भी वह कमजोर हुई है जहां कभी वह बड़ी ताकत रही है. लब्बोलुबाव यह है कि बसपा में भगदड़ जैसी स्थिति है. इस कारण भाजपा की बांछें खिल गई हैं. बसपा से निकाले जाने वाले या उसे छोड़ने वाले नेताओं की भाजपा शरणस्थली बनी हुई है. दिग्गज बसपा नेता जुगल किशोर, पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर और डॉ. अखिलेश दास के भाजपा में जाने की चर्चा के बीच बसपा से निकाले गए दारा सिंह चौहान ने भी कांग्रेस में जातेमजाते भाजपा का दामन थाम लिया है. दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दारा सिंह चौहान को भाजपा में शामिल कराया. कभी बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी रहे दारा सिंह चौहान 15वीं लोकसभा में बसपा संसदीय दल के नेता हुआ करते थे. बसपा में दारा सिंह की गिनती बेदाग नेताओं में हुआ करती थी. 2017 का विधानसभा चुनाव करीब आते-आते बसपा के कई और बड़े नाम भाजपा के साथ जुड़ सकते हैं. इसमें कुछ विधायक भी शामिल हैं. ■

अपराध के साये में राजधानी की जनता

वैष्णवी वंदना

यही घटना अगर देश की राजधानी में हुई होती तो अब तक एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया होता, लेकिन एक लड़की का अपहरण कर उसे आरी से काट कर मारे जाने की वीभत्स घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई तो कोई प्रशासनिक सुगबुगाहट ही दिखाई नहीं दे रही. कुछ सामाजिक संगठन और लड़की के परिवार वाले सड़क पर विरोध तो जता रहे हैं, लेकिन यह विरोध उस तरह तेवर नहीं पकड़ रहा कि पुलिस पर कोई कारगर सामाजिक दबाव बने. पुलिस घटना को तोड़-मरोड़ कर अपनी खाल बचाने की फिराक में ही लगी है. उत्तर प्रदेश अपराध के कब्जे में है. अभी कुछ ही दिन पहले एक वकील की बम मार कर हत्या कर दी गई थी. बसपा के विधायक और उसकी पत्नी ने एक इंजीनियर की बर्बर हत्या की थी और अब एक लड़की को नृशंसतापूर्व मारा गया. ये घटनाएं लखनऊ की हैं. पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं रोजाना दर्ज हो रही हैं.

पिछले दिनों लखनऊ में गणेशगंज इलाके से गौरी श्रीवास्तव नाम की लॉ छात्रा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई. उसकी क्षतविक्षत लाश बाद में मिली, तब पता चला कि गौरी को लकड़ी काटने वाली आरी से काटा गया था और उसके टुकड़े काट कर इधर उधर फेंक दिया गया था. पुलिस ने इस घटना का सनसनीखेज खुलासा करने का दावा किया और हत्या में इस्तेमाल में लाई गई आरी भी बरामद कर ली. लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस ने मामले को आनन-फानन निपटाने के चक्कर में तेलीबाग से खुद ही आरी खरीदी और उस पर खून लगा कर उसे हत्यारे से बरामद आरी दिखा दिया. जिस दुकान से पुलिस ने आरी खरीदी थी, उस दुकानदार ने पुलिस की करतूतों की कलई खोल दी. पीजीआई थाने के दो पुलिसकर्मी आरी खरीदने गए थे. तेलीबाग बाजार में हार्डवेयर की वह दुकान रवि चावला और उनके छोटे भाई पंकज चावला की है. दोनों पुलिसकर्मियों ने 50 रुपये में आरी खरीदी थी. इसके बाद तो पुलिस के खिलाफ विरोध खुल कर सामने आने लगा. कई सामाजिक संगठन सामने कूद पड़े और लड़की के परिवार वाले भी सड़क पर उतर आए. समाजसेवी डॉ. नूतन ठाकुर और उनके पति आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी गौरी हत्याकांड के खुलासे पर उठ रहे सवालों को लेकर सामने आ गए. नूतन ठाकुर ने खुद गौरी के परिजनों और हत्यारोपी हिमांशु की बहन डॉली को साथ लेकर आरी बेचने वाले चावला बंधुओं से मुलाकात की. जांच से गौरी के माता-पिता पूरी तरह असंतुष्ट हैं. उनका कहना है कि यह वारदात कोई अकेला शख्स कर ही नहीं सकता. पुलिस उन्हें तफ्तीश के बारे में कुछ भी नहीं बता रही है. यहां तक कि गौरी का जो मोबाइल फोन बरामद दिखाया गया है, उसमें पहले सिम कार्ड कुछ और था जबकि जो मोबाइल फोन वापस किया गया उसमे सिम कार्ड कुछ और है. फोन का सारा डेटा भी डिलीट पाया गया. गौरी की मां ने कहा कि वे अभियुक्त की आवाज फोन पर पहचान सकती हैं पर पुलिस ने ऐसा भी नहीं कराया.

गौरी हत्याकांड में उसके दोस्त हिमांशु प्रजापति को आरोपी बनाकर हिरासत में लिया गया है. हत्या में शक की सुई हिमांशु के अलावा किसी दूसरे-तीसरे शख्स पर अटकी है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही. पुलिस की यह हरकत तब है जब खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर और एसएसपी यशस्वी यादव को तलब कर जांच की जानकारी ली थी और पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया था.

गौरी हत्याकांड और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कई सामाजिक संगठन सड़क पर उतर आए हैं. सामाजिक संस्था वीरांगना के नेतृत्व में कई सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है. लेकिन पुलिस की कार्रवाई कोई सकारात्मक दिशा नहीं पकड़ रही. पुलिस इतनी अराजक हो गई है कि मृतक गौरी श्रीवास्तव की मां और उसके पिता शिशिर श्रीवास्तव व बुआ सहित परिवार के अन्य परिजनों को धरना में भी शामिल नहीं होने दिया, उन्हें एसएसपी ऑफिस में ही बिठाए रखा. डॉ. नूतन ठाकुर और उनके पति अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग और प्रदेश के डीजीपी के समक्ष अभियुक्त के परिवार वालों के मानवाधिकार उल्लंघन के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराई है. कथित अभियुक्त की बहन डॉली ने बताया है कि पुलिस ने परिवार की महिलाओं से अभद्रता की और दो सूटकेस बिना लिखापढ़ी के अपने साथ ले गए जिसमें कपड़े और गहने थे. अभियुक्त का मकान भी पुलिस ने बिना कोर्ट के आदेश के सीलबंद कर दिया, जिससे परिवार के लोग बाहर रहने को मजबूर हैं. डीजीपी को पत्र लिख कर यह मांग की गई है कि पुलिसिया जांच के संदेहास्पद पहलुओं की गहराई से छानबीन हो, गौरी के परिवारवालों को विवेचना का हिस्सा बनाया जाए ताकि उन्हें पुलिस तफ्तीश पर विश्वास हो सके और इस घटना में दोषी पाए गए सभी पुलिसवालों पर समुचित कार्रवाई हो.

उधर, वकील और इंजीनियर हत्याकांड में भी पुलिस ने कोई ठोस कामयाबी हासिल नहीं की है. इंजीनियर शिखर श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में तो सपा सरकार ने बसपा के दबाव में आकर मामले की जांच सीबीसीआईडी को दे दी. उत्तर प्रदेश में सीबीसीआईडी को जांच दिए जाने का मतलब ही होता है कि शासन अभियुक्त को बचाना चाहता है. सीबीसीआईडी के महानिदेशक को खत लिख कर इस एजेंसी पर लोगों का विश्वास स्थापित करने का अनुरोध किया गया है ताकि शिखर के अभिभावकों द्वारा सीबीसीआईडी पर व्यक्त किया जा रहा अविश्वास निर्मूल साबित हो सके.

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में वकील निखिलेंद्र गुप्ता की बम मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में राज्यपाल राम नाइक तक ने मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था के प्रति आगाह किया था. वकील को बम से मारे जाने की घटना के एक ही दिन पहले राजधानी लखनऊ के निशातगंज इलाके में बसपा विधायक विजय कुमार और उसकी शिक्षा अधिकारी पत्नी मृदुला आनंद ने एक युवा इंजीनियर शिखर श्रीवास्तव की बर्बर हत्या कर दी थी. इंजीनियर को पहले चाकुओं से गोदा गया, फिर गोली मारी गई और बाद में गाड़ी से कुचला गया था. इंजीनियर भी बहराइच के कांग्रेस नेता व जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष दिनेशचंद्र श्रीवास्तव का बेटा था. हत्या के पीछे मृदुला आनंद द्वारा इंजीनियर से घूस लेने के साथ-साथ रंजिश के कई कारण बताए जा रहे हैं. लेकिन पुलिस ने इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की. अभियुक्त विधायक और उसकी पत्नी समेत पांच नामजद लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया. हत्यारोपी विधायक विजय कुमार गोरखपुर जिले के बांसगांव से बसपा विधायक हैं. वे इंजीनियर की हत्या की घटना के बाद भी राजधानी में खुलेआम देखे जाते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें छुआ तक नहीं. अब तो सीबीसीआईडी को जांच देकर सरकार ने मामला ही निपटा दिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

अखिलेश यादव की मांग

राष्ट्रीय विकास परिषद भंग हो

अंशु दीनमणि

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय विकास परिषद समाप्त किए जाने की मांग की है. राष्ट्रीय विकास परिषद के औचित्य पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीति आयोग के कामकाज और उसकी उपादेयता पर भी सवाल उठाया है. मुख्यमंत्री ने नीति आयोग को लेकर तमाम किस्म की आशंकाएं सामने रखी हैं. अखिलेश ने कहा है कि राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के बीच तालमेल कैसे कायम होगा और पिछड़े व कमजोर राज्यों को प्राथमिकता पर रखते हुए उन्हें संसाधनों के हस्तान्तरण का कार्य कैसे और किस संस्था के जरिए किया जाएगा, नीति आयोग के नए स्वरूप से यह स्पष्ट नहीं है. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद को अनौचित्यपूर्ण करार दिया है और कहा है कि नीति आयोग की शासी परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का स्वरूप और उद्देश्य करीब-करीब समान है. इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में भी प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. दोनों संस्थाओं को समानान्तर रूप से बनाए रखना औचित्यपूर्ण नहीं है. उल्लेखनीय है कि अभी पिछले ही दिनों दिल्ली में नीति आयोग की पहली बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (पश्चिम बंगाल छोड़ कर) शरीक हुए थे.

उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति आयोग से केंद्रीय बजट योजना का 50 फीसदी हिस्सा एकमुश्त उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री से मांग की है, जिससे राज्य सरकार स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के मुताबिक योजनाएं लागू कर सके. उत्तर प्रदेश सरकार की शिकायत है कि प्रदेश की जरूरतों और समस्याओं पर केंद्र सरकार संजीदगी से ध्यान नहीं दे रही है. प्रदेश सरकार नीति आयोग में अपना सीधा प्रतिनिधित्व भी चाहती है. नीति आयोग के कारगर तरीके से धरातल पर उतरने तक पूर्ववर्ती वार्षिक योजना व्यवस्था को फिलहाल बनाए रखने की आवश्यकता बताई गई है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि दूरगामी परिणाम वाली रणनीति के तहत 10-15 वर्षों की दीर्घकालीन योजनाएं बनाना वर्तमान परिदृश्य में आवश्यक तो है, लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं समयबद्ध ढंग से बनाने की मौजूदा प्रणाली को बनाए रखना उचित होगा.

इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की अवस्थापना परियोजनाओं के काम की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप का गठन किया है. इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने केंद्र से भी प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप बनाने की मांग की है, जो केंद्र के पास लम्बित राज्य के विभिन्न प्रस्ताव और अपेक्षित स्वीकृतियों को गति दे और लागू कराए. राज्य ने केंद्र के उक्त ग्रुप में राज्य सरकार के अधिकारियों को भी सम्मिलित करने की मांग की है. उल्लेखनीय है कि लखनऊ मेट्रो की सैद्धान्तिक सहमति और बजट प्रावधान दोनों ही केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में ही किए जा चुके हैं, लेकिन इसकी मंजूरी केंद्र सरकार के स्तर पर काफी दिनों से लम्बित चल रही है, जबकि समस्त औपचारिकताएं राज्य सरकार ने पूरी कर दी हैं. नीति आयोग के समक्ष प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की बदहाली का मसला भी उठाया गया है. प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों का उचित रख-रखाव नहीं हो रहा है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ लखनऊ में हुई बैठक के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्गों की बेहतरी के लिए केंद्र ने कोई कदम नहीं उठाया है. कोल ब्लॉक का आवंटन नहीं होने के कारण राज्य में बिजली उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है. इसके साथ ही केंद्रीय विद्युत परियोजनाओं से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, विभिन्न प्रोजेक्टों के पर्यावरण क्लीयरेन्स जैसे मामले भी केंद्र सरकार के पास लम्बित हैं, लेकिन केंद्र सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है. इस मामले में यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार विकास योजनाओं पर बात बहुत करती है लेकिन जमीनी स्तर पर उसे उतारने में ढीली है. केंद्र की सारी पहल अभी तक इरादों तक ही सीमित है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-263 के अधीन पहले से ही अन्तर्राज्यीय परिषदों का गठन है, वहीं राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदें भी गठित हैं. हाल ही में लखनऊ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी हुई थी. लिहाजा, इन्हीं क्षेत्रीय परिषदों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सुदृढ़ करते हुए उन्हें और प्रभावशाली बनाने की जरूरत है. क्षेत्रीय परिषदों के अधिकार और कार्य क्षेत्र में किस प्रकार विभाजन होगा यह भी अभी स्पष्ट नहीं है. नीति आयोग की बैठक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एजेंडा तैयार करने वाले अधिकारियों में से एक ने कहा कि विकास की योजनाओं के मसलों में केंद्र और राज्य के बीच कोई संवाद नहीं रहता, तो विकास क्या होगा. उन्होंने कहा कि कुछ केंद्रीय कार्यक्रम ऐसे भी हैं जिनकी कठिन शर्तों और प्रतिबन्धों के चलते मात्र कुछ चुनिंदा राज्य ही उनका लाभ उठा पाते हैं. राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन शर्तों और प्रतिबन्धों को लचीला बनाना जरूरी है, लेकिन केंद्र इस पर ध्यान ही नहीं देता. वित्तीय संसाधनों के आवंटन में विवेक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पारदर्शी तरीके से वस्तुपरक मानक के जरिए राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए. इस बंटवारे में पिछड़े क्षेत्रों और राज्यों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

प्रमुख सचिव स्तर के एक अधिकारी ने कहा कि राज्यों को विकास योजनाओं संचालित करने के लिए केंद्र से स्थानान्तरित होने वाले संसाधनों की निगरानी के लिए जो भी नई संस्था बने उसे पारदर्शी और वस्तुपरक होना चाहिए और उसे राज्यों के पिछड़ेपन, गरीबी को प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई करनी चाहिए. फिलहाल यह स्थानान्तरण गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के आधार पर किया जाता है. भविष्य में इसमें संशोधन प्रस्तावित है, इसीलिए उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में संशय की स्थिति बनी हुई है. उक्त अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल के बरक्स प्रदेश सरकार द्वारा पहले से ही अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित कर रही है. लेकिन ये योजनाएं धरातल पर दिख क्यों नहीं रही हैं? इस सवाल पर वे चुप्पी साध गए. उन्होंने सोलर पावर जेनरेशन परियोजना समेत तमाम योजनाओं के नाम तो गिनाए लेकिन जमीन पर दिख रही बदतर हालत की वजहों के बारे में कुछ नहीं बता पाए.

बॉक्स

देश की नियति तय करेगा नीति आयोग

योजना आयोग की स्थापना जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में 1950 में हुई थी. 64 साल के इतिहास में पंचवर्षीय और सालाना योजनाएं तैयार करने वाला योजना आयोग अब इतिहास का अध्याय रह गया है, जिसने 25 रुपये और 32 रुपये में ग्रामीण और शहरी गरीब की परिभाषा रच दी थी. अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया (नीति) भावी चुनौतियों से निबटेगा. नए योजनाकार केंद्र सरकार की 66 योजनाओं की संख्या घटाकर 10 किए जाने पर विचार कर रहे हैं. मौजूदा योजनाओं में से कुछ खत्म हो सकती हैं और कुछ राज्यों के कंधे पर जा सकती हैं. केंद्रीय योजनाओं के लिए 2014-15 में 3,38,562 करोड़ रुपये का बजट था. यह राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 से दोगुनी है. पिछले साल योजनाओं की संख्या घटाकर 147 से 66 की गई थी. मुख्यमंत्रियों के तीन उप-समूह इस संबंध में फैसला करेंगे. केंद्र की योजनाओं में कटौती से उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों की केंद्र से नाराजगी और बढ़ेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस का मिशन-2017 संकट में

राजकुमार शर्मा

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) की भारी जीत और कांग्रेस की 62 सीटों पर जमानत जब्त होने और शून्य पर सिमटने से प्रदेश कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसके कांग्रेस भाजपा के लिए सबक बताया. दिल्ली में जनता के इस तरह बदले हवा के रूख ने भीतर ही भीतर कांग्रेस को उसका मिशन-2017 संकट में दिख रहा है. यही बात मुख्यमंत्री हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत जो उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रही हैं, उनके द्वारा धर्मनगरी हरिद्वार में दिए गए भाषण से साफ झलका. हरिद्वार के पार्टी कार्यकर्ता रेणुका रावत से मुलाकात करने आए थे. इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी कार्यकर्ता को निराश होने की जरूरत नहीं है. मिशन 2017 को लेकर सभी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें. सरकार और पार्टी एक साथ मिलकर काम कर रही है. कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे राज्य के विकास के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएं. रेणुका ने कहा कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता है. कार्यकर्ताओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए समय- समय पर उनके साथ इस तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी. रेणुका रावत ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की महत्वपूर्ण धुरी होते हैं. उनकी समस्याओं का निदान व उचित सम्मान हमारी प्राथमिकता है. कांग्रेस नेता रेणुका रावत ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करने में जुट जाए. उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजों ने यह दिखा दिया है कि लोग पाखंड को पसंद नहीं करते और अच्छी छवि के लोगों पर भरोसा करते हैं. दिल्ली चुनाव के नतीजों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप के पक्ष में व्यापक जनाधार मिलने के बाद कांग्रेस व भाजपा को अपनी पराजय पर सोचना चाहिए. हार कारणों का पता लगाना चाहिए. इससे भाजपा व कांग्रेस दोनों की पराजय हुई. कुंजवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी है. कुंजवाल ने कहा कि उत्तराखंड में फिलहाल कोई तीसरा विकल्प नहीं है बावजूद इसके सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को ईमानदारी से धरातल पर काम करना चाहिए और पाखंड व धोखेबाजी से बचना होगा, तभी प्रदेश का विकास होगा. कुंजवाल ने केजरीवाल को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की है कि दिल्ली की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, वे उस पर खरा उतरेंगे. दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं की नींद उड़ा दी है, प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा. अधिकतर पार्टी के वरिष्ठ नेता मीडिया से बात करने में कतराते दिखे, कार्यकर्ताओं ने माना कि पार्टी में जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई, उसी से दिल्ली में भाजपा की करारी हार हुई है. लिहाजा यदि पार्टी को प्रदेश में मिशन-2017 में कामयाब करना है तो केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के मामले में सूझबूझ के साथ भविष्य की रणनीति तैयार करनी होगी, वरना प्रदेश में भी भाजपा का काफी बुरा हाल होगा. पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब समय आ गया है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के किसी भी एक सांसद को मोदी मंत्रिमंडल में स्थान दिलाने की वकालत करे. ताकि कार्यकर्ताओं में जिस तरह से निराशा के भाव छाए हैं उन्हें खत्म किया जा सके. प्रदेश की जनता को भी लग रहा है कि यहां के लोगों ने प्रदेश की पांचों सीटें बीते लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की झोली में डाल दी. बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किसी सांसद को अपने मंत्रिमंडल में स्थान देना उचित नहीं समझा. जो उनकी प्रदेश के प्रति उदासीनता दिखाता है और उनके तानाशाह रवैया का संकेत है, जो आम जनता को पसंद नही आ रहा है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश भाजपा को अब नए अध्यक्ष की आवश्यकता है. नया अध्यक्ष ही प्रदेश में पार्टी को संजीवनी प्रदान कर सकता है, नया अध्यक्ष पार्टी को जल्द ही मिलना चाहिए, वरना जितनी देर होगी उतनी ही प्रदेश में पार्टी कमजोर होती चली जाएगी. इसका असर मिशन-2017 में होने वाले विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा. दिल्ली चुनाव से प्रदेश भाजपा के अधिकतर नेता सदमे में हैं. कार्यकर्ताओं में निराशा के भाव हैं. इसलिए अब बिना देर किए ही भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को संगठन को मजबूत करने के मकसद से सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है. मिशन-2017 में भाजपा को कामयाबी मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर की कौड़ी सिद्ध होगी.

प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने कहा कि दिल्ली में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस सहित सभी पार्टियां एक हो गई. इसकी वजह से दिल्ली में भाजपा की हार हुई. केंद्रीय नेतृत्व की पूरे मामले पर नजर है और जल्द ही वह भविष्य की रणनीति भी तय करेगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव परिणामों का प्रदेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा. प्रदेश में भाजपा की ताकत बढ़ रही है. नए सदस्य भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं. इसलिए मिशन-2017 पर दिल्ली चुनाव का कोई असर नहीं दिखेगा. हर भाजपा कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है. इसलिए चिंता जैसी कोई बात नहीं है. पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं. प्रदेश में तो कांग्रेस से आम आदमी परेशान है, कांग्रेस ने प्रदेश के विकास के लिए अब तक किसी तरह की कोई प्लानिंग ही नहीं की है. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा-उत्तराखंड में भाजपा की ताकत बढ़ रही है. लेकिन सच्चाई तो यह है कि मिशन 2017 पर पानी फेरने का काम अपने झूठे अहम में चूर भाजपा के दिग्गज आज भी जनता से दूरी बना कर कर रहे है जो इनके लिए आत्मधाती सिद्ध हो सकता है.

आप की जीत की खुशी राजधानी में भी मनी

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत का जश्न देवभूमि उत्तराखंड में भी मनाया गया. जीत की खुशी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजधानी में होली-दीवाली एक साथ मनाई. अबीर-गुलाल भी उड़ाया और जमकर आतिशबाजी भी की. विजय जुलूस निकालकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आम जनता में मिठाई भी बांटी. आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता कुंवर जपेन्द्र सिंह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में आप पार्टी को मिली जीत ने साबित कर दिया है कि यह जीत आम आदमी और उनके मुद्दों की जीत है. उन्होने कहा कि भाजपा व कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त जनता को आम आदमी पार्टी के रूप में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प दिखने लगा है. देश की राजधानी दिल्ली से पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत पर समाजवादी पार्टी ने भी खुशी जताई. सपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. एसएन सचान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनोद बड़थ्वाल, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गुलफाम अली आदि पदाधिकारियों ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा व कांग्रेस का सफाया कर दिया है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच से 26 इंच का हो गया है. चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि खोखले वादे ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकते हैं और न ही जनता को इस तरह के वादे पसंद हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव मेंकांग्रेस का सूपड़ा साफ होने और भाजपा का केवल तीन सीटों पर सिमट जाने से एक बात जाहिर हो गई है कि जनता को नया राजनीतिक विकल्प चाहिए. ■

मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख़

रेनू शर्मा

हरिद्वार, टिहरी व ऊधम सिंह नगर के बाद स्वास्थ्य विभाग में हुए करोड़ों रुपये के तेल बिल घोटाले में मुख्यमंत्री के दखल के बाद देहरादून में भी मुकदमा दर्ज हो गया है. मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून डा. एसपी अग्रवाल ने कोतवाली में मैसर्स उनियाल टूर एंड ट्रवेल्स पंडितबाड़ी व मैसर्स काला टूर एंड टवेल्स मथुरावाला के साथ ही दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. उनियाल टूर एंड ट्रवेल्स पर फर्जी बिलों के आधार पर 5 लाख दो हजार पांच सौ रुपये जबकि काला टूर एंड ट्रेवल्स पर 22 लाख 23 हजार रुपये हड़पने का आरोप लगाया गया है. उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपये का फर्जी तेल बिल घोटाले का खुलासा हुआ था. जिसमें पिछले पांच साल के दौरान ऊधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार जिलों के सीएमओ कार्यालयों एवं कई बड़े अस्पतालों से सीएमएस आफिस से फर्जी आदेशों के आधार पर करोड़ों रुपये के पेट्रोल बिलों का भुगतान ट्रवेल एजेंसियों को किया गया. निदेशक ललित मोहन गुसाई के नेतृत्व में जब विभाग ने जांच कमेटी बनाई तो जांच में पता चला कि मुख्यमंत्री के आदेश व तेल बिल फर्जी थे. इस मामले को मुख्यमंत्री ने मीडिया में आयी खबरों का स्वयं संज्ञान लेते हुए घोटाले बाजों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है. इस घोटाले में प्रदेश में विभिन्न जिलों में तैनात 11 नये-पुराने सीएमओ व सीएमएस को दोषी करार दिया गया है. विभागीय जांच में उन्हें गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाया गया है. शासन स्तर पर जांच रिपोर्ट लंबित रहने पर विगत वर्ष दिसंबर में स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ओम प्रकाश को पत्र लिखकर तेल बिल घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए थे. मुकदमा दर्ज करने से पहले शासन ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच बैठा दी. इसके साथ ही मुकदमा दर्ज कराने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से फाइल मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजी गई थी. मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद शासन ने महानिदेशक स्वास्थ्य को मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए. इसके बाद इसमें एक और पेंच फंसा था कि मुकदमा अलग-अलग जिलों में दर्ज कराया जाए या एक साथ, इसके लिए डीजी ने शासन से राय मांगी थी. शासन से निर्देश मिलने के बाद डीजी हेल्थ ने एक हफ्ते पहले देहरादून सीएमओ, प्रमुख अधीक्षक दून अस्पताल, सीएमओ टिहरी, सीएमएस कोरोनेशन, ऋषिकेश, सीएमओ हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर के सीएमओ को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये थे. हरिद्वार, टिहरी व ऊधम सिंह नगर के सीएमओ ने मुकदमा दर्ज कर दिया था. देहरादून के सीएमओ डा. एसपी अग्रवाल ने कोतवाली में घोटाले के संबंध में ट्रवेल एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है. डा. अग्रवाल ने मैसर्स उनियाल टूर एंड ट्रवेल्स पंडितवाड़ी व मैसर्स काला टूर एंड ट्रवेल्स मथुरावला के साथ ही दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. इसके साथ ही दो अन्य लोगों पर भी फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है. फर्जी तेल बिल घोटाले में कोरोनेशन अस्पताल की सीएमएस ने भी थाना डालनवाला में मुकदमा दर्ज किया है. उन्होंने काला टूर एंड ट्रवेल्स मोथरोवाला के खिलाफ फर्जी बिलों के आधार पर लाखों रुपये हड़पने का आरोप लगाया है. सीएमएस डा. भारती राणा ने कहा कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. ■

> नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे कई ऐसे भी पूर्व मंत्री हैं, जिन पर लैकफेड घोटाले में शामिल होने का आरोप तो लगा लेकिन उन्हें छुआ तक नहीं गया. आरोप है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तीन एग्रीकल्चर फर्टीलाइजर टेस्ट लेबोरेट्रीज के निर्माण, 15 पोस्ट मॉर्टम हाउसों के निर्माण और दो प्लालस्टिक सर्जरी सेंटर्स के लिए 12 करोड़ रुपये लैकफेड को जारी किए थे. इसी तरह मायावती सरकार में मंत्री रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर आरोप है कि उन्होंने 10 होम्योपैथी अस्पताल और एक हॉस्टल के निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ रुपये लैकफेड को जारी किए थे.

लैकफेड घोटाला

सपा ने मायावती के भ्रष्ट मंत्रियों को बचाया

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश के चर्चित लैकफेड (लेबर एंड कंस्ट्रक्शन को-ऑपरेटिव फेडरेशन) घोटाले में सात लोगों को सजा तो हुई, लेकिन लचर जांच के कारण घोटाले के सारे सूत्रधार बाइज्जत बरी हो गए. इनमें मायावती-काल के कई मंत्री और आला नौकरशाह शामिल हैं. लैकफेड घोटाले की जांच में संदेहास्पद भूमिका अदा करने वाले एसआईबी (को-ऑपरेटिव) के अतिरिक्त महानिदेशक रहे सुब्रत त्रिपाठी पर खुलेआम उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं, लेकिन शासन की संदेहास्पद भूमिका पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है. लैकफेड घोटाले के कई प्रमुख अभियुक्तों के बरी होने और कोर्ट द्वारा लचर विवेचना साबित होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिख कर एसआईबी (को-ऑपरेटिव) के तत्कालीन एडीजी सुब्रत त्रिपाठी की भूमिका की जांच कराने की मांग की है. लेकिन उन्होंने यह मांग नहीं की कि मायावती-काल के भ्रष्टाचार मामलों में फंसे नेताओं और आला नौकरशाहों को बचाने के लिए समाजवादी सत्ता के किस स्तर से जांच एजेंसियों को दबाव में लिया जा रहा है. स्वाभाविक है कि यह जांच सीबीआई ही कर सकती है.

जांच में दबाव की बातें सामने आ भी चुकी हैं. जांच में शामिल रहे डीएसपी आदित्य प्रकाश गंगवार को एसपी बना दिया जाना और जांच की फाइलों पर एडीजी व एसपी के एकाधिकार के साथ-साथ एसआईबी (को-ऑपरेटिव) के आईजी आनंद स्वरूप को जांच से अलग रखना और फिर अचानक मानवाधिकार प्रकोष्ठ में उनका तबादला कर दिए जाने जैसी हरकतें शासन की सरपरस्ती के बिना नहीं हो सकतीं. एडीजी के भांजे द्वारा लैकफेड घोटाले के मुजरिमों से वसूली की भी शिकायतें रही हैं. इन तथ्यों के आधार पर लैकफेड घोटाले की लचर विवेचना करने वाले विवेचना अधिकारी, एसपी आदित्य प्रकाश गंगवार और एडीजी सुब्रत त्रिपाठी की भूमिका की जांच कराने का अनुरोध किया गया है.

मायावती की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा लैकफेड घोटाला मामले में भी अभियुक्त थे. लेकिन उन पर सपा सरकार की मेहरबानियां कोई छुपी हुई बात नहीं है. लैकफेड घोटाले की जांच कर रहे कोआपरेटिव सेल के महानिदेशक सुब्रत त्रिपाठी को अचानक पद से हटा दिए जाने और उनसे आर्थिक अनुसंधान शाखा यानी ईओडब्लू का अतिरिक्त चार्ज भी छीन लिए जाने के पीछे शासन की मंशा क्या थी, यह बिल्कुल साफ है. सहकारिता विभाग के इस घोटाले में कई मंत्री और अफसर जांच के घेरे में थे और कई पूर्व मंत्रियों को जेल तक जाना पड़ा था. लैकफेड को निर्माणदायी संस्थान बनाने में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. इसके एवज में लैकफेड ने कुशवाहा के गांव में चार किलोमीटर की सड़क 24 घंटे में ही बना दी थी.

बहरहाल, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने लैकफेड घोटाला मामले के सात दोषियों को सजा सुनाई. कोर्ट ने लैकफेड के प्रबंध निदेशक रहे ब्रह्मप्रकाश को 10 साल की कैद की सजा दी. साथ ही उन पर 1.30 करोड़ रुपये का जुर्माना भी ठोका. इसके अलावा अदालत ने लैकफेड के महाप्रबंधक रहे पंकज त्रिपाठी को 10 साल की कैद और 90 लाख का जुर्माना, चीफ इंजीनियर गोविंद शरण श्रीवास्तव को 10 साल की कैद और 90 लाख का जुर्माना, इंजीनियर दिनेश साहू को सात साल की कैद और 50 लाख का जुर्माना, इंजीनियर अजय कुमार को सात साल की कैद और 25 लाख का जुर्माना, इंजीनियर संजय कुमार को पांच साल की सजा व पांच लाख का जुर्माना और लेखाकार अनिल कुमार अग्रवाल को तीन साल की कैद और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. लैकफेड घोटाले का मुख्य आरोपी तत्कालीन चेयरमैन सुशील कटियार अबतक गिरफ्तार नहीं हुआ है. उसे भगोड़ा घोषित कर उसकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है. लैकफेड घोटाला मामले में तत्कालीन बसपा सरकार के चार मंत्रियों समेत सात लोगों को साक्ष्यों के अभाव में पहले ही बरी किया जा चुका है. कई मंत्रियों पर तो कानूनी कार्रवाई की औपचारिकता भी नहीं निभाई गई.

उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सहकारिता महासंघ (लैकफेड) में हुए करोड़ों के घोटाले में विशेष न्यायाधीश लल्लू सिंह की अदालत ने मायावती सरकार के मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा, बादशाह सिंह, रंगनाथ मिश्र और चन्द्रदेव राम यादव के साथ-साथ तत्कालीन बैंक प्रबंधक दीपक दवे, प्रवीण कुमार सिंह और तत्कालीन आईएएस अधिकारी रामबोध मौर्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. उल्लेखनीय है कि लैकफेड के तत्कालीन महाप्रबंधक (प्रशासन) ने मायावती सरकार के चारों मंत्रियों समेत 14 लोगों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कराया था. 746 पन्नों के फैसले में विशेष न्यायाधीश लल्लू सिंह ने खास बात यह कही है कि भ्रष्टाचार से विकास की परियोजनाएं बेअसर हो जाती हैं और देश प्रगति के रास्ते से भटक जाता है. जनता विभिन्न प्रकार के अभावों में जीने के लिए मजबूर हो जाती है. जिन लोक सेवकों पर विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन व उसे संवारने का परम दायित्व होता है, अगर वही अपने दायित्व से विचलित होकर स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज व देश पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा. सभी समाज का विकास रुक जाएगा. कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण का सहारा लेता है तो उसे कठोरता से दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाना जांच एजेंसियों का प्राथमिक दायित्व है.

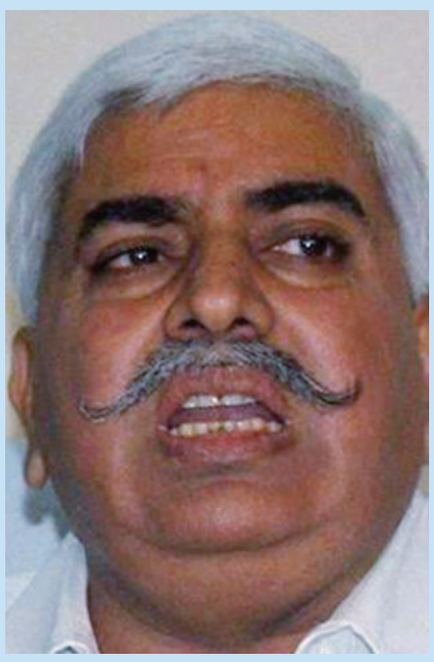

लैकफेड मामले में मायावती काल के कई मंत्री गिरफ्तार भी किए गए थे लेकिन साक्ष्यों के अभाव में आखिरकार बरी होते गए. मायावती सरकार में श्रम मंत्री रहे बादशाह सिंह को गिरफ्तार किया गया था. बादशाह सिंह पर रिश्वत लेने का आरोप था. लैकफेड के अधिशासी अभियंता व घोटाले के अभियुक्त दिनेश कुमार साहू का आरोप था कि बादशाह सिंह ने वर्ष 2010 में मजदूरों लिए शरणस्थल बनाने का ठेका दिल-वाने के लिए पांच करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी. लैकफेड को वह ठेका नहीं मिलने के बावजूद सिंह ने रिश्वत की वह रकम नहीं लौटाई थी. लेकिन जांच एजेंसी मंत्री की इस रिश्वतखोरी को साबित नहीं कर पाई. एसआईबी ने पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी से भी पूछताछ की थी. मायावती सरकार के सात और मंत्रियों को जांच के घेरे में लिया गया था. जिनमें पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, अनीस अहमद, नंद गोपाल नंदी, चौधरी लक्ष्मी नारायण, अवधपाल सिंह यादव, सदल प्रसाद निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ रुपये लैकफेड को जारी किए थे. मायावती सरकार के मंत्री रहे अवध पाल सिंह ने आठ पशु चिकित्सालयों के निर्माण के लिए 68 लाख रुपये लैकफेड को जारी किए थे. तत्कालीन प्राविधिक शिक्षा मंत्री सदल प्रसाद ने मंत्री रहते हुए आईटीआई में 12 छात्रावास बनवाने के लिए लैकफेड को 11 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था. तत्कालीन मंत्री अनीस अहमद अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सप्लाई के लिए 18 करोड़ रुपये से ज्यादा का काम लैकफेड को दिया था. तत्कालीन मंत्री चंद्रदेव राम ने भी लगभग 31 करोड़ रुपये अपने विभाग से लैकफेड को दिलवाए थे. चंद्रदेव राम तो गिरफ्तार भी किए गए थे. तत्कालीन मंत्री रंगनाथ मिश्रा ने प्रदेश के 25 उच्च प्राथमिक स्कूलों के निर्माण और नवोदय विद्यालयों में साइनबोर्ड लगाने के लिए लैकफेड को 16 करोड़ रुपये जारी किए थे. रंगनाथ मिश्र पर यह भी आरोप है कि उनके द्वारा लाइजनिंग के तहत जुलाई 2010 के अंतिम सप्ताह में लैकफेड के अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार सिंह व अवधेश कुमार सिंह के समक्ष सवा करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में लेकर 14 जिलों में 25 विद्यालयों के निर्माण कार्य के लिए अपने हस्ताक्षर से कार्यदायी संस्था लैकफेड को नामित किया था. रंगनाथ मिश्र भी गिरफ्तार होकर लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं. मंत्रियों ने लैकफेड पर सारे अनुग्रह रिश्वत लेकर किए थे. लैकफेड घोटाला मामले में पूर्व मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के खिलाफ जांच भी हुई थी. एसआईबी ने जांच में पाया था कि मंत्री रहते हुए चौधरी लक्ष्मी नारायण ने व्यवसायिक शिक्षा विभाग से रिश्वत लेकर 31 करोड़ रुपये जारी किए थे. लेकिन जैसा हमेशा होता है कि मंत्रियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वे बरी कर दिए गए. कई मंत्रियों को कार्रवाई की औपचारिकताओं से भी नहीं गुजरना पड़ा. भारतवर्ष का कानून यही है कि सामर्थ्यवानों की रिहाई हो जाती है और मामूली औकात वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को जेल की सजा भुगतनी पड़ती है. ■

कलह में खुल गई कलई

बांदा की एक सड़क के ठेके में हुई रिश्वतखोरी ने बसपा सरकार के मंत्रियों में इतनी कलई बोई कि आखिरकार लैकफेड घोटाले की कलई खुल गई. इसी कलह के नतीजतन लैकफेड घोटाले की जांच के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया था. महोबा में दो किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए पावर प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को चार करोड़ 28 लाख रुपये का ठेका दिया गया था. कार्पोरेशन के ठेकेदार ने काम शुरू भी कर दिया था, लेकिन बीच में ही वह ठेका रद्द कर लैकफेड को दे दिया गया. तत्कालीन मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के कहने पर पूर्व आईएएस रामबोध मौर्य ने यह काम किया था. पावर प्रोजेक्ट कारपोरेशन के ठेकेदार को कुछ रुपये देकर उसे मुंह बंद रखने की चेतावनी दे दी गई थी. लैकफेड को ठेका दिए जाने में जो कमीशनबाजी हुई वह मायावती तक पहुंची ही नहीं. पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और पूर्व आईएएस रामबोध मौर्य के बीच ही रकम की बंदरबांट हो गई. इस पर मायावती के इशारे पर तत्कालीन मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने किसी के जरिए लखनऊ की हुसैनगंज कोतवाली में लैकफेड का मुकदमा दर्ज कराया था. हालांकि नसीमुद्दीन पर भी लैकफेड की कालिख के दाग थे, लेकिन आका का निर्देश था, उसे पालन करना ही था. मुकदमा दर्ज कराने के पीछे बाबू सिंह कुशवाहा पर दबाव बनने की मंशा थी, लेकिन सत्ता पलटते ही पत्ते भी पलट गए. पूरे प्रकरण की जांच में यह सामने आया कि लैकफेड में चार सौ से पांच सौ करोड़ के बीच का घोटाला हुआ. घोटाले की रकम के इतना अधिक होने का खुलासा तब हुआ था जब मामले की जांच कर रही पुलिस कोऑपरेटिव सेल की टीम ने आरोपी पूर्व महाप्रबंधक (प्रशासन) पंकज त्रिपाठी को रिमांड पर लेकर लैकफेड कार्यालय में छापामारी की थी. छापामारी में करोड़ों के भुगतान के दस्तावेज गायब पाए गए थे. पूछताछ में सामने आ चुका है लैकफेड को कई विभागों से करोड़ों का काम मिला था और लगभग सभी में जमकर धांधली हुई थी.

उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने लैकफेड घोटाला मामले के सात दोषियों को सजा सुनाई, कोर्ट ने लैकफेड के प्रबंध निदेशक रहे ब्रह्मप्रकाश को 10 साल की कैद की सजा दी, साथ ही उन पर 1.30 करोड़ रुपये का जुर्माना भी ठोका, इसके अलावा अदालत ने लैकफेड के महाप्रबंधक रहे पंकज त्रिपाठी को 10 साल की कैद और 90 लाख का जुर्माना, चीफ इंजीनियर गोविंद शरण श्रीवास्तव को 10 साल की कैद और 90 लाख का जुर्माना, इंजीनियर दिनेश साहू को सात साल की कैद और 50 लाख का जुर्माना, इंजीनियर अजय कुमार को सात साल की कैद और 25 लाख का जुर्माना, इंजीनियर संजय कुमार को पांच साल की सजा व पांच लाख का जुर्माना और लेखाकार अनिल कुमार अग्रवाल को तीन साल की कैद और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई, लैकफेड घोटाले का मुख्य आरोपी तत्कालीन चेयरमैन सुशील कटियार अबतक गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसे भगोड़ा घोषित कर उसकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे कई ऐसे भी पूर्व मंत्री हैं, जिन पर लैकफेड घोटाले में शामिल होने का आरोप तो लगा लेकिन उन्हें छुआ तक नहीं गया. आरोप है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तीन एग्रीकल्चर फर्टीलाइजर टेस्ट लेबोरेट्रीज के निर्माण, 15 पोस्ट मॉर्टम हाउसों के निर्माण और दो प्लालस्टिक सर्जरी सेंटर्स के लिए 12 करोड़ रुपये लैकफेड को जारी किए थे. इसी तरह मायावती सरकार में मंत्री रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर आरोप है कि उन्होंने 10 होम्योपैथी अस्पताल और एक हॉस्टल के